HP/129/SML/2019-2021 Title Code : HPBIL00313 RNI Reference No. 1328500 01-15 जनवरी, 2020

द रीव टाइम्स
The RIEV Times

हिमाचल, वर्ष 2, अंक 36/ पृष्ठ: 16 मूल्य: ₹ 25/-

www.therievtimes.com

शरीर,मन व आत्मा के उत्थान के लिए वर्ष 2020 सभी के लिए मंगलमय हो : डॉ॰ एल.सी. शर्मा

THE ONLY INITIATIVE THAT COVERS ALL 17 SDG's GOALS

अनुसूचित जनजाति बाहुल .....

गुजरात की लुवारा पंचायत को गोद लेगा आईआईआरडी

संस्था ने किया पंचायत का मुआयना, पेट्रोनेट एलएनजी व अन्य के सहयोग से बनेगी मॉडल पंचायत

द रीव टाइम्स : हेम राज चौहान

सामाजिक क्षेत्र में बेहतरीन सेवाऐं दे रही संस्था आईआईआरडी अब गुजरात के बरुच ज़िला की वाग्रा तहसील की लुवारा पंचायत को मॉडल पंचायत बनाने के लिए गोद लेने जा रही है। यह पंचायत गुजरात के दूरदराज़ की पंचायत है तथा इसमें 65 प्रतिशत से अधिक आबादी अनूसुचित जन-जाति से संबन्धित है।

इस पंचायत को गोद लेकर वहां संस्था पेट्रोनेट एलएनजी के सहयोग से आवश्यक विकास कार्यों को करने में पंचायत को सहयोग करेगी। आधारभूत संरचना के अलावा स्वच्छता, सीवरेज, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य, कृषि, एंव सबसे महत्वपूर्ण स्वरोजगार के अवसर पैदा कर लोगों को लाभ मिलेगा। इस बाबत हाल ही में संबन्धित पंचायत में आयोजित की गई बैठक में आईआईआरडी के प्रबंध निदेशक डॉ० एल सी शर्मा, वरिष्ठ सहयोगी दीपक पाण्डेया,पेट्रोनेट एलएनजी के सीएसआर अधिकारी सुमित ने पंचायत सरपंच एवं अन्य पंचायत पदाधिकारियों के साथ बैठक कर वहां की परिस्थितियों का जायज़ा लिया तथा बैठक में आवश्यकता आकलन कर कार्ययोजना निर्माण का क्या ख़ाका तैयार किया जाना है, इस पर मंथन किया। उन्होंने बताया कि आईआईआरडी ट्राईबल आबादी को विशेषकर विभिन्न माध्यमों एवं कार्यक्रमों / योजनाओं के द्वारा लाभान्वित कर स्थायित्व प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक बैठक कर इसके लिए वांछित रुपरेखा तैयार की जाऐगी तथा अतिशीघ्र पेट्रोनेट एलएनजी एवं अन्य औद्योगिक इकाईयों के सहयोग से इस योजना को अमलीजामा पहनाने का कार्य पूरा किया जाऐगा। आधारभूत विकास कार्यों को संस्था लोगों के साथ मिलकर पंचायत को मॉडल पंचायत बनाने के लक्ष्य की ओर अग्रसर होगी। लुवारा पंचायत के सरपंच रायसंग राठौर ने द रीव टाइम्स से बातचीत में बताया कि हमारी पंचायत में 65 प्रतिशत से अधिक आबादी अनुसूचित आबादी से संबन्धित है।

ऐसे में यहां पर विकास के लिए हम निरंतर प्रयासरत भी हैं।

लेकिन हमारी पंचायत में रोजगार एक बड़ा मुद्दा है और यहां ऐसे अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है कि जिससे लोग स्वरोजगार से जुड़ सके। नालियों का निमार्ण और स्वच्छता हमारी प्राथमिकता है। लेकिन सोलर लाईट, संपर्क सड़कें, स्वरोजगार, महिलाओं एवं युवाओं को प्रशिक्षण आदि की यहां बहुत आवश्यकता है।

इसके लिए आईआईआरडी के साथ हमारा क़रार हो रहा है जो कि हमारी पंचायत को गोद ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रबंध निदेशक के साथ हुई बैठक में आधारभूत संरचना का खाका तैयार करने के लिए बातचीत की गई। संस्था को पंचायत का पूर्ण सहयोग मिलेगा ताकि हमारी पंचायत एक मॉडल पंचायत बन सके।

आईआईआरडी अतिशीघ्र ही इस पंचायत में एमओयू हस्ताक्षर कर सेवाओं को प्रदान करेगी ।

निष्ठा और व्यवसायिकता में सामजस्य से ही लक्ष्य को साधा जा सकता है - प्रो0 आर के गुप्ता

आईआईआरडी ने मंथन और धूम धड़ाके से 2019 को कहा अलविदा

उपलब्धियों से लबरेज़ रहा 2019, 2020 के लिए लक्ष्य निर्धारित

द रीव टाइम्स

किसी भी संस्था से संबन्धित सेवाकर्मियों की निष्ठा और व्यवसायिकता में सामजस्य बिठाकर वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति का संभव बनाया जा सकता है। आईआईआरडी ने इसे साबित करते हुए प्रदेश से बाहर देश भर में वर्ष 2019 में लगभग हर क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़े हैं।

ये उद्गार आईआईआरडी के चेयरमैन प्रो० आर के गुप्ता ने मुख्य कार्यालय में आयोजित मंथन और सांस्कृति कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि शिरकत करते हुए कही।

उन्होंने कहा कि संस्था हमेशा अच्छे लोगों से ही निरंतर उन्नति करती है। संस्था ने 2019 में अच्छे अनुभवों से आगे बढ़ने की प्रेरणा ली तथा तिक्त अनुभव कुछ न कुछ सीख देकर 2020 के लिए मार्ग प्रशस्त कर गए हैं। उन्होंने समस्त आईआईआरडीयनस् को नव वर्ष की शुभकामनाऐं दी तथा संस्था की ओर से मिलकर आगे बढ़ने के संकल्प को भी दोहराया। इससे पूर्व संस्था के कार्यालय विस्तार को रिब्बन काट कर उद्घाटन किया।

इस अवसर पर उनके साथ प्रबंध निदेशक डॉ० एल सी शर्मा और निदेशक सुशमा शर्मा भी उपस्थित रहीं। इस अवसर पर प्रबंध निदेशक डॉ० एल सी शर्मा ने सभी सेवाकर्मियों को 2019 के सहयोग के लिए आभार जताते हुए 2020 की शुभकामनाऐं दीं।

उन्होंने कहा कि 2019 में आईआईआरडी ने सामाजिक एवं अन्य समस्त क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करते हुए रोजगार के लिए रास्ते खोले हैं। उन्होंने बताया कि संस्था ने लगभग हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया और लगातार पुरस्कार प्राप्त किए। देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी महत्पवपूर्ण उपस्थिति दर्ज़ की है। जिनेवा में संस्था के माध्यम से अनूठे प्रयास मिशन रीव की धमक दुनिया ने देखी और सुनी। महिलाओं को कार्यस्थल पर बेहतरीन सेवाऐं देने वाली कंपनी के रुप में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया।

कार्यक्रम में समस्त सेवाकर्मियों ने खूब मस्ती की तथा इस अवसर पर समस्त सेवाकर्मियों ने रैंपवॉक भी किया। सामुहिक नृत्य के साथ 2019 को अलविदा कहा तथा 2020 के लिए सामाजिक सेवा की संकलबद्धता की शपथ के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

नगर निगम शिमला उतरा मनमानी पर

वरिष्ठ नागरिकों की गुहार को अनसुना कर बिना ग्रेड के रास्ते की बना दी सड़क

बुजुर्ग नहीं चल पा रहे रास्ते में, नगर निगम को परवाह नहीं

द रीव टाइम्सः हेम राज चौहान

नगर निगम शिमला के इंजनघर वार्ड के अंतर्गत नगर निगम शिमला ने खड़ी चढ़ाई में सारी सीढ़ीयों को तोड़कर सड़क बनाई जा रही है। इंजनघर से नीचे की ओर सीधी चढ़ाई पर वहां के बुजुर्गों और वरिष्ठ नागरिकों की मनाही के बावजूद आम लोगों के चलने के लिए बनी सीढ़ीयों को तोड़ कर सड़क बनाई जा रही है।

उसे ऐंबुलेंस रोड़ का नाम देकर प्रशासन मनमानी कर रहा है। यह सड़क वाहन चलने के लायक नहीं है। फिर भी कुछ लोगों की चाहत के आगे नगर निगम ने वरिष्ठ नागरिकों को ठेंगा बताते हुए सीढ़ीयों को तोड़ दिया। अभी तक बनी सड़क में कहीं भी नालियों की व्यवस्था नहीं की गई है और बर्फ या कोहरे जमने के बाद ख़तरनाक हो सकती है

स्थानीय निवासी एवं वरिष्ठ नागरिक वयोवृद्ध प्रो० आर के गुप्ता ने बताया कि उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर नगर निगम शिमला के कमीशनर और पूर्व महापौर को ज्ञापन सौंपा था और गुहार लगाई थी कि यह एक आम रास्ता है और बिलकुल खड़ी चढ़ाई पर है।

इसकी सीढ़ीयों को तोड़कर यहां सड़क बन ही नहीं सकती है। इसके लिए मौका पर संबन्धित अधिकारियों, तकनीकी स्टाफ को भी बुलाया गया था जिन्होंने कहा था कि इस रास्ते को सड़क में नहीं तबदील किया जा सकता है क्योंकि इसका ग्रेड ही नहीं बनता है। यही बात कमीशनर पंकज रॉय के कार्यालय में उनके सामने भी कई बार हो चुकी है तथा अधिकारियों ने वहां भी स्वीकार किया था कि यह रास्ता किसी भी सूरत में सड़क में नहीं बदला जा सकता है। लेकिन यह सब कुछ झूठ था और एक सोची-समझी चाल के तहत निगम ने मनमाने तरीके से सीढ़ीयों को तोड़ दिया तथा ज़बरदस्ती सड़क बनाने पर उतारु है।

उन्होंने द रीव टाइम्स को बताया कि हैरानी है कि समाज के वरिष्ठ नागरिकों, समाजसेवियों की बात को निगम ने गंभीरता से नहीं सुना और उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता यदि किसी के साथ भी कोई भी अनहोनी वहां घटित हो जाए। उन्होंने कहा कि सरकार और नगर निगम से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं थी।

वहां निजी घरों की सुरक्षा को भी ख़तरा हो गया है। मनमानी के तहत किए जा रहे निर्माण कार्य से घर में बारिश का पानी आने का ख़तरा भी बन गया है। साथ ही पैदल चलना तो दूभर हो ही गया है। प्रो० आर के गुप्ता 86 वर्षीय, ने हज़ारों युवाओं को शिक्षित कर राष्ट्रनिर्माण में योगदान दिया तथा हि० प्र० के पूर्व मुख्य सचिव भी इनके शिष्य रह चुके हैं ।

द रीव टाइम्स ने मौका पर जाकर पड़ताल की तो पाया कि सीढ़ीयों को तोड़ कर वहां सड़क का निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान ढ़ांचे में सीधी चढ़ाई पर बुजुर्गों एवं बच्चों का चलना दूभर हो रहा है। इतना ही नहीं वहां महिला के पैर में इस कारण चोट भी आ चुकी हैं। द रीव टाइम्स ने कमीशनर से इससे पूर्व बात भी की थी लेकिन वहां अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि वहां सड़क नहीं बन

रही है। जबकि वहां सड़क का ही निर्माण कर दिया गया। यदि वहां वाहनों की अवाजाही होती है तो किसी भी प्रकार की दुर्घटना भविष्य में घटित होने का पूरा अंदेशा बना हुआ है। यहां दीगर बात ये है कि महापौर और कमीशनर के कहने के बाद भी यदि निर्माण कार्य हो रहा है और सड़क को बनाया जा रहा है तो क्या अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं?

क्या किसी के दबाव या कुछ लोगों की चाहत को सर्वोपरी रखते हुए निगम वरिष्ठ नागरिकों की बात भी नहीं सुन रहा है? क्या भविष्य में वहां वाहन चलने के बाद बिना ग्रेड की सड़क पर कोई भी दुर्घटना होती है तो नगर निगम इसकी जिम्मेवारी लेगा। नगर निगम शिमला को आम लोगों की चिंता करते हुए स्थानीय लोगों को विश्वास में लेते हुए सही निर्णय लेने चाहिए।

वहां सीढीयों का तुरंत निर्माण करके चलने योग्य मार्ग बनाने की आवश्यकता है जिस पर वरिष्ठ नागरिकों के साथ-साथ आम लोग सुविधाजनक तरीके से चल सके ।

2019 में चर्चित घटनाएं

बीता साल 2019 कई मायनों में यादगार रहा। इस साल देश-विदेश में हुई घटनाओं ने इसे खास बनाया। एक साल के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो लंबे समय तक जेहन में कैद रहेंगी। इनमें से कई घटनाएं ऐसी रहीं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालने वाली साबित हुई हैं। कुछ घटनाओं और फैसले भारत के भविष्य पर असर छोड़ेंगे। वहीं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ ऐसे फैसले आए जो भविष्य के लिए नजीर बन गए। अंतरराष्ट्रीय पटल पर भी ऐसी घटनाएं सामने आई जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। हम आपको बता रहे हैं 2019 की ऐसी ही 20 बड़ी घटनाएं जिन्हें भुला पाना कभी संभव नहीं होगा। आइए जानते हैं ऐसी ही 20 बड़ी घटनाओं के बारे में।

नरेंद्र मोदी का जादू

2019 में नरेंद्र मोदी का जादू फिर मतदाताओं के सिर चढ़कर बोला। आम चुनाव में भाजपा ने प्रचंड बहुमत हासिल कर सियासी पंडितों को भी चौंका दिया। भाजपा को इस साल 303 सीटों पर जीत मिली जबकि 2018 में उसने 282 सीटें जीती थीं। इसी के साथ नरेंद्र मोदी जवाहर लाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद तीसरे व पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। पीएम मोदी ने एक बार फिर वाराणसी से चुनाव लड़ा और चार लाख 79 हजार वोटों से जीते। इस दौरान उनकी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अुच्छेद 370 हटाने जैसा ऐतिहासिक फैसला लिया।

राहुल गांधी का इस्तीफा

साल 2019 में कांग्रेस में उस वक्त भूचाल आया जब राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का एलान कर दिया। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद जुलाई में राहुल ने पद से इस्तीफा दे दिया। राहुल गांधी ने चार पन्नों का इस्तीफा लिखकर इसे ट्विटर पर शेयर भी किया था। कांग्रेस अध्यक्ष पद के इस्तीफा देने वाले राहुल गांधी ने कहा था- मैं एक कांग्रेसजन के तौर पर पैदा हुआ, यह पार्टी हमेशा मेरे साथ रही है और यह मेरी रगो में है और हमेशा रहेगी।

बैंकों का विलय

30 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कई बैंकों के आपस में विलय का एलान किया। इसी साल वित्तीय वर्ष में देना और विजया बैंक के विलय का एलान किया गया था। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों के विलय का एलान करते हुए कहा था कि यूनाइटेड बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और पंजाब नेशनल बैंक का विलय होगा।

दूसरी ओर केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक का आपस में विलय होगा। तीसरा बड़ा विलय यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का जबकि इलाहाबाद बैंक के साथ इंडियन बैंक का विलय होगा। इस फैसले के बाद इन 10 बैंकों की जगह केवल चार राष्ट्रीयकृत बैंक होंगे, जबकि पहले से मौजूद आठ अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों को मिलाकर देश में सरकारी बैंकों की संख्या केवल 12 रह जाएगी।

जेट एयरवेज हुई ठप

17 अप्रैल 2019 की तारीख देश के विमानन इतिहास में याद रखी जाएगी क्योंकि इसी दिन जेट एयरवेज के विमान ने अपनी आखिरी उड़ान भरी थी। इसके बाद अनिश्चितकाल के लिए इस कंपनी की सेवाएं बंद हो गई हैं। 17 अप्रैल को रात 10.30 बजे अमृतसर के हवाई अड्डे से मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए जेट एयरवेज के विमान ने अंतिम उड़ान भरी थी।

जेट एयरवेज के धड़ाम होने से यात्रियों सहित कंपनी के कर्मचारियों कतो भी कई दिक्कतें आई। कंपनी लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रही थी। जेट एयरवेज के बंद होने से करीब 22 हजार लोगों की नौकरियां प्रभावित हुई। स्किल्ड से लेकर सेमी-स्किल्ड तक, जेट के तमाम कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा।

महाराष्ट्र का सियासी रण

महाराष्ट्र का सियासी रण भी इस साल चर्चा में रहा। ऐतिहासिक रूप से यहां के सियासी घटनाक्रम को लंबे समय तक याद रखा जाएगा। यहां भाजपा शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा और स्पष्ट बहुमत हासिल किया। लेकिन शिवसेना ने सीएम पद को लेकर 50-50 का फॉर्मूला रखकर नया विवाद छेड़ दिया। उद्धव ठाकरे ढाई साल के लिए सीएम पद को लेकर अड़ गए।

नतीजतन भाजपा को शिवसेना से अलग होना पड़ा। सियासी नाटक ने ऐसा करवट ली कि भाजपा ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे अजित पवार के साथ मिलकर रातोंरात सरकार बना ली। इसे लेकर जबरदस्त सियासी हंगामा मचा, बयानों की बाढ़ आई और आरोप-प्रत्यारोपों की झड़ी लग गई। लेकिन ये सरकार महज साढ़े तीन दिन ही टिक सकी। आख़िर शिवसेना ने अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार का गठन किया। जिसमें बाद में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद परिवारवाद का आरोप भी लगा।

आंध्र में सत्तापलट

इस साल आंध्र प्रदेश में भी बड़ी सियासी उठापटक हुई। यहां एक साथ हुए लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जगनमोहन रेड्डी का नाम चर्चा में आया। 46 साल के वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के मुखिया जगनमोहन रेड्डी ने राज्य से चंद्रबाबू नायडू की सरकार को उखाड़ फेंका। आंध्र प्रदेश में हुए चुनाव में उनका जादू इस कदर लोगों के सिर चढ़कर बोला कि वाईएसआर ने लोकसभा की 25 में से 22 सीटों पर कब्जा जमाया।

वहीं विधानसभा चुनाव में भी तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) को करारी शिकस्त देते हुए 175 में से 151 सीटों पर जीत हासिल की। विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के बाद जगनमोहन रेड्डी राज्य के नए सीएम बने।

राम मंदिर पर फैसला

मोदी सरकार के कार्यकाल में अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने विवादित जमीन पर रामलला के हक में निर्णय सुनाया। शीर्ष अदालत ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को राम मंदिर बनाने के लिए तीन महीने में ट्रस्ट बनाने के निर्देश दिए। अदालत ने कहा कि 2.77 एकड़ जमीन केंद्र सरकार के अधीन ही रहेगी।

साथ ही मुस्लिम पक्ष को नई मस्जिद बनाने के लिए अलग से पांच एकड़ जमीन देने के भी निर्देश दिए। इस फैसले के साथ ही दशकों पुराना ये विवाद हमेशा के लिए सुलझ गया। फैसले को तकरीबन सभी पक्षों ने स्वीकारा। इस फैसले के खिलाफ कहीं भी किसी तरह के विरोध प्रदर्शन या हिंसा की खबर नहीं आई।

ये फैसला देश के लिए एक नजीर बना और आने वाले समय में भारत का भविष्य संवारने वाला फैसला साबित हुआ है। हालांकि इस फैसले के खिलाफ एआईएमपीएलबी, हिंदू महासभा सहित करीब 22 पक्ष पुनर्विचार याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे लेकिन अदालत ने इन्हें खारिज कर दिया।

अनुच्छेद 370 हटाया

5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का एलान किया। सरकार ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त करने संबंधी एक संकल्प और राज्य को दो केंद्र शासित क्षेत्रों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करने के प्रावधान वाला एक विधेयक पेश किया। गृह मंत्री अमित शाह ने साथ ही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 भी पेश किया।

इस दौरान विपक्षी सदस्यों ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त करने संबंधी एक संकल्प और राज्य को दो केंद्र शासित क्षेत्रों जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में विभाजित करने के प्रावधान वाले विधेयक का विरोध किया। इसे लेकर देशभर में सियासी संग्राम छिड़ा और विपक्ष ने सरकार को निशाने पर लिया। कश्मीर में पूर्व सीएम फारुक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती सहित कई नेताओं को नजरबंद भी किया गया। विदेशी मीडिया में भी इस मामले की गूंज सुनाई पड़ी।

तीन तलाक बिल बना कानून

इसी साल 30 जुलाई 2019 को केंद्र सरकार ने एक और ऐतिहासिक बिल को पास कराने में कामयाबी हासिल की। राज्यसभा में तीन तलाक बिल को मंजूरी मिलने के साथ ही इसके कानून में बदलने का रास्ता साफ हो गया। संसद के दोनों सदनों में तीन तलाक विधेयक पारित हो जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे मुस्लिम महिलाओं के हित में एक ऐतिहासिक कदम बताया।

पीएम मोदी ने कहा कि पूरे देश के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है। करोड़ों मुस्लिम माताओं-बहनों की जीत हुई है और उन्हें सम्मान से जीने का हक मिला है। सदियों से तीन तलाक की कुप्रथा से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को आज न्याय मिला है। इस ऐतिहासिक मौके पर मैं सभी सांसदों का आभार व्यक्त करता हूं। इस पर भी खूब सियासी संग्राम मचा लेकिन कानून अमल में आ ही गया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी इसपर हरी झंडी दे चुका था।

नागरिकता कानून लागू

नरेंद्र मोदी सरकार ने 11 दिसंबर 2019 को एक और इतिहास रचा। इस दिन नागरिकात संशोधन बिल को राज्यसभा से भी पारित करा लिया गया। अगले ही दिन राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह विधेयक (Citizenship Amendment Bill :CAB) कानून बनकर लागू हो गया। लेकिन इस बिल के कानून बनने के साथ ही देश में एक नया संग्राम छिड़ गया। सबसे पहले विरोध शुरू हुआ असम में, धीरे-धीरे विरोध की चिंगारी दूसरे राज्यों में फैल गई।

९. बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली सहित कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन हुए। हिंसा में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा हिंसा बंगाल, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश, बिहार में हुई। लाखों-करोड़ों की सार्वजनिक संपत्ति को फूंका गया, वाहनों को आग लगाई गई। दिल्ली में भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। छात्रों के प्रदर्शन के दौरान जामिया मिल्लिया में हिंसा हुई।

झारखंड में मुरझाया कमल

इस साल एक तरफ जहां भाजपा सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए वहीं उसे कई सियासी झटके भी लगे। महाराष्ट्र के बाद दूसरा बड़ा झटका उसे झारखंड में लगा। भाजपा यहां अपनी सत्ता बचाए नहीं रख सकी और झामुमो-कांग्रेस गठबंधन ने उसे बुरी तरह हराया। रघुवर दास खुद ही चुनाव हार बैठे। उन्हें भाजपा के बागी व कद्दावर नेता सरयू राय ने बड़े अंतर से हराया।

हैदराबाद दुष्कर्म कांड

ये एक ऐसा कांड रहा जिसने देश ही नहीं पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। दिल्ली के निर्भया कांड की पुनरावृत्ति हैदराबाद में दिखी। 26 नवंबर को चार लोगों ने तेलंगाना में साइबराबाद के शादनगर में एक युवा महिला पशु चिकित्सक (27) के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसे जिंदा ही जला दिया। जिस तरह निर्भया को मदद का भरोसा देकर बस में बैठा लिया गया था, उसी तरह मदद का झांसा यहां भी देकर इंसानियत को शर्मसार कर दिया गया। लेकिन, इस मामले में हैरान करने वाला मोड़ आया 6 दिसंबर को आया जब खबर आई कि चारों आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। इसे लेकर पुलिस पर सवाल भी उठे, जांच भी बैठाई गई, लेकिन कई लोगों ने पुलिस की कार्रवाई को सही भी ठहराया। अदालत ने इस पर जांच बैठाई और मारे गए आरोपियों का दोबारा पोस्टमार्टम भी कराया गया।

बगदादी हुआ ढेर

28 अक्तूबर 2019 को आईएस सरगना अबु बकर अल बगदादी को अमेरिका ने ढेर कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसके अगले दिन दावा किया कि आईएस सरगना अबु बकर अल बगदादी को ढेर करने के बाद उसके उत्तराधिकारी को भी ढेर कर दिया गया है। 29 अक्तूबर को ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कहा था कि पिछली रात अमेरिका दुनिया के नंबर एक आतंकी को इंसाफ के दायरे में लाया गया।

मुशर्रफ को फांसी की सजा

साल 2019 पाकिस्तान के लिए भी उथलपुथल भरा रहा। इमरान खान की अगुवाई में ये देश आर्थिक संकट से जूझता रहा। भारत के साथ उसके रिश्ते लगातार बिगड़ते रहे। इसी दौरान 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आर्मी चीफ व तानाशाह परवेज मुशर्रफ को मौत की सजा का एलान किया। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार किसी पूर्व राष्ट्रपति को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। इस्लामाबाद की विशेष अदालत ने पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफ को राजद्रोह के मामले में फांसी की सजा सुनाई है। उन्हें यह सजा नवंबर 2007 में संविधान से इतर आपातकाल लागू करने की वजह से सुनाई गई है। उन्होंने देश में आपातकाल लागू करने के बाद मार्शल लॉ लगा दिया था। पूर्व सेनाध्यक्ष इस समय दुबई में हैं। उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दिसंबर 2013 से लंबित था।

ट्रंप पर महाभियोग

इस साल की एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटना रही अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग। 19 दिसंबर को अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग को मंजूरी दे दी। अमेरिकी इतिहास में ट्रंप ऐसे तीसरे राष्ट्रपति हैं जिनके खिलाफ महाभियोग को मंजूरी दी गई।

डेमोक्रेट सांसदों के बहुमत वाले अमेरिकी संसद के निचले सदन ने 197 के मुकाबले 230 मतों से महाभियोग को मंजूरी दे दी। अब ये मामला संसद के ऊपरी सदन सीनेट में जाएगा, हालांकि यहां रिपब्लिकन सांसद बहुमत में हैं। ऐसे में इस बात की संभावना बहुत कम है कि राष्ट्रपति ट्रंप को उनके पद से हटाया जा सकेगा।

हांगकांग में प्रदर्शन

हांगकांग में लोकतंत्र की मांग को लेकर सालभर से चल रहे प्रदर्शन अब भी थमे नहीं हैं। 2019 में इस खबर ने अंतरराष्ट्रीय मीडिया में जगह बनाई। इन्हें कुचलने के लिए चीन ने अपनी सेना भी तैनात कर दी। पिछले 6 महीने से जारी प्रदर्शन के खिलाफ पहली बार पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के सैनिक सड़कों पर दिखे। विरोध प्रदर्शन की असली वजह थी चीनी प्रत्यर्पण बिल। इसे लेकर आंदोलन ने इस कदर जोर पकड़ा कि जनता सड़कों पर उतर आई।

4 सितंबर को चीन ने इस बिल को वापस ले लिया। इस कानून में प्रावधान था कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करके हांगकांग आ जाता है तो उसे जांच प्रक्रिया में शामिल होने के लिए चीन भेजा जा सकता है। हांगकांग की सरकार कानून में संशोधन के लिए फरवरी 2019 में प्रस्ताव लाई थी।

श्रीलंका धमाके

21 अप्रैल 2019 को श्रीलंका में हुई एक घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। ईस्टर की प्रार्थना के दौरान श्रीलंका छह सिलसिलेवार धमाकों और दो आत्मघाती हमलों से श्रीलंका दहल उठा। राजधानी कोलंबो के अलावा तटीय शहर नेगेंबो और बट्टिकलोआ में हुए कुल आठ धमाकों में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। मरने वाले वालों में महिलाएं, बच्चे और 11 विदेशी नागरिक भी शामिल थे।

2009 में लिट्टे के खात्मे के बाद श्रीलंका के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा हमला था। गेस्ट हाउस और होटल द सिनामोन ग्रांड में हुआ हमला आत्मघाती था। इन धमाकों के लिए नेशनल तौहीद जमात (एनटीजे) पर शक गहराया, जो इस्लामिक स्टेट (आईएस) का मॉड्यूल माना जाता है। आतंकी हमलों का मुख्य हमलावर जहरान हाशिम धमाकों में मारा गया था।

इंग्लैंड में बोरिस जॉनसन की जीत

इस साल ब्रिटेन में हुए आम चुनाव में सत्ताधारी कंजरवेटिव पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की। बोरिस जॉनसन की कंजरवेटिव पार्टी को 650 सीटों वाली संसद में 364 सीटें मिलीं। चुनाव में कश्मीर में 370 हटाने के फैसले का विरोध करने वाली लेबर पार्टी को महज 203 सीटें ही मिलीं। चुनाव परिणाम के साथ ही ब्रेग्जिट (यूरोपीय संघ से ब्रिटेन का अलगाव) का रास्ता साफ हो गया। इस चुनाव में एक दर्जन से अधिक भारतवंशी उम्मीदवारों ने भी जीत का परचम लहराया। 1980 के दशक में मारग्रेट थ्रैचर के दौर के बाद कंजरवेटिव पार्टी की यह सबसे बड़ी जीत रही। नतीजों का एलान होने के बाद प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने दो-टूक कहा हम यूरोपीय संघ (ईयू) से ब्रिटेन को अलग करने वाले ब्रेग्जिट को 31 जनवरी तक हर हाल में पारित कराएंगे।

2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल विवाद

2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल खूब विवादित रहा और जिस अंदाज में मेजबान इंग्लैंड को जीत मिली उस पर सवाल उठाए गए। क्रिकेट इतिहास में ये पहला मौका था जब वर्ल्ड कप में ओवर थ्रो के चलते किसी टीम को जीत मिली। न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल द्वारा फेंका गया थ्रो बल्लेबाज बेन स्टोक्स के बल्ले से लगकर बाउंड्री पार कर गया था और टीम को 6 रन मिल गए जिसने इंग्लैंड को पहली बार 50 ओवर क्रिकेट का ताज दिला दिया।

गांगुली बने बीसीसीआई अध्यक्ष

इस साल भारतीय क्रिकेट में भी अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिला। 23 अक्तूबर 2019 को टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली अधिकारिक तौर पर बीसीसीआई के 39वें अध्यक्ष चुन लिए गए। मुंबई में बोर्ड के हेडक्वार्टर में गांगुली को बोर्ड की कमान सौंपी गई। सौरव गांगुली को इस पद के लिए निर्विरोध चुना गया था। गांगुली का कार्याकाल 10 महीने का होगा। करीब 30 महीने के लंबे अंतराल के बाद बीसीसीआई को गांगुली के रूप में नया अध्यक्ष मिला। उनके अलावा बोर्ड के अन्य सदस्यों केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह (गुजरात) सचिव, उत्तराखंड के महिम वर्मा उपाध्यक्ष, बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के छोटे भाई अरुण धूमल (हिमाचल प्रदेश) कोषाध्यक्ष और जयेश जॉर्ज (केरल) संयुक्त सचिव नियुक्त किए गए।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

अनिल कुमार खाची बने हिमाचल के नए मुख्य सचिव

द रीव टाइम्स

हिमाचल सरकार ने 1986 बैच के आईएएस अधिकारी और वर्तमान में काडर के सबसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनिल कुमार खाची को मुख्य सचिव नियुक्त किया। इसके साथ ही सरकार ने आठ प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यभार में फेरबदल कर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे दो अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंप दी है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के तहत अतिरिक्त मुख्य सचिव वन राम सुभग सिंह को ऊर्जा और बिजली बोर्ड के चेयरमैन पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया है। उनके पास मौजूद भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग को प्रधान सचिव शिक्षा कमलेश कुमार पंत को दिया गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आरडी धीमान को पूर्व मुख्य सचिव डॉ. श्रीकांत बाल्दी के पास रहे पर्यटन विभाग का अतिरिक्त कार्यभार, सचिव वित्त अक्षय सूद को सचिव आवास, विशेष सचिव वित्त राजेश शर्मा को एग्जामिनर लोकल ऑडिट विभाग, निदेशक एचपी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चंद्र प्रकाशन वर्मा को निदेशक भू राजस्व और निदेशक आयुर्वेदा डीके रतन को शिमला मंडल के सेटलमेंट अफसर का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। खास यह है कि प्रबोध सक्सेना यूपीए सरकार के दौरान वित्त मंत्रालय में हुए एक कथित घोटाले में चल रही ईडी और सीबीआई जांच झेल रहे हैं। वर्तमान में वह इन मामलों में जमानत पर हैं और केंद्र ने उनके खिलाफ अभियोजन मंजूरी भी दे दी है, जिसके बाद

सीबीआई ने दिल्ली की स्थानीय अदालत में सक्सेना समेत कई अन्य के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर रखी है। वहीं, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे रजनीश को सचिव सूचना एवं जनसंपर्क के अलावा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त कार्यभार और जीके श्रीवास्तव को सचिव आयुर्वेद और प्रशिक्षण व विदेशी एसाइनमेंट लगाया गया है।

रेलिंग फांद वीआईपी गैलरी में घुसे लोग

द रीव टाइम्स ब्यूरो

राज्य सरकार के दो साल जश्न में रैली के आयोजन स्थल पर अव्यवस्था का आलम दिखा। रैली के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मगर रैली के आयोजन स्थल पर भाजपा के सदस्यों सहित समर्थकों को रेलिंग फांद कर वीआईपी ब्लॉक में घुसते हुए देखा गया, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि उक्त स्थल पर तैनात जवान यह नजारा खडे होकर देखते रहे।

हुआ यूं कि रिज मैदान पर होने वाली रैली में शामिल होने के लिए आईजीएमसी की तरफ से काफी संख्या में लोग एक साथ आए। जिन्हें सुरक्षा घेरे को तोडते हुए वहां लगी रेलिंग को फांद कर सीधे वीआईपी ब्लॉक में घुसते हुए देखा गया। इसमें महिलाएं भी शामिल रहीं। हालांकि रैली के आयोजन स्थल पर अव्यवस्था का आलम दिखा। मगर इसके अलावा शिमला के अन्य स्थलों पर लॉ एंड आर्डर चाकचौबंध देखने को मिला। पुलिस ने जहां सुरक्षा के मद्देनजर हर इतंजाम किए हुए थे। वहीं, पुलिस को रैली में प्रदेश के विभिन्न कोनों से आए लोगों का मार्गदर्शन करते हुए देखा गया।

स्पीति में पुराने सरकारी भवनों की जगह बनेगी नई बिल्डिंग

द रीव टाइम्स ब्यूरो स्पीति

जनजातीय उपयोजना और सीमा क्षेत्र विकास योजना के तहत परियोजना सलाहाकार समिति की बैठक कृषि जनजातीय एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डा. रामलाल मार्कंडेय अध्यक्षता में संपन्न हुई हुई। बैठक में जनजातीय उपयोजना के अंतगर्त 39.4 करोड़ व सीमा क्षेत्र विकास योजना 8.96 करोड़ और कुल कार्य योजना बजट 48 करोड़ की वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए प्रस्तावित कार्य योजना अनुमोदन प्रदान किया। बैठक में चालू वित्तीय वर्ष में चल रहे विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के कार्यों की प्रगति समीक्षा भी की गई। इस दौरान कृषि मंत्री ने इस बात का खुलासा भी किया कि स्पीति में विभागों के पुराने हो चुके भवनों को जल्द गिराया जाएगा और उनकी जगह नई बिल्डिंगों का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सरकार से भी चर्चा कर ली गई है और संबंधित विभाग इस पर काम शुरू करदें। बैठक में कृषि मंत्री ने लोक निर्माण विभाग द्वारा लियो वायपास सड़क के बनने देरी पर नाराजगी जताई। अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा इस सड़क के कार्य में तीव्रता लाई जाए। विभाग धीमी गति से कार्य कर रहा है, जोकि किसी भी सूरत में बर्दाशत नहीं किया जाएगा, वहीं मुद-भावा मार्ग के कार्य भी पिछले लंबे समय से धीमी गति से चला है इस कार्य को तुरंत तेजी लाने के भी आदेश दिए गए। बैठक में आईपीएच विभाग की लंबित योजनाओं के बारे समीक्षा करते हुए कृषि मंत्री डा. रामलाला मार्कंडेय ने कहा कि जिन सिंचाई योजनाओं से अधिक से अधिक जनता को लाभ होना है उन्हें प्राथमिकता के आधार पूरा किया जाए। ताकि ग्रामीणों की आय बढ़ सके। ग्रामीण विकास विभाग के आधीन पिछले कई सालों से लटकी योजनाओं एंव कार्यों को वर्ष 2020 में हर हाल में पूरा किया जाए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि स्पीति क्षेत्र में विकासात्मक कार्यों की समीक्षा की गई है।

स्मार्ट शहर की झलक दिखेगी 2020 में, 28 प्लान तैयार

द रीव टाइम्स ब्यूरो

2020 में नगर निगम के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनने वाली कई योजनाएं जमीन पर उतरती नजर आएंगी। इस साल शहर स्मार्ट दिखना शुरू होगा। शहर में तारों के जंजाल से लोगों को राहत मिलेगी। वहीं पानी और सीवरेज की पाइपें नालियों में ब्लॉकेज का कारण नहीं बनेंगी। शहर के मुख्य नाले के आसपास सौंदर्यकरण किया जाना है। नगर निगम प्रशासन ने स्मार्ट सिटी के लिए शहर के लिए 28 प्लान तैयार किए हैं। इसमें से 10 को इसी साल पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा है। इसके बाद मालरोड की सीवरेज, पानी की पाइपों के साथ हर तार इसी से गुजरेगी। राजधानी में निगम की 987 दुकानें हैं, इनको तोड़कर दोबारा से एकरूपता से प्रीफेबरिकेटिड तरीके से बनाया जाएगा।

बिजली खाद बनाने का काम भी होगा शुरु

निगम के कूड़ा संयंत्र से बिजली और खाद बनाने का काम शुरू होगा। लंबे समय से बिजली से कूड़ा और बिजली बनाने का प्लान है। इसके बावजूद शहर में इन दोनों प्रोजेक्टों पर काम शुरू नहीं हो सका है। इस साल दोनों ही प्रोजेक्टों पर काम शुरू करने की योजना है।

बनेंगे कवर्ड फुटपाथ

स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नए साल पर पैदल चलने वाले लोगों को कवर्ड फुटपाथ बनेंगे। संजौली से इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आइजीएमसी) तक यह फुटपाथ बनाया जाएगा। फुटपाथ पर छत लगाई

जाएगी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 11 करोड़ रुपये का प्रावधान इसके लिए किया गया है।

शहर में लगेंगे ई शौचालय

शहर में ई-शौचालयों का निर्माण होगा। बस स्टॉप, सार्वजनिक स्थलों में निगम द्वारा ई-शौचालय स्थापित किए जाएंगे। शहर भर में ई-शौचालयों के निर्माण के लिए एक करोड़ 20 लाख का प्रावधान किया गया है।

फिर शिक्षकों के दबाव में झुकी सरकार, नहीं लगेंगी एक्स्ट्रा क्लासें

द रीव टाइम्स ब्यूरो

अजीबोगरीब आदेशों को जारी करने और फिर उन्हें वापस कर अपनी किरकिरी कराने वाली सरकार एक बार फिर शिक्षकों के दबाव के आगे झुक गई है। सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि अब सरकारी स्कूलों में छुट्टियों के दौरान एक्स्ट्रा क्लासें नहीं लगेंगी। साथ ही इस दौरान शिक्षकों को भी नहीं बुलाया जाएगा। शिक्षा विभाग ने प्री बोर्ड परीक्षाओं के खराब परिणाम के बाद सर्दियों की छुट्टियों के दौरान 1 जनवरी से 12 फरवरी तक अतिरिक्त कक्षाएं लगाने के आदेश जारी किए थे। इस आदेश के जारी होने के बाद शिक्षक संगठनों ने सख्त चेतावनी देते हुए तत्काल इसे वापस लेने या खामियाजा भुगतने की बात कही थी। हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ ने तो एलान कर दिया था कि प्रदेश का कोई भी शिक्षक शीत अवकाश के दौरान एक्सट्रा क्लास नहीं पढ़ाएगा। उल्लेखनीय है कि शीतकालीन स्कूलों में विभाग ने एक फरमान जारी किया था जिसके तहत 1 जनवरी से 12 फरवरी तक स्कूलों में प्री बोर्ड के रिजल्ट के आधार पर कमजोर बच्चों को रिमेडियल क्लास लगाने के लिए कहा गया था। सरकार यूनियन के आगे झुककर अपनी ही किरकिरी कर रही है ।

केलांग में मेधावियों पर बरसे इनाम

द रीव टाइम्स ब्यूरो

राजकीय प्राथमिक केंद्र पाठशाला केलांग में वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लाहुल-स्पीति बीडीसी जिला अध्यक्ष समीता यारपा ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। इस दौरान स्कूल की मुख्यशिक्षिका छिमे अंगमों ने मुख्यातिथि को समृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। उन्होंने इस दौरान स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ मुख्यातिथि को वर्ष भर में की गई गतिविधियों व स्कूल की उपलब्धियों से भी अवगत करवाया। कार्यक्रम में छात्रों ने नेपाली नृत्य, लाहुल नृत्य, कुल्लूवी नृत्य पेश किया। छात्रों ने फिल्मी गानों पर भी नृत्य पेश कर सबका दिल जीत लिया। इस दौरान विभिन्न कक्षाओं में प्रथम स्थान हासिल करने वाले छात्रों को जहां सम्मानित किया गया, वहीं खेलकूद प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए मानकू, कृष्णा, सूर्यांश और अनुष्का राणा को मुख्यातिथि द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्यातिथि ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि छात्रों को पढ़ाई के साथ-साथ खेलकूद में भी बढ़-चढ़कर भाग लेना चाहिए।

हिमाचल प्रदेश विवि में भर्ती होंगे 325 शिक्षक

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में लंबे समय के बाद शिक्षकों की भारी संख्या में भर्ती होगी। इसमें 325 पद शिक्षकों के भरे जाने हैं। इसके लिए प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर, इक्डोल और सांध्य महाविद्यालय के लिए अलग से भर्तियों की अधिसूचना जारी की है। बुधवार से इन पदों को भरने के लिए प्रार्थी आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जनवरी तय की है। सामान्य वर्ग के प्रार्थियों को 2000 रुपये के शुल्क के साथ आवेदन करना होगा।

वहीं आरक्षित वर्ग के प्रार्थियों को 1000 रुपये फीस देनी होगी। इसमें पहली बार सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10 फीसद आरक्षण होगा। इसमें प्रोफेसर के 21, निदेशक के सात, विवि में एसोसिएट प्रोफेसर के 52, इक्डोल में 26, इवनिंग स्टडीज में दो, विवि

के रिजनल सेंटर धर्मशाला में एक पद भरा जाएगा। रिजनल सेंटर धर्मशाला में प्रधानाचार्य का एक पद भी भरा जाएगा। इसके अलावा विवि के तहत एचपीयू में असिस्टेंट प्रोफेसर के 55, इक्डोल में असिस्टेंट प्रोफेसर के 18, इवनिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के 18, रिजनल सेंटर धर्मशाला में असिस्टेंट प्रोफेसर के 31, कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज में 11, इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी में 50, लीगल स्टीज में आठ और फिजीकल एजुकेशन एंड यूथ प्रोग्राम में चार पद भरे जाने हैं। यूजीसी के नियमों के तहत यह भर्तियां करवाई जाएंगी।

ऐसे छूटेगा नशा.... सरकार के उपाय समझ से परे

नशा छुड़वाने को आधे दामों में बेचा दूध, हाथों हाथ बिका

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल सरकार ने युवाओं को नशा छोड़कर सेहत बनाने का अनोखा संदेश दिया । साल के आखिरी दिन को सरकारी उपक्रम मिल्कफेड ने शिमला के रिज मैदान, राज्य सचिवालय और मंडी के सेरी मंच पर हिम गौरी दूध आधे दामों पर दिया। एक दिन सस्ता दूध देकर सरकार ने युवाओं को 'नशा छोड़ो, दूध पीयो' के प्रति जागरूक किया।

हर स्टॉल पर 1500–1500 लीटर सस्ता दूध देने का लक्ष्य रखा था जो कुछ ही घंटों में हाथों हाथ बिक गया। मात्र पांच घंटों में ही सारा दूध खत्म हो गया।

मिल्कफेड के चेयरमैन निहाल चंद शर्मा ने

बताया कि दूध को फोर्टिफाइड बनाया गया है, जो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी है। इस दूध में विटामिन ए और विटामिन डी भरपूर मात्रा में है।

यहां सवाल ये है कि क्या इस प्रकार एक दिन में दूध बेचकर सरकार नशे के ख़िलाफ क्या संदेश देना चाहती है ?

यूनियनबाजी से उपर उठकर सरकार तुरंत उठाए ये क़दम शहरी क्षेत्रों, निदेशालय में डटे शिक्षकों को दूरदराज भेजने की तैयारी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

शिक्षकों के तबादला एक्ट को लेकर फिर से फाइल मूवमेंट शुरू हो गई है। राज्य सचिवालय में प्रधान सचिव शिक्षा के के पंत की अध्यक्षता में तबादला एक्ट के प्रारूप को लेकर समीक्षा बैठक हुई। इसमें शिक्षकों के सेवाकाल (सर्विस रिकॉर्ड) पर चर्चा की गई। प्रधान सचिव ने शिक्षा निदेशक को निर्देश दिए कि ऐसे शिक्षक जो शिक्षा निदेशालय, शिक्षा उप निदेशालय में प्रतिनियुक्ति पर हैं या अन्य राज्यों और दूसरे विभागों में सेवाएं दे रहे हैं उनके सेवाकाल के रिकहर्ड भी तैयार किया जाए। सूत्रों के अनुसार शहरों के आसपास के स्कूलों और प्रतिनियुक्ति पर शिक्षा निदेशालय में सालों से डटे शिक्षकों को दूरदराज के क्षेत्रों में भेजा जा सकता है । महिला शिक्षकों को तबादले में कुछ छूट दी जा सकती है ।

नगर निगम की मनमानी हमेशा से ही जनता पर पड़ती है भारी

पेयजल सस्ता न होने पर भड़के पार्षद, पूर्व मेयर ने भी खोला मोर्चा

द रीव टाइम्स ब्यूरो

शहरवासियों को सस्ता पानी देने के लिए बुलाई गई पेयजल कंपनी की निदेशक मंडल की बैठक से मेयर-डिप्टी मेयर के गायब रहने के मामले पर सदन में खूब हंगामा बरपा। नई मेयर सत्या कौंडल की अध्यक्षता में यह पहला सदन था। पहले ही सदन में पार्षदों ने उन्हें निशाने पर ले लिया। इस पर मेयर सत्या कौंडल ने कहा कि 15 दिन के भीतर बीओडी की बैठक करेंगे। इस पर पूर्व मेयर कुसुम सदरेट भड़क गईं। कहा कि ढाई साल मामला लटका नहीं बल्कि सिरे चढ़ाया। पार्षद संजीव ठाकुर, आनंद कौशल, सिमी नंदा, शारदा चौहान, विवेक शर्मा, किरण बावा ने कहा कि सस्ते पेयजल के लिए पार्षदों

ने पोर्ट ब्लेयर दौरा तक रद्द कर दिया था लेकिन मेयर-डिप्टी मेयर ने बैठक में न जाकर जनता से धोखा किया। द रीव टाइम्स ने लोगों से बात की तो लोग भी इस बात से नाराज़ ही हैं कि नगर निगम अपनी मनमर्जी से सीवरेज, पानी, कूड़े आदि के बिलों में बढ़ौतरी कर लोगों पर बोझ बढ़ा रहा है ।

अस्पताल में फिर भी ठिठुरन कायम

द रीव टाइम्स ब्यूरो

शिमला के अस्पतालों में सेंट्रल हीटिंग सिस्टम शुरू करने के बावजूद राज़धानी के अस्पतालों के कुछ भागों में ठिठुरन है। इसे लेकर शिमला के अस्पतालों में आए मरीज़ों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि सेंट्रल हीटिंग सिस्टम के जो प्वाइंट खराब हैं उन्हें जल्द दुरूस्त किया जाए। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में लगभग छह से सात प्वाइंट ऐसे हैं जो खराब हैं।

हालांकि आईजीएमसी के वार्ड में मरीज़ों को ठंड से ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है लेकिन वार्ड के बाहर मरीज़ और उनके तीमारदारों को ज्यादा दिक्कत झेलनी पड़ रही है, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

नगर परिषद घर-घर जाकर करेगी हाउस टैक्स की वसूली

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सोलन

नगर परिषद सोलन ने बकाया ढाई करोड़ रुपये के टैक्स की वसूली को लेकर घर-घर से उगाही का फैसला किया है। नगर परिषद अब अपने कर्मचारियों को वसूली के लिए भेजेगी। जो लोग अदायगी नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद पैसा न देने की सूरत में संबंधित व्यक्ति को नोटिस भेजा जाएगा। नगर परिषद ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए कड़ी कार्रवाई की योजना तैयार कर ली है। नगर परिषद सोलन में करीब ढाई करोड़ हाउस टैक्स पिछले एक साल से लोगों पर बकाया है। हालांकि, नगर परिषद ने हाउस टैक्स न चुकाने वाले लोगों की अंतिम सूची पहले ही तैयार कर ली है। शहर में नगर परिषद से हर महीने पांच प्रतिशत के हिसाब से हाउस टैक्स वसूला जाता है। कई लोग लंबे समय से भुगतान नहीं कर रहे हैं। नगर परिषद के नियमों को ठेंगा दिखाते हुए पैसों को सही समय पर नहीं चुका रहे हैं।

इससे नगर परिषद के विकास कार्यों पर रोक लग रही है। नगर परिषद घाटे की स्थिति से गुजरने लगी है। वहीं, दुकानों का एक करोड़ पर भी लोग कब्जा किए बैठे हैं। उधर, नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी ललित कुमार ने बताया कि लाखों की राशि को वसूलने के लिए कर्मचारियों को डोर टू डोर भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि पैसा न देने पर डिफाल्टरों का नोटिस भेजे जाएंगे। उन्होंने बताया कि जल्द ही कार्रवाई को शुरू की जाएगी।

200 रुपये की खरीद पर नही दिया बिल तो लगेगा 25 हजार रुपये जुर्माना

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सोलन

सोलन में अब सामान के बदले में ग्राहकों को बिल न देने वाले जीएसटी पंजीकृत कारोबारियों की खैर नहीं। यही नहीं नियमों की अवहेलना करने पर कारोबारी को 25 हजार रुपये जुर्माना भुगतना पड़ेगा। इसके लिए विभाग ने कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया है। इसके तहत किसी भी पंजीकृत कारोबारी को बक्शा नहीं जाएगा। वहीं, विभाग के बार-बार कहने पर भी कोई बिल नहीं दिया जाता है तो जुर्माना लगाने के बाद नियमानुसार विभाग और अधिक सख्ती से पेश आएगा। गौर रहे कि जिला भर में 8 हजार 179 जीएसटी पंजीकृत कारोबारी हैं। इनमें से सोलन शहर में एक हजार के करीब कारोबारियों में से कुछ कारोबारी अभी भी लोगों को 200 रुपये से ऊपर का सामान खरीदने पर बिल नहीं दे रहे हैं। इससे जहां सरेआम लोगों से लूट हो रही है, वही लोगों को सामान की असली कीमत का भी पता नहीं लग पा रहा है। इससे साफ प्रतीत हो रहा है कि कारोबारी टेक्स तो काट रहा है, लेकिन उसे सरकारी कोष में जमा नहीं करवा रहा है। इससे पूर्व विभाग की टीम ने कड़ी कार्रवाई करते हुए सोलन और धर्मपुर में पंजीकृत कारोबारियों को बिल न चुकाने पर 5 केस बनाए थे। अभी तक कारोबारी विभाग की आंखों में धूल झोंककर लोगों को चूना लगाने में लगे हैं। अब विभाग ने ऐसे कारोबारियों के प्रति कड़ा संज्ञान लिया है। इसमें पंजीकृत कारोबारियों को बक्शा नही जाएगा, जबकि विभाग की ओर से नियमों की पालना करने का आह्वान समय-समय पर किया जा रहा है।

दो साल में 14,667 को दी सामाजिक सुरक्षा पेंशन

द रीव टाइम्स ब्यूरो,ऊना

बचत भवन में मीडिया से संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर जिला कल्याण अधिकारी सुरेश शर्मा भी उपस्थित रहे। एडीसी ने कहा कि 1 जनवरी 2018 से दिसंबर 2019 तक जिला के 14,667 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी गई। जो पूरे राज्य में सर्वाधिक है। उन्होंने बताया कि 11621 बुजुर्गों, 1759 विधवाओं व 1287 दिव्यांगों को पेंशन का लाभ दिया गया है। फिलहाल विभाग के पास 3875 व्यक्तियों की पेंशन के मामले लंबित हैं। इन सभी के आवेदन सॉफ्टवेयर से अपलोड कर दिए गए हैं और बजट का प्रावधान होते ही आवेदकों को पेंशन मिलना प्रारंभ हो जाएगी। जिला कल्याण अधिकारी सुरेश शर्मा ने बताया कि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान जिला के कुल 36,420 व्यक्तियों को पेंशन देने पर दिसंबर तक 39.17 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। 99 परिवारों को मकान बनाने को दी आर्थिक सहायता जिला कल्याण अधिकारी सुरेश शर्मा ने कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 में जिला के अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित 99 परिवारों को गृह निर्माण के लिए 1.30 करोड़ की आर्थिक सहायता दी गई है। गृह निर्माण अनुदान योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार की ओर से प्रति परिवार 1.30 लाख की आर्थिक मदद दी जाती है। उन्होंने कहा कि गृह निर्माण के लिए 624 मामले अभी लंबित हैं और इसके लिए प्रदेश सरकार से बजट की मांग की गई है। इस अवसर पर तहसील कल्याण अधिकारी कुलदीप दयाल भी उपस्थित रहे।

सभी कार्यालयों में लगाना होगा तंबाकू मुक्त स्थल का पट्ट

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सोलन

जिला सोलन के सभी कार्यालयों में तंबाकू मुक्त स्थल पट्ट लगाने निर्देश अधिकारियों को जारी किए गए। इसमें 15 जनवरी तक यह कार्य जिला के सभी कार्यालयों में पूरा करना होगा।

यदि इसमें उक्त निर्देश की पालना नहीं की गई तो जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई भी की जा सकती है। इसका निर्णय सोलन में उपायुक्त केसी चमन की अध्यक्षता में आयोजित तंबाकू नियंत्रण अधिनियम के तहत आयोजित बैठक में लिया गया है। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध सुनिश्चित किया जाए। दुकानों में तंबाकू उत्पादों को प्रदर्शित करना इस अधिनियम के तहत निषेध है और 18 वर्ष से कम आयु के युवाओं को तंबाकू उत्पादों का विक्रय करने पर दुकानदार को जुर्माने का प्रावधान है।

उन्होंने कहा कि कोटपा अधिनियम के तहत शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में किसी भी तरह के तंबाकू उत्पाद बेचना अपराध है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करने पर भी जुर्माने का प्रावधान है।सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद से संबंधित विज्ञापन भी निषेध हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अधिनियम का उचित कार्यान्वय सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए। वर्तमान में जिला सोलन में तंबाकू की अवैध बिक्री सहित सेवन करने पर चालान भी काटे गए हैं।

इसमें सोलन पुलिस की ओर से 1 हजार 250 चालान काट कर एक लाख 80 हजार 650 का जुर्माना भी वसूल किया गया है।

मिनी जू रेणुका में दहाड़ेगा बंगाल टाइगर, प्लान को मिली मंजूरी

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सिरमौर

मिनी जू रेणुका जी जल्द ही बंगाल टाइगर की दहाड़ से गूंजेगा। केंद्रीय जू प्राधिकरण (सीजेडए) ने वन्य प्राणी विभाग की ओर से तैयार किए ले आउट प्लान को स्वीकृति दे दी है। प्लान को हरी झंडी मिलते ही वन्य प्राणी विभाग अब बंगाल टाइगर के लिए नए और आधुनिक बाड़े का निर्माण करेगा। जिसका प्राक्कलन भी विभाग ने तैयार कर लिया है। गुजरात के जूनागढ़ से शेरों का जोड़ा लाया जाएगा। चार साल से यहां शेरों के पिंजरे खाली पड़े हुए हैं। विभाग लंबे समय से यहां शेरों का जोड़ा लाने की कोशिश में था। लेकिन, सीजेडए के कड़े नियम आड़े आ रहे थे। नियमों को ध्यान में रखते हुए वन्य प्राणी विभाग ने जू का विस्तृत ले आउट प्लान तैयार करवाकर सीजेडए को भेजा था। जिस पर सीजेडए ने अपनी स्वीकृति प्रदान करने के साथ ही टाइगर के बाड़े के निर्माण को हरी झंडी दे दी है। प्लान के अंतर्गत ही सीजेडए के नियम और मापदंडों को पूरा करके जू में कुछ आवश्यक सुविधाएं भी जुटाई जाएंगी। उम्मीद है कि गर्मियां शुरू होने से पहले ही यहां शेर का जोड़ा लाया जा सकेगा। उधर वन्य प्राणी विभाग शिमला के डीएफओ राजेश शर्मा ने बताया कि प्लान को स्वीकृति मिल चुकी है। बाड़े का प्राक्कलन भी तैयार कर लिया गया है। उसे स्वीकृति के लिए उच्च अधिकारियों को भेजा जा रहा है। मंजूरी मिलते ही सबसे पहले आधुनिक रूप से बाड़े का निर्माण किया जाएगा। मिनी जू रेणुका में एशियन प्रजाति के शेर लुप्त हो जाने के बाद ही सीजेडए के आदेशों के बाद यहां रहयल बंगाल टाइगर (शेर की दूसरी प्रजाति) लाने

की योजना बनाई गई। रोग रोधक क्षमता कम होने के कारण बब्बर शेर की प्रजाति यहां की आबो हवा से मेल नहीं खा रही थी। विभाग यहां अब रहयल बंगाल टाइगर लाने की तैयारी कर रहा है। शुरूआती तौर पर टाइगर के कम उम्र के एक ही जोड़े को यहां लाया जाएगा। अगर यह जोड़ा यहां की आबो हवा में रस बस गया तो इसकी संख्या को बढ़ाया भी जा सकेगा।

थानाकलां का शिवांग कबड्डी में करेगा हिमाचल का नेतृत्व

द रीव टाइम्स ब्यूरो, ऊना

उपमंडल बंगाणा के थानाकलां स्कूल का होनहार कबड्डी खिलाड़ी शिवांग शर्मा अंडर-14 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिमाचल की टीम का नेतृत्व करेगा। शिवांग की उक्त उपलब्धि से क्षेत्र में खुशी की लहर है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने शिवांग शर्मा को मिष्ठान खिलाकर बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए बेहतर कदम उठा रही है। खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिसकी बदौलत प्रदेश के खिलाड़ी अन्य राज्यों में जाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे है। उन्होंने अपनी ओर से शिवांग को 11 हजार रुपये देने की भी घोषणा की और भविष्य में भी सहयोग देने का आश्वासन दिया। बताते चलें कि राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 12 से 16 जनवरी 2020 तक होगी। इसमें देश भर के खिलाड़ी अपने जौहर दिखाएंगे। प्रदेश की टीम के लिए कोचिंग कैंप का आयोजन हमीरपुर जिला के राजकीय माध्यमिक पाठशाला घंलू में किया जाएगा।

शिवांग शर्मा इससे पहले भी प्रदेश की टीम का प्रतिनिधित्व कर चुका है। इस मौके पर पूर्व जिला परिषद केपी शर्मा, प्रधानाचार्य योगराज भारद्वाज, कै. प्रीतम चंद, अशोक कुमार, डीपीई राजेंद्र सिंह व वार्ड पंच बलदेव सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने भी खिलाड़ी शिवांग, दादा रोशन लाल, दादी प्रकाशो देवी, पिता राजकुमार व माता बृज बाला को बधाई दी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी शिवांग बेहतर प्रदर्शन करेगा।

यौन उत्पीड़न रोकने को होंगे स्कूलों के निरीक्षण

द रीव टाइम्स ब्यूरो, ऊना

नाबालिग यौन उत्पीड़ित बच्चों को आर्थिक सहायता और पुनर्वास योजना के तहत सहायता योजना - 2019 को लेकर बाल कल्याण समिति बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने की। एडीसी अरिंदम चौधरी ने बताया कि नाबालिग पीड़ित / पीड़िता को इस योजना के तहत आजीविका सहायता उपाय के रूप में 21 वर्ष की आयु तक 7 हजार 500 रुपये प्रतिमाह की राशि प्रदान करने का प्रावधान है, जिसमें से 2 हजार 500 रुपये की राशि नाबालिग के बचत खाते में तत्काल चिकित्सा जरूरतों और अन्य आवश्यकताओं के लिए दी जाती है।

उन्होंने बताया कि इसके अलावा 5 हजार रुपये बच्चे एवं पीड़ित / पीड़िता के नाम आरडी प्लैज खाते में जमा करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से नाबालिग पीड़ित / पीड़िता को कैशलेस उपचार की सुविधा दी जाएगी।

साथ ही जिला स्तरीय समिति तकनीकी शिक्षा विभाग की मदद से 16 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर बच्चे एवं पीड़ित / पीड़िता को कौशल आधार प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेगी।

इस अवसर पर एडीसी अरिंदम चौधरी ने बच्चों के साथ होने वाली यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए बाल कल्याण समिति को समय - समय पर स्कूलों में जाकर निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने चाइल्ड लाइन ऊना को भी इस बारे लोगों को जागरूक करने को कहा। उन्होंने संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के

निर्देश दिए, ताकि कोई यौन उत्पीड़ित बच्चा सरकार की ओर से दी जा रही सुविधाओं से वंचित न रहे।

इस अवसर पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऊना विवेक खैनल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऊना विनोद कुमार धीमान, मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऊना डॉ. रमन शर्मा, जिला कार्यक्रम अधिकारी ऊना सतनाम सिंह और जिला बाल संरक्षण अधिकारी ऊना भी उपस्थित रहे।

अब खेतों में उगेगी औषधीय गुणों वाली गुच्छी, प्रयोग सफल

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सोलन

खुंब अनुसंधान निदेशालय चंबाघाट ने गुच्छी तैयार करने के प्रथम चरण में सफलता पाई है। निदेशालय ने यह गुच्छी लैब में तैयार की है। हालांकि, अभी तैयार की गई गुच्छी का आकार प्राकृतिक गुच्छी से बहुत छोटा है। अब उक्त मशरूम को और बेहतरीन बनाने पर काम किया जा रहा है।

इसे आउटडोर में उगाने का भी प्रशिक्षण किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार भारत पहला देश है, जिसे इंडोर गुच्छी उगाने में सफलता मिली है। निदेशालय ने करीब एक वर्ष पूर्व गुच्छी पर अनुसंधान शुरू किया था। निदेशालय ने इंडोर गुच्छी के उत्पादन में सफलता मिली थी। हालांकि, व्यापक स्तर पर अभी गुच्छी का उत्पादन नहीं किया गया है। इसके लिए अनुसंधान चल रहा है। गुच्छी के अपने सीजन समय में प्राकृतिक रूप से तैयार होने की पूरी संभावना है।

औषधीय गुणों से भरपूर गुच्छी के नियमित उपयोग से दिल की बीमारियां नहीं होती हैं। दिल के मरीज अगर इसका उपयोग करते हैं उन्हें भी अधिक फायदा होता है। इसमें विटामिन बी और डी के अलावा सी और के प्रचुर मात्रा में होता है। जो स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होते हैं।

नगर परिषद ने तीन दर्जन अतिक्रमणकारियों को खदेड़ा

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सोलन

नालागढ़ शहर में अतिक्रमणकारियों को चेतावनी या रियायत नहीं दी जाएगी लेकिन सीधी कार्रवाई कर उनका सामान जब्त होगा और जुर्माना ठोका जाएगा। नगर परिषद ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ छेड़े अभियान के तहत चौथे चरण में बाजारों की स्थिति का जायजा लिया और करीब तीन दर्जन अतिक्रमणकारियों को हटाया। साथ ही परिषद ने अतिक्रमणकारियों को चेताया कि परिषद अब किसी प्रकार की रियायत नहीं बख्शेगी और न ही कोई चेतावनी जारी करेगी।

अब सीधी कार्रवाई करते हुए सामान जब्त करेगी और भारी - भरकम जुर्माना भी लगाएगी। नगर परिषद के अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी एवं तहसीलदार नालागढ़ ऋषभ शर्मा के नेतृत्व में नगर परिषद ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ गठित कमेटी के कार्य पर्यवेक्षक एवं सर्वेयर बलजीत राणा की अगुवाई वाली टीम ने नालागढ़ बाजारों से तीन दर्जन अतिक्रमणकारी हटाए हैं। शहर में अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे वह रेहड़ी फड़ी धारक हो या फिर दुकानदारों का सड़कों पर सजाया गया सामान। नगर परिषद के अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी एवं तहसीलदार नालागढ़ ऋषभ

शर्मा ने कहा कि अब परिषद सीधी कार्रवाई करेगी। कई बार हिदायतें और चेतावनी जारी की जा चुकी है। उन्होंने दुकानदारों से आह्वान किया कि वे अपना सामान सड़कों पर नहीं सजाएं वरना नप उनका सामान जब्त करेगी और चालान काट जुर्माना भी वसूलेगी।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

35 करोड़ की लागत से बुझेगी बरमाणा क्षेत्र वासियों की प्यास

द रीव टाइम्स ब्यूरो, बिलासपुर

प्रदेश सरकार सभी वर्गों के परिवारों को किसी न किसी योजना से जोड़ने का प्रयास कर रही है ताकि उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाया जा सके। यह बात सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने बरमाणा में गैस वितरण कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों का जीवन स्तर सुधारने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से प्रत्येक व्यक्ति को घर, बिजली, पानी, स्वास्थ्य बीमा तथा रसोई गैस की सुविधा प्रदान करके हर संभव सहायता प्रदान की जा है। इस अवसर पर उन्होंने गृहिणी सुविधा योजना के तहत 170 निशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना जहां पर्यावरण संरक्षण में सहायक बनी है वहीं प्रदेश सरकार ने पात्र महिलाओं को निशुल्क रसोई गैस सुविधा प्रदान करके महिलाओं का सम्मान व स्वाभिमान बढ़ाया है।

उन्होंने बताया कि बरमाणा क्षेत्र के लोगों की पानी की समस्या को दूर करने के लिए लगभग 35 करोड़ रुपये की लागत से पेयजल योजना बनाई जा रही है जिसका कार्य शीघ्र आरंभ कर दिया जाएगा। इस अवसर पर महामंत्री पवन कुमार, प्रधान ग्राम पंचायत मंजू मिन्हास, सुरेंद्र कुमार, युवा मोर्चा सदस्य अशोक कुमार, अधिशाषी अभियंता वीएन पराशर, बीडीओ भाग सिंह, निरीक्षक खाद्य आपूर्ति विभाग रजनी कालिया, एसडीओ विद्युत शमशेर सिंह के अतिरिक्त स्थानीय गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

बिना स्वीकृति प्लॉटों का रजिस्ट्रीकरण न करे राजस्व विभाग

द रीव टाइम्स ब्यूरो, हमीरपुर

मंडलीय नगर योजना कार्यालय हमीरपुर ने बिते दिनों सुजानपुर में आशा मेहता नगर एवं ग्राम योजनाकार हमीरपुर की अध्यक्षता में जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इसमें सुजानुपर योजना क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों, नगर परिषद सुजानपुर के अधिकारियों / कर्मचारियों, पंचायत प्रतिनिधियों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों को नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम - 1977 के तहत इस क्षेत्र में लागू नियमों और विनियमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। टीसीपी अधिकारी ने ग्रामीण क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियों के लिए अधिनियम के तहत प्रदान की गई छूट और नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 की धारा 16 सी के प्रावधानों के बारे में भी विस्तार से बताया। राजस्व अधिकारियों से आग्रह किया कि वे विभाग से स्वीकृति लिए बिना प्लॉटों का रजिस्ट्रीकरण न करें। लोगों को भी बताया गया कि वे विभाग की ओर से स्वीकृत उपविभाजन भूमि से ही प्लॉट खरीदना सुनिश्चित करें ताकि उन्हें वर्गाकार, आयताकार प्लॉट रास्ते व अन्य सुविधाओं सहित मिल सकें।

आशा मेहता ने भू - संपदा (विनियमन और विकास अधिनियम प्राधिकरण) रेरा के प्रावधानों के बारे में भी अवगत करवाया। कहा कि जो व्यक्ति 500 वर्ग मीटर भूमि पर प्लॉट या 8 से अधिक फ्लैट का निर्माण कर विक्रय करना चाहेगा तो उसे भू - संपदा (विनियमन और विकास अधिनियम प्राधिकरण) रेरा में पंजीकृत होना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त जिले में कहीं भी 2500 वर्ग मीटर से ज्यादा भूमि पर प्लॉट बनाने या फ्लैट का निर्माण विक्रय करना हो तो उस क्षेत्र को डीम्ड योजना क्षेत्र समझा जाएगा और वहां भी विभाग की स्वीकृति लेना व भू - संपदा (विनियमन और विकास अधिनियम प्राधिकरण) रेरा के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है।

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करें प्रदेश सरकार

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कांगड़ा

राजकीय अध्यापक संघ ने प्रदेश सरकार से वर्ष 2016 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जारी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को हिमाचल में अमलीजामा पहनाए जाने की मांग की है। संघ का कहना है कि इससे शिक्षकों सहित अन्य सरकारी कर्मी भी लाभांवित होंगे। एचजीटीयू के जिला अध्यक्ष नरेश कुमार के अनुसार केंद्र सरकार के वर्ष 2016 में जारी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को हिमाचल में अभी तक आईएएस कैटेगरी पर ही लागू किया गया है। ऐसे में अन्य कर्मचारी इससे अभी तक वंचित हैं।

उन्होंने कहा कि यह वेतनमान जनवरी 2016 से देय है। इस अवसर पर जिला महासचिव संतोष पराशर, राम सरूप, अरुण पठानिया, सुरेश नरयाल, देव राज डडवाल, रश्मि ठाकुर, बलवान डडवाल, सरूप चिव, राज कुमार चौधरी, बालकृष्ण मेहरा, पंकज पूरी, विजय शमशेर, राजेश नंदा, विजय राणा, अनिल सुग्गा, अश्विनी सिपहिया, कुलदीप राणा, राकेश कुमार, प्रदीप शर्मा, सुरेंद्र कंदोरीया, राजीव कुमार, शोकत अली, घनश्याम सिंह, राजेंद्र सिंह, सुखदेव सिंह. उपेन्द्र शर्मा उपस्थित रहे।

जांच कमेटी ने बिना हस्ताक्षर के ही भेज दी एसडीएम को रिपोर्ट

द रीव टाइम्स ब्यूरो, बिलासपुर

फोरलेन के निर्माण के दौरान बदले गए रूट की जांच के लिए बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बिना हस्ताक्षर और रिपोर्ट दर्ज किए ही एसडीएम घुमारवीं को भेज दी। इसके बाद एसडीएम ने उसे वापस तहसीलदार घुमारवीं को भेज दिया है। उल्लेखनीय है कि फोरलेन के बदले रूट की जांच के लिए उपायुक्त बिलासपुर ने एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था लेकिन कमेटी ने अपनी आधी अधूरी रिपोर्ट एसडीएम घुमारवीं को सौंप दी है जिससे नाराज होकर एसडीएम ने फिर से पूरी रिपोर्ट मांगी है। एसडीएम घुमारवीं की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने मौजा औहर से कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन के संरेखण परिवर्तन के संबंध में मौका पर रिपोर्ट तैयार करनी थी लेकिन उक्त कमेटी की रिपोर्ट में पाया गया कि कमेटी ने जो रिपोर्ट एसडीएम घुमारवीं को सौंपी है उसमें किसी भी कमेटी के सदस्य के हस्ताक्षर तक नहीं है।

इस पर एसडीएम घुमारवीं ने तहसीलदार घुमारवीं को स्पष्ट रिपोर्ट को भेजने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में क्षेत्रिय कानूनगो रोहिण अत्र सिंह ने बताया कि एनएचएआई भूमि अधिग्रहण की विशेष इकाई मुख्यालय बिलासपुर की ओर से केवल प्यारे लाल कानूनगो ही उपस्थित रहे।

ज्वालाजी अस्पताल में 24 घंटे मिलेंगी दवाइयां

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कांगड़ा

नागरिक अस्पताल ज्वालामुखी में मेडिकल टेस्टों के रेट कम होंगे। अस्पताल में जल्द ही एसआर लैब स्थापित होगी। साथ ही यहां अब 24 घंटे दवाइयां मिलेंगी। अस्पताल प्रशासन ने प्रस्ताव पारित कर विभाग को भेज दिया गया है। ज्वालाजी के विश्रामगृह में रोगी कल्याण समिति की बैठक आयोजित हुई। इसमें योजना बोर्ड उपाध्यक्ष रमेश धवाला ने शिरकत की। एसडीएम ज्वालाजी अंकुश शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 22 लाख रुपये का बजट पास किया गया।

निर्णय लिया गया कि अस्पताल में सिविल सप्लाई की दुकान खोली जाएगी, जिससे मरीजों को 24 घंटे दवाइयां उपलब्ध हो सकें। अस्पताल में गार्ड की नियुक्ति जल्द की जाएगी। अस्पताल परिसर में और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। अस्पताल के इर्दगिर्द लगभग 4 सोलर लाइटें लगाई जाएंगी। वाटर कूलर सहित मरीजों के बैठने के लिए बेंच व हॉल में एलईडी लगवाने सहित अस्पताल में लाइट जाने के दौरान जनरेटर की सुविधा का प्रावधान बजट में किया गया है। मरीज ठंड में न ठिठुरें, इसके लिए यहां हीटर की भी व्यवस्था की जाएगी।

अस्पताल के चारों ओर चहारदीवारी लगाई जाएगी। अस्पताल में डॉक्टरों के बने आवासीय मकानों को सीवरेज सुविधा से जोड़ने का भी प्रावधान किया जाएगा। ज्वालाजी अस्पताल में गेट लगवाने सहित अस्पताल के अंदर खराब पड़े पंखों को ठीक करवाने व एक ओर 108 एंबुलेंस वाहन सहित कार शेड बनाने का भी निर्णय लिया गया।

हैल्थ ऑफिसर व टाउन प्लानर तो दूर नगर निगम में नंही सेनेटरी इंस्पेक्टर

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कांगड़ा

सरकार और शहरी विकास विभाग धर्मशाला के लोगों के प्रति कितना गंभीर है, इसका खुलासा मुंबई की प्रजा फाउंडेशन की रिपोर्ट में हुआ है। इसमें खुलासा हुआ है कि धरातल पर स्मार्ट सिटी परियोजना के काम अभी नहीं दिख रहे हैं। नगर निगम में हेल्थ ऑफिसर व टाउन प्लानर तो दूर की बात, एक सेनेटरी इंस्पेक्टर तक नहीं है। इसके अलावा धर्मशाला शहर के 1000 लोगों के लिए सिर्फ दो कर्मचारी के सहारे काम चल रही है। सफाई कर्मचारियों के कुल 36 पद सृजित हैं, जिसमें से 23 खाली हैं। इसके अलावा ठेकेदार से सफाई का काम करवाया जा रहा है। प्रजा फाउंडेशन ने नगर निगम धर्मशाला की अतिरिक्त आयुक्त, उपमहापौर ओंकार नैहरिया और पार्षदों के समक्ष रिपोर्ट पेश की। प्रजा फाउंडेशन के निदेशक मिलिंद महस्के ने एमसी के अधिकारियों व पार्षदों को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम - 1993 के तहत अनिवार्य 18 कार्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अधिनियम के अनुसार धर्मशाला में 18 कार्यों में से केवल सात कार्यों पर एमसी का सीधा नियंत्रण रहता है, जबकि कई एजेंसियां अन्य सात कार्यों और चार कार्यों पर राज्य सरकार के नियंत्रण में हैं। वर्तमान में एमसी में कुल स्वीकृत पदों में से 35 प्रतिशत (202 स्थायी पदों में से 71) रिक्त हैं। 17 वार्डों में एक कनिष्ठ अभियंता के सहारे काम चलाया जा रहा है। इस मौके पर नगर निगम धर्मशाला की अतिरिक्त आयुक्त मधु चौधरी, उपमहापौर ओंकार नैहरिया, आईपीएच के अधीक्षण अभियंता विकास बख्शी, प्रजा फाउंडेशन के परियोजना अधिकारी हर्षिल सुरेश, पार्षद रणधीर राणा, नीनू शर्मा, सर्वचंद आदि मौजूद रहे। केंद्र सरकार और नीति आयोग को सौंपी जाएगी रिपोर्ट प्रजा फाउंडेशन ने संविधान संशोधन अधिनियम - 1993 के कार्यान्वयन की मैपिंग पर एक राष्ट्रव्यापी अध्ययन किया है। अब तक देश के 23 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश और 33 प्रमुख शहरों को कवर किया है।

कांगड़ा में कीटनाशक-खरपतवार दवाइयों की सप्लाई बंद

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कांगड़ा

कृषि विभाग ने कांगड़ा के कृषि विक्रय केंद्रों के लिए कीटनाशक और खरपतवार सहित अन्य दवाइयों की सप्लाई बंद कर दी है। किसानों को मजबूरन महंगे दामों पर कीटनाशक और खरपतवार दवाइयों की खरीद के लिए निजी बीज-दवाई विक्रेताओं के यहां लुटने को मजबूर होना पड़ रहा है। नवंबर माह में प्रदेश में 2022 तक प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के को लेकर डिप्टी डायरेक्टर कृषि विभाग पालमपुर ने नवंबर माह में एक नोटिफिकेशन जारी की। इस नोटिफिकेशन में जिला कांगड़ा के सभी विषयवाद विशेषज्ञों (एसएमएस) को निर्देश दिए कि सरकारी विक्रय केंद्रों में कीटनाशकों, फफूंदनाशकों, और खरपतवार सहित अन्य दवाइयों को किसानों को उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा। इसके चलते कृषि विभाग ने इस बार जिला कांगड़ा में इन दवाइयों की खेप भी नहीं भेजी।

हालांकि यह सभी दवाइयां जिला कांगड़ा में चल रहे निजी बीज-दवाई भंडारों में किसानों को आसानी से उपलब्ध हो रही है कृषि विक्रय केंद्रों में दवाइयां न मिलने का खामियाजा भी जिला के किसानों को महंगे दामों पर बाहरी दुकानों में दवाइयां खरीद कर भगुतना पड़ रहा है।

बिना बारिश ही गिर गया बिलासपुर में निर्माणाधीन एम्स का 30 फीट ऊंचा डंगा

द रीव टाइमस ब्यूरो, बिलासपुर

बिलासपुर में निर्माणाधीन एम्स साइट में बिना बारिश ही लगभग 30 फीट ऊंचा डंगा ढह गया। आयुष ब्लॉक के लिए जाने वाले रास्ते में लाखों रुपये खर्च कर लगाया गया डंगा गिर गया। जोरदार धमाके से साइट पर दहशत का माहौल बन गया। हालांकि इस हादसे में किसी प्रकार से जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है लेकिन डंगे के गिरने से सरकार को लाखों की चपत लगी है। कंपनी प्रबंधकों ने केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के दौरे से पहले सामने आई घटना पर पर्दा डालने के लिए गिरे डंगे को तिरपालों से ढक दिया ताकि कंपनी की करतूत पर कहीं केंद्रीय मंत्री की नजर न पड़ जाए।

हालांकि निर्माण कार्य में गुणवत्ता को लेकर किसी भी प्रकार का समझौता न करने के दावे किए जाते रहे हैं। बिना बरसात के ही डंगे के गिर जाने से कई सवाल खड़े हो गए हैं। एम्स में जनवरी महीने में शुरू होने वाली ओपीडी पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। क्योंकि ओपीडी को जाने वाली पूरी की पूरी सड़क धंस गई है।

अब ओपीडी शुरू करने को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।

देवभूमि के बेटों ने रोशन किया नाम, वायु सेना में बने फ्लाइंग अफसर

द रीव टाइम्स ब्यूरो, बिलासपुर

शाहतलाई के पट्टा गांव के आश्चित ठाकुर भारतीय वायु सेना में फ्लाइंग अफसर के पद पर तैनात हुए हैं। 21 दिसंबर को एयरफोर्स अकादमी हैदराबाद में पासिंग आउट परेड हुई। आश्चित के पिता विजय ठाकुर बाबा बालक नाथ मंदिर न्यास शाहतलाई में बतौर कनिष्ठ अभियंता के पद पर कार्यरत हैं। माता रेखा कुमारी अध्यापिका हैं। छोटी बहन अंचिता सिंह पीयू से बीएससी की पढ़ाई कर रही हैं।

आश्चित के पिता विजय ठाकुर ने बताया कि आश्चित ने डीएवी बिलासपुर से जमा दो की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2015 में एनडीए की परीक्षा दी। उनका चयन नवंबर 2015 में नेशनल डिफेंस अकादमी खडगवासला पुणे में हुआ। तीन साल की ट्रेनिंग के बाद नवंबर 2018 में इनका चयन एयरफोर्स अकादमी हैदराबाद के लिए हुआ।

हटली क्षेत्र के आशीष कुमार फ्लाइंग अफसर बन गए हैं। आशीष बारी गांव के रहने वाले हैं। पिता प्रेम चंद शर्मा वायु सेना में सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत हैं और माता अंबिका शर्मा गृहिणी हैं। छोटी बहन प्रतिक्षा शर्मा हमीरपुर में दसवीं कक्षा में पढ़ रही हैं। इनके दादा जगदीश चंद शर्मा शिक्षा विभाग से मुख्य शिक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। आशीष की प्रारंभिक शिखा बारी और बलद्वाड़ा स्कूल से हुई है।

जमा दो की परीक्षा सैनिक स्कूल सुजानपुर से पास करने के बाद इन्होंने पुणे से बीएससी की। अब वे फ्लाइंग अफसर बन गए हैं।

चाचा विनोद कुमार शर्मा और चाची रेखा देवी ने बताया कि आशीष की उपलब्धि सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आशीष 21 दिसंबर को भारतीय वायु सेना अकादमी हैदराबाद से पास आउट हुए हैं।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

सीवरेज सिस्टम से जुड़ेंगे मनाली के 26 गांव

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कुल्लू

मनाली और इसके आसपास के क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार विशेष जोर दे रही है। इन सुविधाओं के लिए सरकार ने करोड़ों रुपये का बजट आवंटित किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर होटल निर्माण और पर्यटन गतिविधियों के विस्तार के साथ ही यहां सड़क, बिजली, पानी, सीवरेज और अन्य मूलभूत सुविधाओं की मांग भी बढ़ी है। इसको देखते हुए वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर मनाली शहर और इसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के प्रति गंभीर है।

नगर परिषद मनाली के छूटे क्षेत्रों के साथ-साथ ब्यास नदी के दोनों किनारों की सात ग्राम पंचायतों के लगभग 26 गांवों को भी सीवरेज लाइन से जोड़ने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है। सरकार ने लगभग 162 करोड़ रुपये की इस योजना को प्रशासनिक मंजूरी प्रदान कर दी है। आईपीएच कुल्लू के अधीक्षण अभियंता देवेश भारद्वाज ने बताया कि सीवरेज लाइन से छूटे नगर परिषद मनाली के सात वार्डों के साथ-साथ ब्यास नदी के लेफ्ट बैंक के गांव बाहंग, वशिष्ठ, चचोगा, अलेउ, प्रीणी, शूरू, शामीनाला और जगतसुख, राइट बैंक में गांव ओल्ड मनाली, सियाल, नसोगी, बलसारी, सिमसा, रांगड़ी, कनयाल, छियाल, गधेरनी, बरौड पारशा तथा साथ लगती बस्तियों को भी सीवरेज से जोड़ने के लिए यह योजना तैयार की गई है।

जिले में खुलेंगी उचित मूल्य की 17 दुकानें, लोगों को मिलेगी सहूलियत

द रीव टाइम्स ब्यूरो, चंबा

जिले के विभिन्न विकास खंडों में उचित मूल्य की 17 नई दुकानें खुलेंगी। इससे क्षेत्र के लोगों को घर-द्वार पर सस्ता राशन मिलेगा। यह उचित मूल्य की दुकानें भटियात, तीसा , चंबा, मैहला और सलूणी विकास खंडों में विभिन्न जगहों पर खुलेंगी।

इनमें भटियात विकास खंड के तहत लनोह, ककीरा, डलहौजी, सिहुंता, जोलना और बकलोह 2/4 शामिल हैं। तीसा विकासखंड में गुलेई-1 और फंगड़ोता में उचित मूल्य की दुकानें खुलेंगी। चंबा विकास खंड में सिल्लाघराट और सिंगी दड़ोगा में उचित मूल्य की दुकान खोली जानी प्रस्तावित है। जबकि सलूणी विकास खंड में सुरगानी में उचित मूल्य की दुकान खुलेगी। मैहला विकासखंड के तहत राख, मैहला, धरवाला, लिल्ह, बटोत और गैहरा में उचित मूल्य की दुकानें खोली जाएंगी। इन दुकानों के खुलने से लोगों को काफी राहत मिलेगी।

उन्हें राशन की खरीद के लिए ज्यादा दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। इसके लिए प्रथम प्राथमिकता सार्वजनिक संस्थाओं या सार्वजनिक निकायों जैसे ग्राम पंचायत, स्वयं सहायता समूह, सरकारी सभा, उचित मूल्य की दुकान के प्रबंधन में महिलाएं और उनके समूह को रहेगी।

दूसरी प्राथमिकता में एकल नारी, विधवा जो अपने बच्चों का स्वयं पालन पोषण कर रही हो, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति जोकि उचित मूल्य की दुकान का कार्य भलीभांति से करने में सक्षम हो, भूतपूर्व सैनिक, शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति जिसके परिवार से कोई भी सदस्य नियमित रोजगार में न हो रहेंगे। तीसरी प्राथमिकता हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के लिए रहेगी।

10.17 करोड़ की योजना से दूर होगी पेयजल समस्या

द रीव टाइम्स, कुल्लू

जिला मुख्यालय के साथ लगती खराहल घाटी में लोगों को आने वाले समय में पेयजल की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। खराहल घाटी में पानी की समस्या को खत्म करने के लिए 10.17 करोड़ की लागत से ब्यास नदी-16 टंकी शलाधरा उठाऊ पेयजल योजना का निर्माण किया जाएगा।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग ने उठाऊ पेयजल योजना की डीपीआर तैयार कर ली है। डीपीआर को आईपीएच विभाग ने मंजूरी के लिए नाबार्ड को भेज दिया है। विधायक प्राथमिकता के तहत बनने वाली इस पेयजल योजना से लोगों को पानी की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। खराहल में अक्सर लोगों को पेयजल को लेकर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। गर्मियों के दिनों में तो कई बार यह नौबत आ जाती है कि विभाग को टैंकर लगाकर लोगों को पानी उपलब्ध करवाना पड़ता है। लेकिन ब्यास नदी से 16 टंकी शलाधरा उठाऊ पेयजल बनने से लोगों को काफी राहत मिलेगी। बिजली महादेव में हर साल सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं। इस स्कीम से बिजली महादेव तक पानी की भी आपूर्ति की जाएगी। इससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं को भी पर्याप्त पेयजल मिलेगा। हालांकि उठाऊ पेयजल योजना में ब्यास नदी के पानी को 16 टंकी तक तीन फेज में पहुंचाया जाएगा। पहला फेज सेउगी, दूसरा फेज चंसारी और तीसरा फेज 16 टंकी रहेगा। कुल्लू सदर के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि विधायक प्राथमिकता के तहत ब्यास नदी-16 टंकी शलाधरा उठाऊ पेयजल योजना की डीपीआर आईपीएच विभाग ने 1017.40 करोड़ की तैयार की है।

इसे स्वीकृति के लिए नाबार्ड को भेजा गया है। उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालय के सामने वाले क्षेत्र में इससे पानी की समस्या दूर होगी। ब्यास के पानी को तीन फेज में लिफ्ट किया जाएगा।

रांगड़ी में कचरे से जल्द बिजली होगी तैयार

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कुल्लू

पर्यटन नगरी मनाली के पास रांगड़ी में स्थापित कूड़ा संयंत्र प्लांट से कचरे का निष्पादन शुरू हो गया है। कूड़े के निकलने वाले आरडीएफ को तैयार कर एसीसी सीमेंट फैक्टरी बरमाणा भेजना शुरू कर दिया है।

मनाली में इकट्ठे होने वाले कूड़े का समय रहते निष्पादन किया जा रहा है। मार्च 2020 तक संयंत्र में कूड़े से बिजली पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। कूड़ा संयंत्र शुरू होने से रांगड़ी व उसके आसपास के क्षेत्र के लोगों को कचरे और इससे फैलने वाली बदबू से भी निजात मिली है। गौर रहे कि मनाली के प्रवेशद्वार रांगड़ी में ही कचरे के ढेरों से पर्यटन नगरी की सुंदरता को ग्रहण लग रहा था। स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों को भी यहां कूड़े के ढेर से आने वाली बदबू के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में कूड़ा संयंत्र शुरू होने से लोगों को राहत मिली है। घाटीवासी पूर्ण सिंह, राकेश, सुनील, सन्नी ठाकुर, विजय और तारा चंद ने कहा कि कूड़ा संयंत्र को सही तरीके से चलाया जाना चाहिए, जिससे भविष्य में किसी प्रकार की दिक्कत न आए। उन्होंने कहा कि कूड़ा संयंत्र पिरड़ी का उचित संचालन न होने के कारण इसे बंद करना पड़ा था। नगर परिषद मनाली घरों से कूड़े को अलग-अलग कर संयंत्र तक लाएं, जिससे कूड़े के निष्पादन में समस्या न आए।

वन, परिवहन, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने भी कूड़ा संयंत्र का दौरा किया है। उन्होंने कहा कि मार्च 2020 तक यहां बिजली का उत्पादन शुरू किया जाएगा। पर्यटन स्थल मनाली को साफ - सुथरा और सुंदर बनाए रखने के लिए कूड़ा संयंत्र अपनी अहम भूमिका निभाएगा।

मनाली को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। अनछुए पर्यटन स्थलों को भी प्रदेश सरकार विकसित करने के निरंतर प्रयास कर रही है।

आरटीओ मंडी कार्यालय के नाम पर ट्रांसपोर्टरों से ठग लिए हजारों

द रीव टाइम्स ब्यूरो, मंडी

गूगल पर आरटीओ कार्यालय मंडी का फर्जी नंबर डालकर कुछ शातिर भोले-भाले ट्रांसपोर्टरों और वाहन मालिकों को हजारों रुपये का चूना लगा रहे हैं। प्रभावितों ने इसकी शिकायत आरटीओ कार्यालय मंडी को दी है। प्रारंभिक जांच के बाद आरटीओ कार्यालय ने पाया है कि अगर कोई मंडी आरटीओ का नंबर गूगल सर्च इंजन पर डाल रहा है तो एक फर्जी नंबर आरटीओ मंडी के नाम का आ रहा है। कॉल करने पर शातिर काम पूछने के बाद ऑनलाइन अकाउंट देकर पैसा जमा करवाने की बात कह रहे हैं। लालच देते हैं कि उनका काम घर बैठे ही हो जाएगा। कुछ लोग इनके चंगुल में आकर हजारों रुपये गंवा चुके हैं। इसकी शिकायत आरटीओ मंडी ने एसपी मंडी को सौंपी है। साथ ही फर्जी नंबर 090883-84504 जारी करके ट्रांसपोर्टर और वाहन मालिकों को सचेत रहने की अपील की है। एसपी मंडी गुरदेव शर्मा ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। 01905-235171 या 94183-06092 पर करें संपर्क क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मंडी डॉ. संत राम शर्मा ने बताया कि जब भी कोई व्यक्ति इंटरनेट पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मंडी का दूरभाष नंबर खोजता है तो सर्च में फेक नंबर 090883-84504 आता है। शातिर कुछ पैसे भरने के लिए कहते हैं। कहा कि इस बारे में उन्हें शिकायत मिली है। उन्होंने सार्वजनिक अपील की कि इस कार्यालय का उक्त नंबर का कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने लोगों को इस दूरभाष नंबर पर फोन न करने की सलाह ही है। उन्होंने बताया कि सही जानकारी के लिए उनके कार्यालय दूरभाष नंबर 01905-235171 या 94183-06092 पर संपर्क कर सकते हैं।

हिमकेयर व आयुष्मान धारक मरीजों के ऑप्ररेशनों पर लगी ब्रेक

द रीव टाइम्स ब्यूरो, चंबा

पंडित जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा में हिमकेयर और आयुष्मान भारत कार्ड धारक मरीजों के ऑपरेशन नहीं हो पा रहे हैं। हड्डी और सर्जिकल विभाग के विशेषज्ञों को ऑपरेशन करने में सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। हड्डी का ऑपरेशन करते समय टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए मरीज को रॉड या जैक डालना पड़ता है। ऑपरेशन के दौरान मरीजों के तीमारदार इन उपकरणों को सिविल सप्लाई की ही दुकान से लाते थे लेकिन अब सिविल सप्लाई ने दवाइयों के साथ उपकरणों को भी देने से मना कर दिया है। इसके चलते हिमकेयर और आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों के ऑपरेशन नहीं हो पा रहे हैं। जबकि, जनरल मरीजों के ऑपरेशन नियमित रूप से हो रहे हैं क्योंकि इन मरीजों को उपकरण लेने के लिए पैसे खर्च ही करने पड़ते हैं। मरीजों की समस्या का समाधान करने में मेडिकल कॉलेज प्रशासन भी विफल साबित हो रहा है। मेडिकल कॉलेज में सिविल सप्लाई से दवाइयों की सप्लाई बंद होने के बाद प्रबंधन ने जन औषधि केंद्र से दवाइयां लेना शुरू किया है लेकिन जनऔषधि केंद्र में ऑपरेशन संबंधी उपकरण नहीं मिल पा रहे हैं। इन उपकरणों को लेने के लिए मरीजों को सिविल सप्लाई या निजी केमिस्टों के पास ही जाना पड़ रहा है। अस्पताल में मौजूदा समय में हड्डी और सर्जिकल वार्ड में एक दर्जन से अधिक मरीज ऐसे हैं जो हिमकेयर और आयुष्मान कार्ड धारक हैं। इन मरीजों के ऑपरेशन का सारा खर्च योजना के तहत मुफ्त होना है। दवाइयों का जुगाड़ प्रबंधन जनऔषधि से कर रहा है लेकिन ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों का प्रबंध नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से इन मरीजों को ऑपरेशन के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। चिकित्सा अधीक्षक के मुताबिक जनऔषधि केंद्र से दवाइयों की व्यवस्था की जा रही है। ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की भी जल्द व्यवस्था की जाएगी। सिविल सप्लाई के लंबित बिल का भी भुगतान किया जाएगा, जिससे मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

सरकारी धन के दुरुपयोग पर दो पंचायत प्रधानों को जिलाधीश ने जारी किए नोटिस

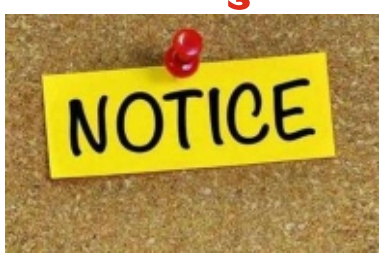

द रीव टाइम्स ब्यूरो, चंबा

जिले की दो पंचायतों के प्रधानों पर सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप लगे हैं। इसको लेकर उपायुक्त ने दोनों पंचायत प्रबंधनों को नोटिस जारी किए हैं। इसमें उनसे संबंधित शिकायतों को लेकर जवाब तलब किया गया है। नोटिस हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1994 के तहत जारी हुए हैं। जांच रिपोर्ट में दोनों प्रधानों को प्रथम दृष्टि में दोषी माना गया है। गौरतलब हो कि विकास खंड भरमौर के तहत ग्राम पंचायत कुगति की प्रधान और विस क्षेत्र भटियात की रायपुर पंचायत प्रधान पर सरकारी धन के दुरुपयोग की शिकायतें जिला प्रशासन के पास पहुंची थी। इन शिकायतों के आधार पर प्रशासन ने अपने स्तर पर जांच प्रक्रिया आरंभ करवाई गई। जांच प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में दोनों पंचायत प्रधानों को प्रथम दृष्टि में दोषी माना गया है। बहरहाल, जिला प्रशासन ने दोनों पंचायत प्रधानों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। जिलाधीश चंबा विवेक भाटिया ने बताया कि जिला प्रशासन ने विकास खंड भटियात की रायपुर पंचायत के प्रधान और भरमौर विकास खंड की कुगती पंचायत की प्रधान के विरुद्ध सरकारी धन के दुरुपयोग को लेकर की गई शिकायतों के मद्देनजर अमल में लाई गई जांच के बाद उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए हैं। पहले मामले में नोटिस प्राप्त होने के 10 दिन और कुगती पंचायत की प्रधान को नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर जवाब देने के आदेश जारी किए गए हैं।

बिजली महादेव सड़क नहीं होगी डबललेन

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कुल्लू

जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बिजली महादेव के लिए सफर सुहाना होने का मामला फिलहाल लटक गया है। 20 किमी सड़क को डबललेन करने की डीपीआर को मंजूरी नहीं मिली है। जिले की चार सड़कों को मंजूरी मिल गई है।

डीपीआर को मंजूरी न मिलने से फिलहाल सड़क डबललेन नहीं होगी। ऐसे में लोगों को इस सड़क पर जाम झेलने के लिए भी तैयार रहना होगा। इसे लेकर स्थानीय लोगों में रोष है। सोशल मीडिया पर भी लोग सड़क को लेकर सरकार के खिलाफ रोष जता रहे हैं। लोग इसे खराहलवासियों के साथ भेदभाव बता रहे हैं। दशहरे के मंच से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घोषणा की थी कि बिजली महादेव सड़क को दूसरे चरण में डबललेन किया जाएगा, जिससे बिजली महादेव की तरफ जाने वाले श्रद्धालुओं को मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। गौर रहे कि बिजली महादेव सड़क वर्तमान में बहुत तंग है। अप्रैल से बिजली महादेव के लिए भारी संख्या में पर्यटक जाना शुरू हो जाते हैं। जाम लगने से लोगों, पर्यटकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

खासकर सावन महीने के दौरान बिजली महादेव मंदिर में हजारों श्रद्धालु शीश नवाते हैं। लेकिन सड़क तंग होने से घंटों जाम लगता है। खराहल घाटी सेब की पैदावार के लिए भी मशहूर है। सेब व धार्मिक पर्यटन

सीजन एक साथ चलने से बिजली महादेव सड़क में जाम की स्थिति बनी रहती है। घाटीवासी गोपाल सिंह ठाकुर, रमेश, रविंद्र सिंह, प्रदीप ठाकुर, यशवर्धन और टेक चंद ने कहा कि बिजली महादेव सड़क को डबललेन करने के लिए मुख्यमंत्री की घोषणा और इसके तीन महीने बाद भी डीपीआर को मंजूरी न मिलना घाटी की जनता के साथ भेदभाव है।

चंबा मेडिकल कॉलेज की प्रयोगशाला में मरीजों के नहीं हो रहे जरुरी टेस्ट

द रीव टाइम्स ब्यूरो, चंबा

मेडिकल कॉलेज चंबा की प्रयोगशाला में मरीजों के जरूरी टेस्ट नहीं हो रहे हैं। इसकी वजह यह हे कि प्रयोगशाला में टेस्ट करने वाली मशीन खराब हो चुकी है। इसके चलते मरीजों को निजी लैबों में महंगे दामों पर टेस्ट करवाने पड़ रहे हैं। जबकि अस्पताल में मरीजों के टेस्ट निःशुल्क होते हैं। या कम दरों पर टेस्ट किए जाते हैं।

चंबा मेडिकल कॉलेज की विभिन्न ओपीडी में रोजाना 1500 से 2000 तक मरीज जांच करवाने के लिए आते हैं। जबकि अस्पताल के विभिन्न वार्डों में 300 से अधिक मरीज भर्ती भी होंगे। इन मरीजों को डॉक्टर इलाज संबंधित जरूरी टेस्ट लिखते हैं। इन्हें करवाने के लिए मरीजों को भटकना पड़ रहा है। वहीं सबसे अधिक परेशानी गरीब और मध्यम वर्गीय तबकों को पेश आ रही है जो कि महंगे दामों पर टेस्ट नहीं करवा रहे हैं।

मेडिकल कॉलेज चंबा में एलएफटी, लिपिड प्रोफाइल, इलेक्ट्रोलाइट, सीबीसी सहित अन्य कई टेस्ट हैं, जोकि अस्पताल की नहीं हो रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में संचालित एमआरएल लैब में भी मरीजों के ये टेस्ट नहीं हो रहे हैं। यहां पर तैनात कर्मचारी भी मशीन खराब बता रहे हैं। ऐसी स्थिति में मरीजों को टेस्ट करवाने के लिए निजी लैबों का रुख करना पड़ रहा है। यहां पर मरीजों से टेस्ट करवाने

के मनमाने दाम लिए जा रहे हैं।

हर प्रयोगशाला में टेस्ट को लेकर अपने-अपने दाम निर्धारित हैं। स्वास्थ्य विभाग का भी इसमें कोई नियंत्रण नहीं है। जिला मुख्यालय में संचालित रेडक्रॉस की प्रयोगशाला में मरीजों को कुछ राहत जरूर मिल रही है। क्योंकि वहां पर निजी लैबों के मुकाबले कम दामों पर टेस्ट किए जाते हैं।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

आजीवन कारावास की सजा कितने साल की होती है? कानून की नज़र से जानें

आर्टिकल 15 क्या है?

भारतीय संविधान का आर्टिकल 15 विधि के समक्ष समता के अधिकार बारे में है। अर्थात विधि के लिए सभी नागरिक बराबर हैं और जात पात, धर्म, लिंग के आधार पर नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

आर्टिकल 15 में कही गई बातों की शुरुआत आर्टिकल 14 से होती है, जिसमें दो मुख्य बातें कही गई हैं :

- आर्टिकल 14 में कहा गया है कि विधि के समक्ष समता, सभी नागरिक समान हैं ।
- विधियों के समान संरक्षण की बात भी आर्टिकल 14 में कही गई है। अर्थात कानून की समान सुरक्षा । इसके कई अर्थ हैं, जिसमें एक यह है कि कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है। किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा । आर्टिकल 15 समता के अधिकार के बारे में ही हमें आगे बताता है, जो बात आर्टिकल 14 में शुरू होती है, उसे आर्टिकल 15 आगे बढ़ाता है ।

आर्टिकल 15 समता के अधिकार का विस्तृत विवरण देता है। संविधान सभा का मानना था कि असमानता के खिलाफ स्पष्ट वर्णन करने के लिए आर्टिकल 14 पर्याप्त नहीं होगा, इसलिए सभा ने विधि के समक्ष समता को समझाने के लिए आर्टिकल 14 से 18 तक इसका वर्णन किया।

आर्टिकल 15 (1) के अनुसार किसी भी जाति, वर्ग, लिंग या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। राज्य किसी नागरिक से केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करेगा।

आर्टिकल 15 का दूसरा उपबंध याने आर्टिकल 15 (2) कहता है कि सार्वजनिक भोजनालयों, दुकानों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, या राज्य-निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग में कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा । हर नागरिक इनका उपयोग बिना किसी भेदभाव के कर सकता है।

आर्टिकल 15 (3) के अनुसार यदि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाए जा रहे हैं तो आर्टिकल 15 ऐसा करने से नहीं रोक सकता। जैसे महिला आरक्षण या बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा। यूं तो सभी नागरिक समान हैं लेकिन महिलाओं एवं बाल विकास के लिए उठाए गए विशेष कदम में आर्टिकल 15 बाधा नहीं है। आर्टिकल 15 (4) के अनुसार राज्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं।

अगर वे कमजोर वर्ग के लिए कोई योजना बनाते हैं तो यह आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं होगा। राज्य सीटों का रिजर्वेशन या फीस में छूट देने जैसे निर्णय ले सकते हैं। आर्टिकल 15 मौलिक अधिकार भी है और मानव अधिकार भी है। इस तरह हमने देखा कि आर्टिकल 15 भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक के प्रावधानों की अहम कड़ी है, जो समता के अधिकार का वर्णन करता है।

एडवोकेट प्रदीप वर्मा
कानूनी सलाहकार, आईआईआरडी, 94180 25649

आपका स्वास्थ्य हमारा परामर्श

दिल की बीमारियों की ये हैं निशानियां और यूं बचें

द रीव टाइम्स ब्यूरो

दिल से जुड़ी मुख्य बीमारियां हैं: एंजाइना, हार्ट अटैक, कार्डिएक अरेस्ट और हार्ट फेल्योर। बीमारी की गंभीरता के लिहाज से देखें तो ये चारों अलग हैं लेकिन ज्यादातर के लक्षण करीब-करीब एक जैसे ही होते हैं।

दर्द से कैसे पहचानें बीमारी

आमतौर पर दर्द के अनुसार बीमारी को पहचानना मुश्किल है लेकिन फिर भी मोटा-मोटा अनुमान लगाया जा सकता है:

एसिडिटी

एसिडिटी का दर्द सीने में एक खास बिंदु पर चुभता महसूस होता है। यह बड़े एरिया में फैला हुआ महसूस नहीं होता।

क्या करें

- 2-3 चम्मच एंटासिड (Antacid) लें। ये मार्केट में डाइजीन (Digene), म्यूकेन जेल (Mucaine Gel), एसिडिन जेल (Acidin Gel) आदि ब्रैंड नेम से मिलते हैं। अगर घंटे भर में दर्द इससे ठीक न हो और बढ़ता जाए तो एंजाइना या हार्ट अटैक का दर्द हो सकता है।

एंजाइना

- अगर छाती के बीच में भारी दबाव महसूस हो, घबराहट हो, सांस रुकी-सी लगे, दर्द जबड़े की ओर जाए बढ़ता लगे, छोटा-मोटा काम (नहाने और खाने जैसे काम करने पर भी) करने पर भी दिल में दर्द महसूस हो और आराम करने पर दर्द बंद हो जाए तो एंजाइना हो सकता है।
- यह दर्द गुस्सा करने, मेहनत का काम करने, सीढ़ियां चढ़ने या चलने-फिरने पर बढ़ जाता है। थोड़ी देर आराम करने पर यह दर्द ठीक हो जाता है।

क्या करें

- मरीज आराम से लेट जाए। गुस्सा न करें, न ही परेशान हों।
- इस दर्द से फौरन मरीज को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन यह दिल में किसी गड़बड़ी का इशारा है। दर्द बार-बार हो तो डॉक्टर के पास जाकर ईसीजी करा लें।
- जब दर्द हो तो ग्लाइसिरल ट्राइनाइट्रेट (Glyceryl Trinitrate) वाली 5 एमजी की गोली जीभ के नीचे रख लें। यह मार्केट में सॉरबिट्रेट (sorbitrate) और आइसोडिल (Isordil) आदि ब्रैंड नेम नाम से मिलती है।

हार्ट अटैक

- अगर सीने के बीचोंबीच तेज दर्द हो, दर्द लेफ्ट बाजू की ओर बढ़ता महसूस हो, सीने पर पत्थर जैसा दबाव महसूस हो, काफी घबराहट-बेचैनी हो, पसीना आए, लगे कि किसी ने दिल को जकड़ लिया है और दर्द कम होने के बजाय बढ़ता जाए तो हार्ट अटैक की आशंका होती है।
- अगर आपके हार्ट की धमनियों में कॉलेस्ट्रॉल जमा होने से कुछ ब्लॉकेज है लेकिन अचानक से वह फट जाए और नली को ब्लॉक कर दे तो हार्ट अटैक होता है।

क्या करें

- आर्टरी के ब्लॉकेज को खोलने के लिए डॉक्टर सबसे पहले मरीज को क्लॉट बस्टर जैसे कि स्ट्रेपटोकायनेस (Streptokinase) या टेनेक्टेप्लेस (Tenecteplase) देते हैं।
- इसके बाद एंजियोप्लास्टी करके स्टेंट डाल देते हैं ताकि आर्टरी की रुकावट खुल जाए।
- हार्ट अटैक में गोल्डन आवर (घंटे) का नियम काम करता है। अगर एक घंटे में इलाज मिल जाए तो दिल की मांसपेशियों को नुकसान नहीं होता। अगर 12 घंटे बिना इलाज के निकल जाएं तो मसल्स पूरी तरह डैमेज हो जाती हैं और उनकी रिकवरी नहीं हो सकती।

कार्डिएक अरेस्ट

- कोई शख्स बिल्कुल ठीकठाक है और अचानक उसका बीपी एकदम नीचे (ऊपर वाला बीपी 90 तक) गिर जाए, शरीर पीला पड़ जाए, वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाए और उसकी धड़कन बहुत तेज या अनियमित होकर एकदम थम जाए तो इसे कार्डिएक अरेस्ट कहा जाएगा। कार्डिएक अरेस्ट अचानक मौत की सबसे बड़ी वजहों में से है।

अगर अस्पताल में किसी को कार्डिएक अरेस्ट होता है तो डॉक्टर एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट, शॉक, वेंटिलेटर आदि के जरिए 80 फीसदी तक मरीजों को बचा सकते हैं।

कैसे पहचानें की दिल फिट है!

अगर आप रोजाना 3 से 4 किमी तेज कदमों से चल सकते हैं और ऐसा करते हुए आपकी सांस नहीं उखड़ती या सीने में दर्द नहीं होता तो मान सकते हैं कि आपका दिल सेहतमंद है। अगर दिल के मरीज हैं और दो मंजिल सीढ़ियां चढ़ने या 2 किमी पैदल चलने के बाद सांस नहीं फूलता तो सामान्य लोगों की तरह एक्सरसाइज कर सकते हैं, वरना डॉक्टर से पूछकर एक्सरसाइज करें।

दिल की बीमारी से बचाव के लिए टेस्ट

40 साल की उम्र में ब्लड प्रेशर (BP) और कॉलेस्ट्रॉल के लिए लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करा लें। अगर रिस्क फैक्टर (फैमिली हिस्ट्री, स्मोकिंग, शराब पीना आदि) हैं तो 25 साल से ही टेस्ट कराएं। अगर सब कुछ ठीक निकलता है तो 2 साल में एक बार टेस्ट करा लें। अगर समस्या लगती है तो डॉक्टर ईसीजी और इको कराने के लिए कहते हैं।

डॉ0 के आर शांडिल
द रीव क्लिनिक, शिमला
अधिक जानकारी के लिए लिखें:hem.raj@iirdshimla.org

कैसे करें करियर की कंफ्यूजन को दूर

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हर कोई जब करियर के चुनाव के पड़ाव में आता है तो उन्हें समझ नहीं आता कि करियर का चुनाव कैसे करें? हर कोई अलग-अगल समय पर करियर विकल्प के बारे में सोचता है।

ज्यादातर लोग कॉलेज खत्म होते ही करियर कैसे बनाये के बारे में सोचते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते है जो नौकरी कर रहे हैं। लेकिन बस पैसे कमाने के लिए वो उस जॉब को कर रहे हैं। करियर का मतलब होता है जिस काम को करने में आपका मन लगे। साथ ही जिस काम से कभी आपका मन न उतरे और रोज उस काम को करने का उत्साह रहे। उस काम में करियर बनाया जाएं तो बात ही कुछ और हो जाएगी।

अपने शौक के बारे में विचार करें

करियर के चुनाव के लिए आप सबसे पहले अपने शोक यानि हॉबीज के बारे में सोचें। कई लोग अपने शौक से ही अपना करियर बनाने के तरीके ढूंढ लेते हैं और उसमें वो लोग काफी सफलता भी प्राप्त करते हैं।

जैसे कि अगर आपको एग्रीकल्चर में शौक है तो आप इसमें भी करियर बनाने के तरीके ढूंढ सकते हैं। आपको पेंटिंग करने का शौक है तो आप अपनी पेंटिंग का एग्जीबिशन कर सकते हैं। अगर आप क्रिएटिविटी में अच्छे हैं तो आपके पास करियर बनाने के अनगिनत करियर विकल्प हैं। जैसे कि आप इंटिरियर डिजाइनर का करियर विकल्प चुन सकते हैं या फिर इवेंट मैनेजमेंट का भी आपके पास एक अच्छा करियर मार्गदर्शन है। इससे आप अपने शौक से भी जुड़े रहेंगे और अच्छी खासी कमाई भी हो जाएगी।

करियर काउंसलर से ले सुझाव

कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको करियर काउंसलिंग की जरुरत पड़ती है। आप किसी करियर मार्गदर्शन संस्था में भी जा सकते हैं। वो लोग करियर सलाहकार के पास जा सकते हैं। और उनको अपने करियर को लेकर जो दिक्कत आ रही है वो बता सकते हैं। करियर काउंसलर से बात करने से आपको करियर का चुनाव कैसे करे के लिए सही सलाह मिलेगी। साथ ही आपको करियर विकल्प के बारे में भी पता चलेगा जिनका आपको अंदाजा भी नहीं होगा।

प्रोफेशनल लोगों से बात करें

अगर आपके पास कई करियर विकल्प हैं और आप अपने लिए सही करियर विकल्प नहीं चुन पा रहे हैं। इस समस्या में आप किसी प्रोफेशनल इंसान से बात कर सकते हैं। जो करियर गाइड बनकर आपकी मदद कर सकते हैं। उन लोगों से आप खुद जाकर मिलें। और उनके साथ करियर काउंसलिंग भी कर सकते हैं या फिर फोन पर भी बात कर सकते हैं।

इंटर्नशिप करें

अगर आपको अपने करियर को लेकर कंफ्यूजन है तो आप पहले इंटर्नशिप कर सकते हैं। इंटर्नशिप का महत्व आपको तभी पता चलेगा। साथ ही आपको पता चलेगा की आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी होगी। फिल्ड में काम करने से आपको अच्छी और सच्ची करियर गाइड मिलेगी। और आपको पता चलेगा कि भविष्य में आपका करियर मार्गदर्शन आपको कहां ले जाएगा। इंटर्नशिप में आप वहां के अनुभवी लोग आपके लिए करियर सलाहकार बन सकते हैं। अगर आप अपनी इंटर्नशिप से खुश हैं तो उसी फिल्ड में अपना करियर बनाएं।

वालंटियर बनें

अगर आपके पास कई करियर ऑपशन हैं तो आप उन सभी के लिए वालंटियर बन सकते हैं। वालंटियरिंग करने के लिए वैसे भी समय नहीं लगता है। इसलिए आप एक से ज़्यादा के लिए वालंटियर बन सकते हैं।

अगर आप छात्र हैं तो क्या करियर चुने

अगर आप 12वीं के बाद करियर के बारे में सोच रहे हैं तो एक बात का खास ध्यान रखें। इस पड़ाव पर कोई भी स्पेसिफिक करियर न चुने। क्योंकि अभी आपके पास कई करियर ऑपशन आएंगे। जैसे कि साइंस में करियर, गणित में करियर, जीव विज्ञान में करियर, आर्ट्स में करियर आदि। जिन करियर के बारे में आपको पता भी नहीं है उन करियर विकल्प से भी आप रुबरु होंगे।

करियर को चुनते समय इन बातों का भी रखें ध्यान असंभव कुछ भी नहीं है करियर को बदल सकते हैं

कई लोग ऐसे होते हैं जो अच्छी खासी नौकरी करने के बाद भी खुश नहीं होते हैं। क्योंकि वो लोग अपने पसंद का काम नहीं कर रहे होते हैं और उनको लगता है कि अब यही उनका करियर मार्गदर्शन है। लेकिन ऐसा नहीं है।

आप अपना करियर बदल सकते हैं। कोई भी किसी भी करियर को बदल सकता है। हमने ऐसी सच्ची कहानियां भी सुनी हैं जहां बड़ी कंपनी की जॉब छोड़कर लोग अपने दूसरे करियर के चुनाव को बदल लेते हैं। क्योंकि अपनी पसंद से काम करने का मजा ही कुछ और होता है। और सबसे बड़ी बात इस काम को करने में मन की शांति मिलती है।

डर को कहो बाय-बाय

सबको एक बड़ा घर, गाड़ी और बैंक बैलेंस चाहिए होता है लेकिन उसे पहले यह जरुरी होता है कि यह सब किस करियर के चुनाव से मिल रहा है और कहां से आ रहा है। क्या जो हम काम कर रहे हैं उस काम से खुश हैं। अगर आप खुश नहीं हैं तो सबसे पहले आपको अपने सही करियर के बारे में समझना होगा। और यह बात आपको आपके अलावा कोई नहीं समझा सकता है। इस फैसले को लेने के लिए आपको अपने डर को भगाना होगा।

यानि की उसे बाय-बाए बोलना होगा। डर इस बात का कि लोग क्या कहेंगे या फिर कम पैसों में गुजारा कैसे होगा। जिस दिन आप इस डर को निकाल देंगे उस दिन आप अपने सपनों को पाने की पहली सीढ़ी पर चढ़ जाएंगे।

प्राथमिकता का रखें ध्यान

करियर चुनने से पहले अपनी प्राथमिकता का भी ध्यान रखें। जैसे कि जो लोग अपने परिवार के साथ ही रहना चाहते हैं, उन लोगों को वो करियर नहीं चुनना चाहिए जिसमें उन्हें घर से दूर जाना पड़े। जो लोग घर से दूर रहने के बाद अपने करियर पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। उनका घर से दूर रहने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए करियर को चुनते समय अपनी प्राथमिकता का भी ध्यान रखें। जिससे आपके करियर पर किसी और चीज का प्रभाव न पड़े।

The Context of 'Happy New Year'

There is no historic or definite scientific interpretation of time / period to determine as to when this earth came into existence. The dawn of the civilization from the Stone Age to the modern era is also assumptive.

With the gradual evolution of the human mind, people thought it important to record the things and to define the time. There was an era of an unknown period before the modern calculation of time started taking place. The ancient system of calculating time and cosmological happenings was evolved in India by the Rishis through rigorous research. The present form of the same calculation got recognition from the era of the Vikramaditya as 'Vikrami Samvat'. Quite limited information is available on the pre-Vikrami-Samvat periods.

The second recording of time and the chronological order thereafter started from the time of existence of Jesus Christ. The historians agreed upon a common time construct and thus began the calculation in form of 'Before Christ' (B.C.) and anno domini (A.D.), which is Latin for 'in the year of the lord'… referring to the periods before and after Jesus was born.

This time period got accepted as a common form of recording history all over the world since the European nations, which were primarily Christian, ruled over a vast number of nations around the globe.

People provided nomenclature to the periods and names like Sunday, Monday, January and so on. But the basis of calculation as per the Indian system is the cosmological happiness taking place regularly and based on defined intervals. Accordingly, the seasons and years have been defined on the similar basis.

Therefore, no matter whatever system of calculating time we adopt, the importance of calculating the timeline cannot be ignored as it gives us the opportunity to make assessment of our progress through the beginning and end of a year.

This also gives us an opportunity to introspect the direction of our progress, which can be classified into two types - internal and external.

The Internal Progress constitutes of endeavours towards good health/physique, a healthy mind and the spiritual evolution. Whereas the External Progress indicates the material and social parameters.

The focus of the majority remains towards the external progress; hence, people are over occupied in material accumulation.

In the internal progress, we tend to care for our body only when it asks so, like when we fall ill or are in pain. Nurturing of mind to make it balanced and unbiased remains of lesser important to people, hence causing a number of problems. The efforts towards spiritual evolution is hardly an agenda for most people.

On the eve of new year, can we resolve that we plan to have periodic detoxification of our body? Can we also resolve that we will take all measures and support from the possible, reliable sources to stabilise our mind and make it stronger and value-based? Can we promise ourselves that we will steal some moments out of our busy schedules to take care of our soul?

As the external progress is already everyone's priority, the celebration of the new year will be more meaningful if we give equal importance to the internal progress as well.

Dr. L.C. Sharma
Editor-in-Chief
Mob.94180 14761, md@iirdshimla.org

नव वर्ष होने के मायने

अभी तक ऐसा कोई इतिहास नहीं है तथा न ही ठोस वैज्ञानिक तथ्य, जो धरती की उत्पति पर सटीक व्याख्या कर सके। पाषाण काल से आधुनिक काल तक सभ्यता के आरंभ की परिकल्पना भी अनुमानित ही है। धीरे-धीरे मानव मस्तिष्क के क्रमिक विकास के साथ लोग घटनाओं के आकलन के साथ - साथ समय को परिभाषित करने लगे।

समय की आधुनिक गणना से पहले एक लंबा अविदित युग रहा। भारत में मनीषी परंपरा द्वारा लंबे शोध के बाद ब्रह्मांडीय घटनाओं के आधार पर समय के निर्धारण की पद्धति प्रतिपादित की गई जिसका वर्तमान स्वरूप सम्राट विक्रमादित्य के समय से विक्रमी संवत के रूप में जाना जाता है। इससे पहले की समय की गणना की सूचना नाममात्र उपलब्ध है। दूसरी गणना जीजस क्राइस्ट के समय से ईसा पूर्व व ईस्वी के रूप आरंभ हुई।

मानव समाज ने समय का रविवार, सोमवार, माघ, फाल्गुन, जनवरी और फरवरी आदि के रूप में नामकरण किया। समय की गणना में भारतीय पद्धति का आधार नियमित व नियमित अंतराल के बाद लगातार होले वाली खगोलीय घटनाएं रहीं और ऋतुएं व वर्ष इसी आधार पर परिभाषित किए गए। वर्ष के आरंभ और अंत हम जिस प्रकार भी निश्चित करें, समय की गणना की महता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि इसी से हम अपनी प्रगति की समीक्षा कर सकते हैं। इससे हमें आत्मविश्लेषण का भी अवसर मिलता है कि हमारी प्रगति किस दिशा में जा रही है।

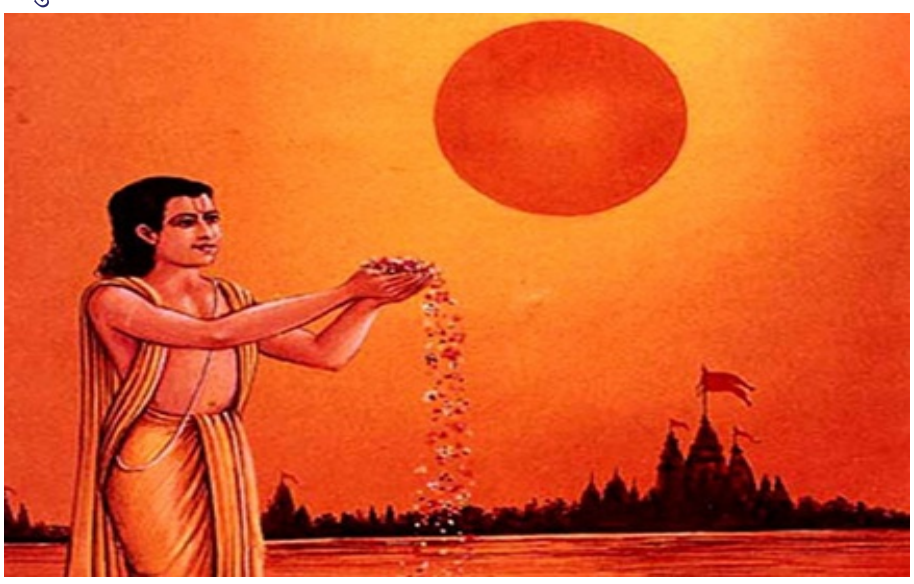

हम अपनी प्रगति को दो भागों में बांट सकते हैं। बाह्य और आंतरिक। हमारे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और आत्मिक उन्नति संबंधि सभी प्रयास आंतरिक प्रगति के सूचक हैं जबकि लौकिक संपदा व सामाजीकरण संबंधि प्रगति बाह्य को प्रदर्शित करते हैं। अधिकांश व्यक्तियों का झुकाव बाह्य प्रगति की ओर रहता है। तभी तो लोग संपत्ति जुटाने में आवयश्कता से अधिक व्यस्त पाए जाते है।

आंतरिक प्रगति में, हम अपने शीरिक स्वास्थ्य की देखभाल तभी करते हैं जब ऐसा करना अपरिहार्य को जाता है। अपने मन को संतुलित तथा निष्पक्ष बनाने के प्रयास हमारी प्राथमिकता में बहुत नीचे रहते हैं। इसीलिए हम कई प्रकार की यातनाएं झेलते हैं। आत्मिक उन्नति शायद ही अधिकांश की प्राथमिकताओं का हिस्सा बन पाती है।

क्या हम नव वर्ष पर तय कर सकते हैं कि हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य की नियमित जांच करवाएं? क्या हम तय कर सकते हैं कि अपने मन को मजबूत तथा मूल्य आधारित बनाने के लिए यथा संभव उपाय कर सके? अक्सर हम अपनी व्यस्तता से कुछ पल आत्मा की उन्नति के लिए भी चुरा सकते हैं, क्योंकि आज के दौर में बाह्य प्रगति सभी की स्वतः ही प्राथमिकता बनी हुई है। नव वर्ष का उत्सव तभी सार गर्भित होगा। जब हम आंतरिक प्रगति को भी बराबर की प्राथमिकता देंगे।

Dr. L.C. Sharma
Editor-in-Chief
Mob.94180 14761, md@iirdshimla.org

वर्ष 2020 आप सभी के जीवन को खुशियों से भर कर सफलता की गारंटी बने, द रीव टाइम्स आपकी आवाज़ बन कर सटीक और सत्य आधारित पत्रकारिता करते हुए सदैव आपकी मंगलकामना करता है। शुभकामनाऐं।

संपादक, द रीव टाइम्स

जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह–शाम

शिमला और पैदल चलना पर्यायवाची

व्यवस्था ही बन गई अवरोधक

न चलना आर्थिक व शारीरिक नुकसान की निशानी

हमारे शरीर की संरचना कुछ इस प्रकार से हुई है कि हम यदि पर्याप्त मात्रा में आहार-विहार न करें और वांछित मानकों का अनुसरण न करें तो हमारा स्वास्थ्य असंतुलित ही रहेगा और एक स्वस्थ जीवन की परिकल्पना संभव नहीं हो पायेगी । विशेषकर जब हम स्वस्थ रहने की बात करते हैं तो इसमें पैदल चलना सबसे पहले स्थान पर हैं जो शरीर की समस्त व्यायाम की क्रियाओं का आधार है । इसे विज्ञान की दृष्टि से देखो या किसी और दृष्टिकोण से....चलना जीवन की सुंदरता की निशानी है । यदि हम आज के आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित जीवनशैली को छोड़कर थोड़ा से पीछे जाऐं और अतीत में नज़र डाले तो हमें सहजता से ज्ञात हो जाऐगा कि चलायमान मानव स्वस्थता के सभी पैमानों पर खरा उतरा है । वाहनों की भीड़ से दूर पैसों के अभाव में लगभग सभी गतिविधियों को पूरा चलकर ही करना पड़ता था । आज भी बुजुर्गों से बात करें तो मालूम पड़ जाता है कि कैसे मीलों के सफर तय करके रोजी-रोटी के लिए चलना पड़ता था । इतना ही नहीं स्कूल जाने के लिए 30 से 50 किलोमीटर का

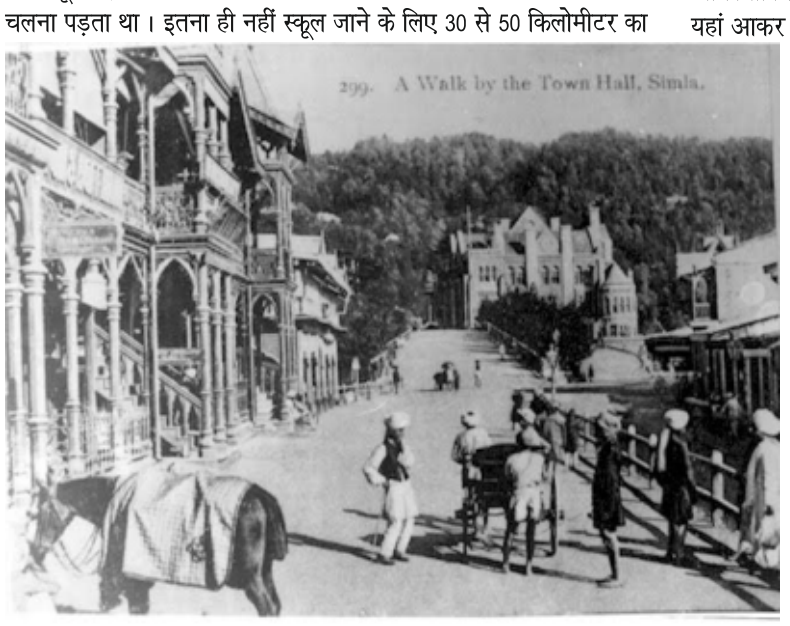

सफर तय किया जाता था । इसका प्रभाव ये देखा जाता है कि आज भी वो पीढ़ी चलना ही पसंद करती है और अक्सर छोटे-बड़े कार्यों के लिए आवाजाही पैदल ही करते हैं ।

गति की दुनिया में भी आज जीवन ठहर सा गया है । पैदा होते ही बच्चों को इतना सुख-सुविधाओं से लैस कर दिया गया है कि वो घर के साथ लगती दुकान से चिप्स का पैकेट भी बाइक या गाड़ी में बैठकर ही लाता है। घर के आंगन से उसे टैक्सी या अपनी कार में बिठाकर स्कूल के गेट तक छोड़ दिया जाता है और घर पर भी वैसे वापिस लाया जाता है । ऐसे में बच्चों में चलने की आदत से हम दूर करते हैं । धीरे-धीरे बच्चे मोटापे का शिकार हो रहे हैं । ये आदत उनके लिए भविष्य में बेहद ख़तरनाक साबित हो सकती है । खान-पान में बदलती आदतें मानसिक और शारीरिक बदलाव के लिए जिम्मेवार है ।

शिमला और पैदल चलना पर्यायवाची

पैदल चलने की बात हो रही हो और शिमला का ज़िक्र न हो ने संभव ही नहीं। बड़ी-बड़ी दुकानों में बिकने वाली पुस्तकों में से कई ऐसी पुस्तकें शोरुम की शोभा बढ़ा रही होती है जिनमें शिमला के पैदल चलने के मार्गों की जानकारी एवं महत्व पर ज्ञान बंट रहा होता है । शिमला एक ऐतिहासिक शहर है और इसकी गरिमा भारत की ग्रीष्मकालीन राज्य होने से भी पहले से विद्यमान है । अंग्रेजों ने अपनी सुविधानुसार शिमला को स्थापित करने में उत्कृष्ठ इंजिनियरिंग का नमूना दिखाया था । तत्कालीन समय के मानवचलित रिक्शे, घोड़ागाड़ी या अन्य वाहन सुविधा को अंग्रेजों ने एक तरतीब तरीके से शिमला के दिल पर संचालित करने में महारत हासिल की थी । लोगों के चलने के लिए शिमला के चारों ओर और केन्द्र में एक सुव्यवस्थित मार्ग सुविधा थी जिसमें पैदल चला जाता था । समय बदला और धीरे-धीरे हमने शिमला के हृदय पर बड़ी-बड़ी ईमारतों का ज़खीरा खड़ा किया । स्थानीय, प्रदेश भर से तथा प्रदेश से बाहरी लोगों ने शिमला को कंकरीट का जंगल बना दिया । निर्माण कार्य ऐसा हुआ कि उसमें चलने से ज़्यादा वाहनों की सुविधा को दरवाज़े तक पहुंचाने की होड़ ही दिखती है । 25 हज़ार की आबादी वाला शिमला अब 5 लाख के पास हमारे ज़िस्म और मनमानी को ढो रहा है । ऐसे में यहां चलने के लिए ट्रैक की असुविधा आज भी है । शिमला एक पहाड़ी पर बसा खूबसूरत शहर है । यहां सुविधा के नाम पर तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं लेकिन यहां की व्यवस्था की चुस्ती-दुरुस्ती का सबसे बड़ा माध्यम पैदल चलना ही है । यह न केवल शिमला की व्यवस्था को सही रखने में कारगर है अपितु इस पहाड़ी शहर में सेहत का का उत्कृष्ठ प्रमाण भी है ।

आज शिमला शहर यातायात की गंभीर समस्या से जूझ रहा है । आर्थिक उन्नति ने जीवन शैली में भी परिवर्तन किया है । ऐसे में हर घर में वाहनों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है । लोग कार्यालयों में अपने-अपने वाहनों का उपयोग करते हैं और इससे शिमला में ट्रैफिक जाम की समस्या ने जीना मुहाल कर दिया है । उस पर बाहरी राज्यों से पर्यटकों की आवाजाही में भी वृद्धि दर्ज़ की गई है । शिमला की वास्तविक सुंदरता को इस यातायात और घुटन ने अपाच्य बना दिया है । स्थानीय लोग तो परेशान है ही लेकिन बाहर से आने वाले पर्यटकों को भी अब शिमला में बहुत सी परेशानियों से दो-चार होना पड़ रहा है । देश और विदेश के पर्यटक यहां जो शिमला को ज़हन में सोच कर आते हैं, यहां आकर उन्हें वो शिमला मिलता भी है, इसमें अतिश्योक्ति है । विशेषकर विदेशी पर्यटक तो चलने को ही जीवन मानते हैं । यहां आकर उन्हें इसलिए निराशा लगती है कि शिमला के मॉल रोड़ और रिज आदि पर ही चलना पड़ता है । शिमला के अन्य क्षेत्रों में तो भीड़ और वाहनों ने शांति-सुकून छीन लिया है ।

स्मार्ट सिटी में करें ग़लतियों में सुधार

शिमला में बेतरतीब तरीके से निर्माण कार्य किया गया तथा इसके चलते पैदल चलने के रास्ते राजस्व विभाग के दस्तावेज़ों में तो दर्ज़ रहे लेकिन धीरे-धीरे उनकी चौड़ाई घटती गई । अब ये रास्ते पूरी तरह से न तो सुरक्षित हैं और न ही इनको इस प्रकार से बनाया गया है कि वो चलने को प्रोत्साहित कर सके । शिमला अब स्मार्ट सिटी में पहला क़दम रख चुका है । ऐसे में इस बात को आरंभिक दौर में ही तय किया जाना आवश्यक है कि शिमला को इसके पुराने प्रारुप में भी रखने के लिए प्राथमिकता दी जाए । यहां चलना ही जीवन है । भवन निर्माण, मार्केट, सड़कें आदि अब धीरे-धीरे आधुनिक प्रारुप में होंगे तो शिमला के चप्पे-चप्पे पर पैदल चलने के लिए रास्तों को बेहतर बनाने के लिए प्रयास हो ताकि लोग सुविधाजनक तरीके से चल सकें। शिमला को निहारना और यहां की खूबसूरती का आनंद लेना है तो वो बिना पैदल चले नहीं हो सकता है । स्मार्ट सिटी में आधुनिक पार्किंग जिसमें सामान्य और शारीरिक रुप से अक्षम लोगों के लिए भी अपना वाहन पार्क करने की सुविधा हो, का निर्माण हो तथा सड़क के एक ओर साईकिल को चलाने तथा दूसरी ओर आरामदायक पैदल मार्गों का निर्माण करना आवश्यक है । शिमला की संरचना वैसे भी इस प्रकार की है कि इसे पैदल चल कर भी घूमा जा सकता है । सबसे बड़ी समस्या यहां के वरिष्ठ नागरिकों को है जिनका शिमला से स्नेह आज का नहीं अपितु उस पुराने शिमला से है जो उस दौर में पैरों से नाप कर पूरा किया जाता था । इस भीड़ में उनकी ये सुविधा आधुनिकीकरण ने छीन ली है । उनको ध्यान में रखते हुए यहां फुटपाथ का निर्माण और यातायात को संभालना होगा ।

बाहरी और निजी वाहनों पर लगे अंकुश

शिमला में अक्सर यह चर्चा होती है कि यहां यातायात की व्यवस्था दम तोड़ चुकी है और इसे सत्य मानने में कोई बुराई भी नहीं है । सरकारें समुचित पार्किंग की व्यवस्था के लिए विधानसभा से लेकर नगर निगम तक के चुनावों में हमेशा शिमलावासियों को वायदा करती रही है । बड़ी तादात में मुख्य शिमला और इसके आसपास पार्किंग का निर्माण हुआ भी है । अफ़सोस कि यातायात की समस्या पहले से भी अधिक विकराल रुप धारण कर चुकी है । यहां यातायात पुलिस सिर्फ वादों पर सरकार को और सरकार अपने वादों पर शिमला वासियों को आवश्वस्त करते रहे हैं । एक व्यक्ति एक कार में अपने कार्यालय आ रहा है । मॉल रोड़ और आसपास से थोड़ा शिमला के अन्य वार्डों में जाओ तो सारे लिंक रोड़ के दोनों ओर गाड़ियों की अवैध पार्किंग है । लोग जाऐं तो कहां जाऐं ? सरकार और नगर निगम शिमला पार्किंग की समस्या से निजात दिलाने में पूरी तरह से असफल रहे हैं । ऐसे में यातायात को एक सुनियोजित योजना के तहत बदलने की आवश्यकता है । शिमला के आरंभ में ही जहां एक बड़ी अदद पार्किंग बनी भी है, वहीं पर बाहरी वाहनों को पार्क करवा दिया जाए और वहां से नगर निगम या सरकार अपनी लग्ज़री बसों के माध्यम से पर्यटकों को शिमला में पहुंचाए । जो स्थानीय लोग या शिमला से बाहरी क्षेत्रों में रहने वाले शिमला आते हैं उन्हें भी निजी वाहनों की आवाजाही पर कुछ नियम-क़ायदे बने । ताकि शिमला को चलने के योग्य रखा जा सके और आबादी को व्यवस्थित करने में परेशानी न हो ।

ऐतिहासिक एवं पुराने फुटपाथ पर भी वाहनों की भीड़

शिमला के ऐतिहासिक फुटपाथ और सड़कें जिन पर चलना कभी शान होती थी, वहां अब गाड़ियों की अवाजाही ने चलना भी दूभर कर दिया है । शिमला में ऐसे अनेक मार्ग है जहां पहले पैदल ही चला जाता था तथा ये मार्ग ऐतिहासिक मार्गों की श्रेणी में आते हैं । नवबहार से संजौली, जाखु मंदिर, फाइव बैंच, संजौली से आईजीएमसी-लक्कड़ बाज़ार, सीटीओ से चौड़ा मैदान-उच्च अध्ययन संस्थान-समरहिल तक आदि ऐसे कितने ही मार्ग है जहां कभी लोग चलकर ही आते-जाते थे । आज उन मार्गों पर चलना सुरक्षित नहीं रह गया है । इन मार्गों पर वाहनों की आवाजाही इस कद्र बढ़ गई है कि वरिष्ठ नागरिक तो इससे खासे परेशान हो चुके हैं । कभी संजौली से लक्कड़ बाज़ार का मार्ग पैदल चलने के लिए ही उपयोग में आता था । आज उस मार्ग पर हर पांच मिनट बाद बसें, गाड़ियों की भागदौड़ है और चलने के लिए अब इस कारण सुरक्षित नहीं है । पहाड़ों के सीने पर जो मार्ग इसकी खूबसूरती के साक्षी थे वहां अब गाड़ियों की पहुंच है और इससे शहरवासियों विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों का सुकून छिन गया है । इन मार्गों पर यहां की अफसरी व्यवस्था और सरकार की मनमानी के चलते अवैध कब्ज़ों के साथ-साथ खुदाई और वाहनों के चलने की स्वीकृति प्राप्त हुई और आज लोग सुकून से चल भी नहीं पा रहे हैं । हर मिनट गाड़ियों के हॉर्न जंगलों में शांति को छीन चुके हैं । इन रास्तों को वाहनों से मुक्त करने की आवश्यकता है । एक एंबुलेंस को ही यहां पर स्वीकृति मिलनी चाहिए ।

चलना ही जीवन है

जितना चला जाए जीवन की सुंदरता में उतना ही निखार आ जाता है । हमें अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करने की वर्तमान में सबसे अधिक आवश्यकता है । कब सोना, कब उठना, कितना चलना, क्या और कितना खाना है, ये सब हमारी जीवनशैली का अहम हिस्सा है । इसमें चलना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के प्रदूषित वातावरण में हम यदि स्वयं को चलायमान रखते हैं तो शरीर की विसंगतियों/विकारों को दूर करने में मदद मिलती है । हमने दरवाज़े से दरवाज़े तक जो वाहनों की सुविधा को अपना लिया है उसका परित्याग करना ही होगा । हमारा प्रयास यही रहना चाहिए कि हम जहां भी संभव हो चलने के अवसर को न त्यागे । अधिक से अधिक चलकर हम अपने शरीर के साथ-साथ मानसिक शांति की प्राप्ति भी कर पाऐंगे। चिकित्सकों की माने तो चलना अपने आप में बहुत बड़ी औषधी है जिससे इंसान अपनी रोग-प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ ही स्वस्थता से दीर्घायु हो सकता है । इसलिए चलने के परहेज न करते हुए अधिक से अधिक चलना ही स्वस्थ जीवन की निशानी है । अधिक से अधिक सरकारी वाहनों का उपयोग करने की आवश्यकता है । इससे न केवल ऊर्जा के अत्यधिक संवर्धन से बचा जा सकता है । साथ ही लगातार भयंकर हो चुके ट्रैफिक जाम की समस्या से भी निजात मिल सकती है ।

नगर निगम और सरकार को बनानी होगी योजना

शिमला को हेरिटेज और ऐतिहासिकता को बनाए रखने के लिए सरकार और नगर निगम शिमला की बड़ी भूमिका रहेगी । इसके लिए बिन देरी किए योजना निर्माण और कार्यान्वयन की ओर अग्रसर होने की आवश्यकता है । शहर में चलने के लिए अधिक से अधिक समुचित व्यवस्था हो इसके लिए समुचित क़दम उठाने ही होंगे । यही एक बड़ा कारण होगा यहां की बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए भी । इसके लिए सभी वार्डों में स्थानों को चिन्हित करके पैदल मार्ग को पुनः सुनियोजित तरीके से निर्मित करके उसे हर वर्ग के चलने के लिए तैयार करने की आवश्यकता है । वरिष्ठ नागरिकों के लिए इन फुटपाथ पर एक उचित दूरी पर बैठने के लिए बैंच की व्यवस्था हो ताकि वहां विश्राम किया जा सके । साथ ही रास्तों के आसपास खाली पड़े स्थानों को जीआईएस तकनीक से चिन्हित करके वहां छोटे-छोटे पार्कों का निर्माण हो । इससे बुजुर्ग और बच्चों को बैठने और मनोरंजन के लिए एक स्थान उपलब्ध होगा । सरकार को यदि पहाड़ों की रानी शिमला को इसकी भव्यता, सुंदरता, ऐतिहासिकता और पौराणिकता को बनाए रखना है तो अविलंब योजना पर कार्य करना ही होगा । प्रदेश की सरकार का केन्द्र बिन्दु शिमला है, नगर निगम शिमला अपनी ऐतिहासिकता के लिए ही जाना जाता है । ऐसे में यह सामुहिक जिम्मेवारी होगी कि इसके लिए सार्थक प्रयास करें । शिमला को पैदल चलने के लिए वातावरण तैयार करना होगा तथा इस पर गंभीरता से कार्य करने की आवश्यकता है । देश और विदेश से शिमला आने वाले पर्यटक भी शिमला की खूबसूरती को आत्मसात तभी कर पाऐंगे जब यहां आकर इसे चलकर देखेंगे और यहां के स्थानीय निवासी भी शिमला में अपनी सेहत को दुरुस्त तभी रख पाऐंगे जब चलते रहेंगे । आइए चलना ही जीवन है इसे चरितार्थ करें.....शिमला को पैरों से मापने की सार्थक पहल करें ।

हेम राज चौहान
संपादक, द रीव टाइम्स
Chauhan.hemraj09@gmail.com,94184 04334

हिमाचल के साढ़े पांच लाख परिवारों को गेहूं की जगह मिलेगा आटा

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल के साढ़े पांच लाख गरीब परिवारों को नए साल जनवरी से सस्ते राशन की सरकारी दुकानों (डिपुओं) में अब गेहूं की जगह आटा दिया जाएगा। अभी तक इन अंत्योदय उपभोक्ताओं को 2 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से गेहूं मुहैया कराया जाता था। गेहूं की पिसाई के लिए प्रति किलो पांच रुपये लिए जाते हैं लेकिन इनसे सरकार सिर्फ 1.20 रुपये ही लेगी। यानी 3.20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आटा मिलेगा। सरकार अंत्योदय परिवारों को 20 किलो आटा जबकि 15 किलो चावल देगी।

लोगों की बार-बार मांग के चलते सरकार ने इसकी अलाटमेंट जारी कर दी है। केंद्र सरकार एपीएल और अंत्योदय परिवार को गेहूं उपलब्ध कराता है। प्रदेश सरकार अपने स्तर पर एपीएल परिवारों को आटा देने के लिए गेहूं की पिसाई कराती है जबकि अंत्योदय परिवारों को गेहूं दिया जाता है। अंत्योदय परिवार के लोग लगातार प्रदेश सरकार पर आटा देने का दबाव बना रहे थे। अब प्रदेश सरकार ने एपीएल की तर्ज पर अंत्योदय परिवारों को भी आटा देने का फैसला लिया है। सूबे के 12 लाख एपीएल परिवारों को जनवरी में प्रति किलो आटा 70 पैसे महंगा मिलेगा। पहले उपभोक्ताओं को 8.60 रुपये के हिसाब से आटा दिया जाता था, अब 9.30 रुपये प्रति किलो मिलेगा। प्रदेश सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। अंत्योदय परिवारों को अब गेहूं की जगह आटा दिया जाएगा। जनवरी से आटा मिलना शुरू हो जाएगा।

उद्योगों की जरुरत के हिसाब से बदलेगा अब कॉलेजों में सिलेबस

द रीव टाइम्स ब्यूरो

प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में अब उद्योगों की जरूरत के हिसाब से सिलेबस बदला जाएगा। शिक्षा को रोजगार के साथ जोड़ने को लेकर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज की मौजूदगी में राजधानी शिमला में हुई राज्य उच्च शिक्षा परिषद की पहली बैठक में यह फैसला लिया गया।

बैठक में कॉलेजों की नैक ग्रेडिंग बढ़ाने को शिमला, मंडी और कांगड़ा को विशेष जोन बनाने पर भी सहमति बनी। इन तीन जिलों में अन्य जिलों के कॉलेजों को शामिल कर नैक की ग्रेडिंग बढ़ाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए विभागीय टीम का चयन किया जाएगा।

जो हर कॉलेज और विश्वविद्यालय में दो माह पूर्व जाकर उसको सुधार कार्यों के बारे में सूचित करेगा। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में उच्च शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018 में विधानसभा में अधिनियम पारित कर संवैधानिक परिषद का निर्माण किया है। यूजीसी और केंद्र सरकार की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में जारी किए गए अनुदान का विश्लेषण प्रदेश परिषद की ओर से किया जाएगा। उस अनुदान का उपयोग परिषद की राय से शिक्षा के अलग-अलग क्षेत्रों में प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रूसा में मिल रहे अनुदान के परिचालन और प्रबंधन करने का कार्य भी परिषद का है।

शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार की ओर से लागू की गई नीतियों का परिषद की ओर से विचार-विमर्श करने के बाद प्रदेश में लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के छात्रों को रोजगार पर आधारित शिक्षा प्राप्त हो सके, इसी उद्देश्य से परिषद को संवैधानिक बनाया गया है।

जीएसटी संग्रहण के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपनाएं अधिकारी: मुख्यमंत्री

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने हाल ही में मण्डी में राज्य स्तरीय जीएसटी की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि आबकारी और कराधान विभाग के अधिकारियों को जीएसटी संग्रहण के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक जीएसटी संग्रह हो सके।

उन्होंने अधिकारियों को जीएसटी के तहत कम से 95 प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा लेकिन जो अधिकारी निर्धारित लक्ष्य हासिल करने में विफल रहेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि फील्ड अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र में सर्कल से मुख्यालय स्तर तक 200 शीर्ष करदाताओं की बारीकी से निगरानी करनी चाहिए।

जय राम ठाकुर ने कहा कि लक्ष्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा के करने के प्रयास किए जाने चाहिए। जीएसटी संग्रह की

निगरानी उच्चतम स्तर पर की जा रही है और इस सम्बन्ध में कोई भी कोताही बर्दाशत नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जीएसटी को जुलाई, 2017 में लागू किया गया था और तब से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जीएसटी वृद्धि कम होने के बावजूद प्रदेश में जीएसटी संग्रहण में नियमित वृद्धि हो रही है।

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय

द रीव टाइम्स ब्यूरो

प्रदेश मंत्रिमण्डल की मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग और हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं में महिला उम्मीदवारों को परीक्षा प्रवेश शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया गया।

एसडीआरएफ का भी होगा गठन

प्रदेश में प्राकृतिक एवं मानव निर्मित खतरों के प्रति संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमण्डल ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) गठित करने का निर्णय लिया है जिसमें तीन कम्पनियां शामिल होंगी। इससे राज्य सरकार को प्राकृतिक आपदाओं के समय न्यूनतम समय में अपने संसाधनों को उपयोग में लाने की सुविधा मिलेगी। इसके अतिरिक्त, एसडीआरएफ का इस्तेमाल मणिमहेश यात्रा, श्रीखण्ड यात्रा, किन्नर कैलाश यात्रा जैसे आयोजनों के लिए भी किया जा सकेगा जहां निवारक उपायों की आवश्यकता रहती है।

एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमण्डल ने सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे 9वीं व 10वीं कक्षा के सामान्य श्रेणी के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण और मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता में 20 हजार रुपये की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय के उपरांत लाभार्थियों को 1.30 लाख रुपये के स्थान पर 1.50 लाख रुपये मिलेंगे। इसी प्रकार, मुख्यमंत्री आवास मुरम्मत योजना के अंतर्गत 25 हजार के स्थान पर 35 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

ई-नाम से जुड़ेंगी 10 सब्जी मंडियां

मंत्रिमंडल ने 10 सब्जी मण्डियों को ई-नाम (इलैक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट) से जोड़ने की स्वीकृति प्रदान की ताकि किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिल सके। इस तरह, अब तक राज्य में 29 सब्जी मण्डियों को इस सुविधा से जोड़ा जा चुका है। इस सुविधा से किसानों को अपने उत्पाद ऑनलाइन बेचने में सहायता मिलेगी और पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें बेहतर दाम मिलेंगे और साथ ही समयबद्ध तरीके से ऑनलाइन अदायगी भी सुनिश्चित होगी।

विभिन्न पदों को भरने की मिली मंजूरी

हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं के 10 पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई है। इन पदों को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती के आधार पर भरा जाएगा। पुलिस विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 174 पद भरने को मंत्रिमण्डल ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिमण्डल ने श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज नेरचौक जिला मण्डी के रेडियोथेरेपी विभाग के कैंसर देखभाल केन्द्र में विभिन्न श्रेणियों के सात पद सृजित करने और भरने का निर्णय लिया है।

इसी प्रकार इन्दिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल शिमला में सीधी भर्ती के माध्यम से रेडियेशन सेफ्टी ऑफिसर का एक पद और चिकित्सा भौतिक विज्ञानी के दो पद भरने को स्वीकृति दी गई है। मण्डी जिला के नगवाईं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 50 बिस्तरों की क्षमता वाले नागरिक अस्पताल के रूप में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 19 पद सृजित कर इन्हें भरा जाएगा। आबकारी एवं कराधान विभाग की कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाने और ई-वे बिल के सत्यापन के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित बनाने, पंजीकरण सत्यापन व डिस्टिलर कर की वसूली और अन्य सम्बन्धित कार्यों के लिए मंत्रिमण्डल ने विभाग ने आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों के 50 पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरने का निर्णय लिया। उपायुक्त शिमला के कार्यालय में जूनियर ऑफिस एसिस्टेंट के 25 पदों को अनुबन्ध आधार पर भरा जाएगा।

पर्यटन को लगेंगे पंख, शिमला में बनेगा प्रदेश का पहला स्काई वॉक

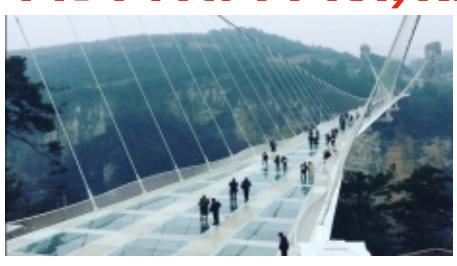

द रीव टाइम्स ब्यूरो

एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) के सहयोग से प्रदेश का पहला स्काई वॉक करोड़ों की लागत से शिमला की हसन वैली में बनने जा रहा है।

इसके अलावा नारकंडा में अंतरराष्ट्रीय स्तर के आई स्केटिंग रिंक खोलने को भी मंजूरी दी है। सैलानियों को लुभाने के लिए शाली टिब्बा में रॉक क्लाइबिंग, हाटू पीक में ट्रैकिंग और बलदेयां में वाटर फॉल का सौंदर्यीकरण हो रहा है। इससे प्रदेश में पर्यटन को पंख लगेंगे। जिला प्रशासन शिमला की ओर से राज्य स्तरीय कमेटी को भेजे गए इन प्रस्तावों को जयराम सरकार से मंजूरी मिल चुकी है।

इस कमेटी के अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। अब इन प्रोजेक्टों को धरातल पर उतारने के लिए इन्हें एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) में डाला जा रहा है।

यहां से इन महत्वाकांक्षी प्रोजेक्टों को करोड़ों की फंडिंग होगी। इसी साल से इन प्रोजेक्टों पर काम शुरू हो सकता है।

प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग को एक लाख, पंद्रह जनवरी तक करें आवेदन

द रीव टाइम्स ब्यूरो

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए प्रदेश सरकार मेधावी विद्यार्थियों को एक लाख रुपये की मदद देगी। मेधा प्रोत्साहन योजना में आवेदन करने के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने आवेदन करने की तारीख को बढ़ाकर 15 जनवरी 2020 कर दिया है।

सालाना 2.50 लाख आय वाले परिवारों के विद्यार्थी इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे।

पात्र विद्यार्थियों को शिक्षा निदेशालय में आवेदन करना होगा। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि अंडर ग्रेजुएशन कर रहे 350 छात्रों और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे 150 छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग लेने के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। अंडर ग्रेजुएशन में सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के 75 फीसदी अंक और आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के 65 फीसदी अंक होने चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन में सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के 50 फीसदी अंक और आरक्षित वर्ग के 45 फीसदी अंक होने चाहिए।

पांच करोड़ के बजट प्रावधान के साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस योजना को शुरू करने की अपने पहले बजट भाषण में घोषणा की थी। मेधा प्रोत्साहन योजना में जमा दो के विद्यार्थियों को जेईई मेन और नीट तथा उच्च स्तरीय शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए कोचिंग दिलाई जाएगी। कॉलेज स्टूडेंट्स को रोजगार आधारित प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे सिविल सेवा की तैयारियों के लिए कोचिंग दिलाई जाएगी। मेधा प्रोत्साहन योजना में राज्य में या राज्य से बाहर कोचिंग के लिए सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। मंत्रिमंडल ने हिमाचल के मेधावी विद्यार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए मेधा प्रोत्साहन योजना को शुरू करने का निर्णय लिया।

योजना के तहत सीएलएटी, एनईईटी, आईआईटी, जेईई, एम्स, एएफएमसी, एनडीए आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग सुविधा प्रदान की जाएगी।

हिमाचल में 6000 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोपी दुबई में गिरफ्तार, जल्द होगा प्रत्यर्पण

द रीव टाइम्स ब्यूरो

Sales tax scam in Himachal: रिपोर्ट के अनुसार, सरकार को कंपनी ने वैट को रूप में 2175.51 करोड़ रुपये का चूना लगाया था। विभिन्न बैंको को 2167 करोड़ और आयकर विभाग को करीब 750 करोड़ रुपये का चूना लगाया था। इसके अलावा, विभिन्न विभागों की करोड़ों की देनदारी भी बकाया है। शिमला, हिमाचल प्रदेश में अब तक के सबसे घोटाले को अंजाम देने वाला आरोपी जल्द ही अब सीआईडी की हिरासत में है। उसे दुबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल, हिमाचल के सिरमौर में बंद हुई इंडियन टैक्नोमेक कंपनी के मालिक राकेश शर्मा को दुबई में पकड़ा गया है। उन पर छह हजार करोड़ रुपये की हैराफेरी का आरोप है।

कुल इतने करोड़ का घोटाला

महासेल्स टैक्स घोटाले के मुख्य आरोपी इंडियन टैक्नोमेक कंपनी के मालिक राकेश शर्मा ने 2008 में पांवटा साहिब में अपनी फैक्ट्री लगाई थी और हिमाचल सरकार को 2100 करोड़ रुपये का चूना लगा कर फरार हो गया था। इनकम टैक्स विभाग, बैंकों और अन्य विभागों को मिलाकर देखे तो राकेश शर्मा करीब 6 हजार करोड़ रुपये डकार कर विदेश भाग गया था। News18 ने मई 2014 में इस सबसे बड़े घपले का पर्दाफाश किया था। अब यह भगोड़ा कानून के शिकंजे में है।

हिमाचल में महंगा हुआ रसोई गैस सिलिंडर, व्यावसायिक के दाम भी बढ़े

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल में रसोई गैस सिलिंडर के दाम 20 रुपये बढ़ गए हैं। जनवरी में उपभोक्ताओं को सिलिंडर लेने के लिए 756 रुपये चुकाने पड़ेंगे। इसके अलावा होम डिलीवरी के लिए अलग से 52.50 रुपये चुकाने होंगे। घरेलू सिलिंडरों की डिलीवरी पर पांच फीसदी जीएसटी लगता है।

घरेलू उपभोक्ताओं को इस माह कुल 808.50 रुपये देने होंगे। 50 रुपये की होम डिलीवरी पर ढाई रुपये जीएसटी के लगेंगे। उधर, व्यावसायिक गैस सिलिंडर के दाम में 26.50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। लगातार पांचवें महीने में गैस सिलिंडरों के दाम में बढ़ोतरी हुई है। दिसंबर में घरेलू सिलिंडर के दाम 13.50 रुपये, नवंबर में 77 रुपये, अक्तूबर में 12 रुपये और सितंबर में 15 रुपये बढ़े थे।

हिमाचल में शराब लाइसेंस देते समय अब बैंक गारंटी और एफडी लेगी सरकार

द रीव टाइम्स ब्यूरो

शराब ठेके का संचालन करने के दौरान लाइसेंस लेने के लिए अब ठेकेदारों को बैंक गारंटी और एफडी देनी पड़ेगी। नए वित्त वर्ष के लिए नई शराब नीति में कई तरह के बदलाव किए जाएंगे, जिनमें जमीन के बजाय एफडी लेने के अलावा शराब ठेके को टीनशेड के बजाय आकर्षक बनाने की शर्त जोड़ी जाएगी।

हाल में ठेकेदारों व अफसरों के साथ हुई बैठकों के बाद विभाग ने शराब नीति में बदलाव की कवायद शुरू कर दी है। दरअसल, पिछले कुछ सालों में विभिन्न ठेकेदारों के पास सरकार के करीब ढाई सौ करोड़ रुपये की रिकवरी फंस गई है। लाइसेंस लेने के दौरान चूंकि पहले जमीन के दस्तावेज लिए जाते थे और जमीन को जब्त करने में कई तरह के कानूनी व्यवधान थे। लिहाजा, विभाग न तो रिकवरी कर पा रहा है और न ही जमीन को अधिगृहीत किया जा पा रहा है।

इस परेशानी को देखते हुए आबकारी विभाग अब वर्तमान शराब नीति में बदलाव करने की तैयारी में जुट गया है। प्रमुख सचिव आबकारी संजय कुंडू ने बताया कि कई मामलों में रिकवरी के दौरान कुछ परेशानियां सामने आई थीं जिसके बाद आबकारी नीति में बदलाव कर संपत्ति दस्तावेज के बजाय बैंक गारंटी या फिक्स डिपॉजिट लेने पर विचार किया जा रहा है।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

कुलदीप ने रचा इतिहास, दो हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय

द रीव टाइम्स ब्यूरो

कुलदीप यादव एकदिवसीय अंतराष्ट्रीय क्रिकेट में दो हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। यह मुकाम कुलदीप यादव ने 18 दिसंबर 2019 को एसीए-वीडीसीए स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए दूसरे वनडे मैच में हैट्रिक लेकर हासिल किया। कुलदीप यादव की शानदार गेंदबाजी ने भारत की जीत में बड़ी भूमिका निभाई और भारतीय टीम को दूसरे मैच में 107 रन से जीत मिली। कुलदीप यादव ने यह कारनामा 33वें ओवर में शाइ होप, जेसन होल्डर और अल्जारी जोसेफ के लगातार तीन विकेट लेकर अपनी दूसरी अंतरराष्ट्रीय हैट्रिक बनाई। कुलदीप यादव ने अपनी पहली हैट्रिक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साल 2017 में कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर ली थी।

साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019: शशि थरूर समेत 23 लेखकों को मिलेगा यह पुरस्कार

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हाल ही में राजनेता एवं लेखक शशि थरूर तथा नाटककार नंद किशोर आचार्य समेत 23 लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 हेतु चुना गया हैं। साहित्य अकादमी के अनुसार, इन सभी विजेताओं को 24 फरवरी 2020 को दिल्ली में ताम्र पत्र और एक लाख रुपये के नकद पुरस्कार के साथ सम्मानित किया जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत में एक साहित्यिक सम्मान है। साहित्य अकादमी द्वारा यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। ये पुरस्कार पहली बार साल 1955 में दिये गये थे। पुरस्कार की स्थापना के समय पुरस्कार राशि मात्र पांच हजार रुपए थी लेकिन समय-समय पर यह राशि बढ़ती गई।

सुप्रीम कोर्ट ने 'निर्भया' केस में चारों अभियुक्तों की मौत की सजा बरकरार रखी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है साल 2017 के फैसले पर पुनर्विचार करने का कोई आधार नहीं है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद चारों दोषियों पवन, मुकेश, अक्षय और विनय की फांसी को लेकर 'डेथ वारंट' जारी करने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करने के साथ ही यह भी कहा कि दोषी को बचाव का पूरा मौका दिया गया था कोर्ट ने कहा कि इस केस के ट्रायल एवं जांच में कोई खामी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष के वकीलों को अपनी-अपनी दलील रखने हेतु 30-30 मिनट का समय दिया था।

ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 112वें स्थान पर: रिपोर्ट

द रीव टाइम्स ब्यूरो

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) ने हाल ही में यह रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत लिंग असमानता के मामले में साल 2018 के मुकाबले चार रैंक पिछड़ गया है।

डब्ल्यूईएफ के अनुसार, विश्वभर में लिंगभेद कम तो हो रहा है लेकिन अभी भी महिलाओं एवं पुरुषों के बीच स्वास्थ्य, शिक्षा, कार्यालय तथा राजनीति में भेदभाव मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक, देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, काम और राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं और पुरुषों में अभी भी असमानता है। हालांकि, साल 2018 में स्थिति थोड़ी बेहतर हुई थी डब्ल्यूईएफ ने साल 2006 में जेंडर गैप को लेकर पहली बार रिपोर्ट पेश की थी। भारत उस समय 98वें स्थान पर था।

दक्षिण अफ्रीका के वर्नन फिलेंडर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सन्यास की घोषणा की

द रीव टाइम्स ब्यूरो

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के गेंदबाजी ऑलराउंडर वर्नन फिलेंडर ने घोषणा की है कि वे इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेंगे। दक्षिण अफ्रीका को 26 दिसंबर 2019 से इंग्लैंड के विरुद्ध चार मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी हैं। यह सीरीज 28 जनवरी 2020 को खत्म होगी। फिलेंडर इसके बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह देंगे।

वर्नन फिलेंडर ने अपने टेस्ट करियर में 60 मैच में कुल 216 विकेट लेने में सफल रहे हैं। वहीं वनडे में 30 मैच खेलकर 41 विकेट चटकाने में सफल रहे हैं। उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए डेब्यू साल 2007 में आयरलैंड के खिलाफ वनडे मैच खेलकर किया था। उन्होंने आखिरी टेस्ट मैच भारत के खिलाफ साल 2019 में पुणे टेस्ट में खेला था।

2019 विराट कोहली 100 सेलेब्रिटी में टॉप पर आलिया भट्ट ने दीपिका पादुकोण को छोड़ा पीछे

द रीव टाइम्स ब्यूरो

विराट कोहली ने फोर्ब्स की सूची में सलमान खान को पछाड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है।

वहीं, इस सूची में बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार दूसरे स्थान पर तथा सलमान खान तीसरे स्थान पर हैं। फोर्ब्स की टॉप-10 सूची में आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण का भी नाम है।

फोर्ब्स द्वारा जारी यह रैंकिंग 01 अक्टूबर 2018 से 30 सितंबर 2019 के बीच मशहूर हस्तियों की अनुमानित कमाई एवं उनकी प्रसिद्धि के अनुमान पर आधारित है। यह पहला मौका है जब किसी खिलाड़ी ने फोर्ब्स सेलेब्रिटी टॉप-100 की सूची में शीर्ष स्थान हासिल की है।

बेल्जियम फीफा की साल की सर्वश्रेष्ठ टीम

द रीव टाइम्स ब्यूरो

फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा ने हाल ही में बेल्जियम को लगातार दूसरी बार साल की सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल टीम के पुरस्कार से सम्मानित किया है।

इस समय बेल्जियम फीफा विश्व रैंकिंग में शीर्ष पायदान पर मौजूद है। विश्व चौंपियन फ्रांस दूसरे स्थान और ब्राजील तीसरे स्थान पर हैं। इंग्लैंड एक स्थान ऊपर चढ़कर चौथे स्थान पर पहुंच गया है। उरुग्वे दो पायदान ऊपर उठकर पांचवें नंबर पर आ गया है। बेल्जियम साल 2015 और साल 2018 साल की सर्वश्रेष्ठ टीम का पुरस्कार जीत चुकी है। इस साल बेल्जियम ने सभी अपने 10 ए-स्तर के मैच जीते हैं तथा उसने यूएफा यूरो-2020 हेतु क्वालिफाई किया है। आठ पश्चिम अफ्रीकी देशों ने साझा मुद्रा का नाम बदला।

डीआरडीओ ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का किया सफल परीक्षण, जानिए इसकी खासियत

द रीव टाइम्स ब्यूरो

ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को जमीन एवं हवाई प्लेटफार्मों से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इस मिसाइल को मोबाइल ऑटोनॉमस लांचर से चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज (आईटीआर) में लांच कॉम्प्लेक्स-३ से प्रक्षेपित किया गया। डीआरडीओ ने इसमें मिसाइल एयर फ्रेम, फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम को डिजाइन किया था। ब्रह्मोस मिसाइल के समुद्री तथा थल संस्करणों का पहले भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है। इस मिसाइल की मारक क्षमता बहुत ही अचूक है। इस मिसाइल को डीआरडीओ लगातार अपग्रेड कर रहा है। ब्रह्मोस भारत एवं रूस के द्वारा विकसित की गई है।

लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने भारत के अगले थलसेना प्रमुख

द रीव टाइम्स ब्यूरो

सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत 31 दिसंबर 2019 को सेवानिवृत्त हुए। इनके स्थान पर मुकुंद नरवाने ने यह पद संभाला।

उन्होंने इस वर्ष सितंबर में वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जिम्मेदारी संभाली थी। इससे पहले वे सेना की पूर्वी कमान की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने को अपनी 37 वर्षों की सेवा के दौरान आतंकवाद - विरोधी अभियानों में काम करने का व्यापक अनुभव प्राप्त है। उन्होंने श्रीलंका में शांति सेना में भी भाग लिया तथा तीन वर्षों तक म्यांमार में भी सेवाएं प्रदान कीं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतरिक्ष बल का किया गठन

द रीव टाइम्स ब्यूरो

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष बल का गठन किया है। अमेरिका ने रक्षा मंत्रालय के तहत पूर्ण विकसित अमेरिकी अंतरिक्ष बल का गठन कर चीन तथा रूस से लगातार मिल रही सामरिक चुनौतियों का उपाय ढूंढ लिया है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतरिक्ष बल के गठन को वास्तविकता में बदलने हेतु साल 2020 राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण कानून पर हस्ताक्षर किया, जो पेंटागन बल के लिए शुरुआती बजट तय करेगा जो सेना की पांच अन्य शाखाओं के लिए बराबर होगी। अमेरिका द्वारा अंतरिक्ष बल स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष में अमेरिकी क्षमता तथा प्रभुत्व को स्थापित करना है।

झारखंड विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2019 जेएमएम गठबंधन को 47 सीटें, बीजेपी को 25

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हाल ही में चुनाव आयोग ने झारखंड विधानसभा चुनाव के अंतिम परिणाम जारी कर दिए हैं। इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) को 30, कांग्रेस को 16 और आरजेडी को 1 सीट मिली है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को सिर्फ 25 सीटें हासिल हुई। झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 05 जनवरी 2020 को समाप्त हो रहा है। यहां कुल 81 विधानसभा सीटें हैं। इनमें 28 अनुसूचित जनजाति और 09 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। झारखंड में 30 नवंबर से 20 दिसंबर तक पांच चरणों में मतदान हुआ था।

DRDO ने पिनाक मिसाइल प्रणाली का किया सफल परीक्षण

द रीव टाइम्स ब्यूरो

डीआरडीओ द्वारा विकसित पिनाका मिसाइल प्रणाली का हाल ही में ओड़िसा के चांदीपुर तट से सफल परीक्षण किया गया। पिनाका मार्क-2 ने सभी लक्ष्यों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। मिसाइल की नौसंचालन प्रणाली को भारतीय क्षेत्रीय नौसंचालन उपग्रह प्रणाली से भी सहायता मिलती है। पिनाका भारत में उत्पादित एक बहुखंडीय रॉकेट लांचर है।

यह रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा विकसित किया गया है। भारतीय सेना ने वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान पिनाका मार्क-1 संस्करण का उपयोग किया था। पिनाका का विकास दिसंबर 1986 में शुरू हुआ था।

पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2020 तक बढ़ी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने हाल ही में पैन (स्थायी खाता संख्या) को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च 2020 कर दिया।

यह तारीख इससे पहले 31 दिसंबर 2019 थी। सरकार ने 8वीं बार आधार को पैन से जोड़ने की समय-सीमा बढ़ाई है। आयकर भरने के लिए आधार को पैन से जोड़ना अनिवार्य है। 01 अप्रैल 2019 से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने हेतु भी आधार-पैन लिंक होना अनिवार्य है। पैन 10 कैरेक्टर (अल्फा - न्यूमैरिक) वाली पहचान संख्या है।

इसे इनकम टैक्स विभाग द्वारा जारी किया जाता है। आधार 12 अंकों वाला यूनीक आइडेंटिफिकेशन संख्या है। इसे यूनिक ऑइडेंडिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किया जाता है।

लिवरपूल ने फीफा क्लब विश्व कप का खिताब जीता

द रीव टाइम्स ब्यूरो

यूरोप की दिग्गज फुटबॉल क्लब लिवरपूल ने हाल ही में फीफा क्लब विश्व कप का खिताब जीत लिया है। कतर में फ्लेमेंगो के विरुद्ध खेले गये इस मैच में लिवरपूल ने ब्राजील के क्लब फ्लेमेंगो को एकमात्र गोल से हरा कर यह कामयाबी हासिल की।

इस जीत के साथ ही लिवरपूल इस खिताब को जीतने वाली दूसरी इंग्लिश टीम बन गई है। इससे पहले साल 2008 में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने यह सफलता प्राप्त की थी। लिवरपूल इंग्लैंड का एक फुटबॉल क्लब है। लिवरपूल विश्व के सबसे अच्छे फुटबॉल क्लब में से एक माना जाता है।

मीराबाई चानू ने कतर इंटरनेशनल कप में जीता स्वर्ण पदक

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने दोहा में चल रहे कतर इंटनेशनल कप में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने 20 दिसंबर 2019 को महिलाओं की 49 किलो वर्ग में सफलता हासिल की।

उन्होंने ओलंपिक क्वालीफायर में 194 किलोग्राम भार उठाया। ये अंक टोक्यो ओलंपिक 2020 की अंतिम रैंकिंग के समय उपयोगी साबित होंगे। मीराबाई चानू चोट के कारण साल 2018 में विश्व चौम्पियनशिप और एशियाई खेलों में भाग नहीं ले सकी थीं। वे एक भारतीय भारोत्तोलन खिलाड़ी हैं। उन्होंने विश्व चौम्पियनशिप तथा राष्ट्रमण्डल खेलों में पदक जीते हैं। उन्हें खेल के क्षेत्र में योगदान हेतु भारत सरकार से पद्म श्री पुरस्कार मिल चुका है।

दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को दी मंजूरी, प्रदूषण पर लगेगा लगाम

द रीव टाइम्स ब्यूरो

दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। ये फैसला दिल्ली सरकार ने दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने हेतु किया है। दिल्ली सरकार सार्वजनिक से लेकर निजी क्षेत्र को ई-वाहन के उपयोग हेतु प्रोत्साहित करेगी।

वाहनों की चार्जिंग हेतु प्रत्येक तीन किलोमीटर पर चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। ई-वाहन नीति का पहला मसौदा नवंबर 2018 में सार्वजनिक किया गया था। सरकार ने नई खरीदी जाने वाली बसों में से 50 फीसदी ई-बसें खरीदने का भी लक्ष्य रखा है। नई पॉलिसी के अंतर्गत एक साल में 35 हजार इलेक्ट्रिक वाहन तथा 250 चार्जिंग स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

राखी हलदर ने वेटलिफ्टिंग में बनाए दो राष्ट्रीय रिकॉर्ड, जीता कांस्य पदक

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हाल ही में राखी हलदर (64 किग्रा) ने कतर इंटरनेशनल कप में कांस्य पदक जीतने के साथ ही दो नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाए। वे एक कॉमनवेल्थ स्वर्ण पदक विजेता हैं। इन्होने स्नैच और कुल भार में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है।

नीति आयोग ने 'एसडीजी इंडिया इंडेक्स' और 'डैशबोर्ड 2019' लॉन्च किया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

नीति आयोग ने हाल ही में 'सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) इंडिया इंडेक्स' का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। यह साल 2030 एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में भारत के राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा की जाने वाली प्रगति को व्यापक रूप से दर्शाया जाता है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2019 दरअसल भिन्न-भिन्न लक्ष्यों और संकेतकों की व्यापक कवरेज की बदौलत प्रथम संस्करण की तुलना में कहीं ज्यादा सुदृढ़ है तथा एनआईएफ के साथ इसका सामंजस्य भी अपेक्षाकृत अधिक है।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

सऊदी अरब और कुवैत ने सुलझाया ऑयल फील्ड विवाद

द रीव टाइम्स ब्यूरो

सऊदी अरब और कुवैत ने एक साझा तेल क्षेत्र से जुड़ा करीब पांच साल पुराना विवाद सुलझा लिया है। दोनों देश न्यूट्रल जोन में तेल उत्पादन पुनः शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। हालांकि सऊदी ने यह स्पष्ट किया है कि इस सहमति के कारण कच्चे तेल का उत्पादन कम करने की ओपेक की प्रतिबद्धता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दोनों पड़ोसी देशों की जमीनी सीमाओं के बीच एक डिवाइडेड जोन है। 2015 में एक विवाद के बाद से यहां के तेल क्षेत्र में उत्पादन रोक दिया गया था। इस रोक से पहले यहां रोजाना करीब तीन लाख बैरल तेल प्रतिदिन निकाला जाता था। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, इस क्षेत्र की क्षमता रोजाना पांच लाख बैरल तेल उत्पादन की है। विवाद खत्म करने और क्षेत्र में पुनः तेल उत्पादन शुरू करने के लिए दोनों देशों ने कुवैत में इस संबंध में समझौते पर हस्ताक्षर किया। सऊदी की तरफ से ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुलअजीज बिन सलमान ने समझौते पर हस्ताक्षर किया। वह पिछले कुछ साल से पड़ोसी देश से इस विवाद को सुलझाने की दिशा में काम कर रहे थे। कुवैत की समाचार एजेंसी ने बताया कि समझौते के इस खास पल के लिए भव्य समारोह आयोजित किया गया था। इस दौरान कुवैत के विदेश मंत्री, ऊर्जा मंत्री एवं अन्य कई अधिकारी उपस्थित रहे थे। इस बीच, सऊदी की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि इस समझौते के कारण सऊदी अरब की उस प्रतिबद्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसके तहत कच्चे तेल के उत्पादन को घटाकर 97 लाख बैरल प्रतिदिन करने को कहा गया है।

मुशर्रफ की अपील पर लाहौर हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ करेगी सुनवाई, मौत की सजा को दी है चुनौती

द रीव टाइम्स ब्यूरो

पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट ने पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ की अपील पर सुनवाई के लिए पूर्ण पीठ का गठन किया है। मुशर्रफ ने अपनी अर्जी में उस विशेष अदालत के गठन को चुनौती दी है, जिसने उन्हें देशद्रोह के मामले में मौत की सजा सुनाई है। डॉन अखबार के अनुसार, हाई कोर्ट की यह नवगठित पीठ नए साल नौ जनवरी से मुशर्रफ की अर्जी पर सुनवाई शुरू करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित विशेष अदालत की तीन सदस्यीय पीठ ने गत 17 दिसंबर को 76 वर्षीय पूर्व सैन्य शासक को देशद्रोह मामले में दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई थी।

वर्ष 2007 में पाकिस्तान पर आपातकाल थोपने, संविधान निलंबित करने और जजों को हिरासत में रखने के आरोप में मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में घिरते देख मुशर्रफ इलाज के बहाने 18 मार्च, 2016 को दुबई चले गए थे। तब से वह अपने मुल्क नहीं लौटे। मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह का यह मामला दिसंबर, 2013 से चल रहा था। करीब छह साल की सुनवाई के बाद विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया। जजों ने 167 पेज के अपने फैसले में लिखा कि अगर सजा दिए जाने से पहले ही मुशर्रफ की मौत हो जाती है तो उनके शव को मुल्क में लाया जाए और इस्लामाबाद के डी-चौक पर तीन दिन तक फंदे से लटकाकर रखा जाए।

मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में उत्तर कोरिया ने अमेरिका को चेताया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

उत्तर कोरिया में मानवाधिकार की स्थिति पर अमेरिकी विदेश विभाग की चिंता पर प्योंगयांग ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उत्तर कोरिया ने कहा है कि कोरियाई प्रायद्वीप में पहले से ही तनाव व्याप्त है, ऐसे में अमेरिका का यह बयान आग में घी का काम करेगा। प्योगयांग ने जोर देकर कहा है कि अमेरिका के इस दृष्टिकोण से दोनों देशों के बीच और तनाव बढ़ेगा। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस सप्ताह प्योंगयांग में मानवाधिकारों के उल्लंघन की निंदा की थी। महासभा का कहना था कि के उत्तर कोरिया में लंबे समय से मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। बता दें कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने भी उत्तर कोरिया को राजनीतिक दमन के लिए और दशकों से परमाणु हथियारों के कार्यक्रम को प्राथमिकता देने के लिए निंदा की थी। इसके बाद अमेरिका ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। कोरियाई सेंट्रल न्यूज एजेंसी के अनुसार उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि प्योंगयांग के मानवाधिकार रिकॉर्ड की निंदा करना कोरियाई प्रायद्वीप पर पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति को और बद्तर कर देगा। केसीएनए ने कहा कि उत्तर कोरिया की यह प्रतिक्रिया मानवाधिकार की स्थिति पर अमेरिकी विदेश विभाग के एक अधिकारी द्वारा व्यक्त की गई चिंता के जवाब में था।

सीरिया समस्या पर बात करेंगे रुस और तुर्की पलायन का मुद्दा मुख्य एजेंडे में शामिल

द रीव टाइम्स ब्यूरो

अमेरिका ने ईरान में चाबहार बंदरगाह के मामले में भारत को प्रतिबंधों से छूट दी है क्योंकि वाशिंगटन का कहना है कि यह रणनीतिक परियोजना युद्धग्रस्त अफगानिस्तान के लिए भारत से मानवीय आपूर्ति प्राप्त करने के लिए जीवनरेखा है। जयशंकर ने जरीफ को उनके सौहार्दपूर्ण स्वागत और सत्कार के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने ट्वीट किया, ईरानी विदेश मंत्री के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक तस्वीर पर बहुत अच्छी बातचीत हुई। भारत और ईरान अपने साझा हितों को लेकर मिलकर काम करेंगे। इससे पहले जरीफ ने ट्वीट किया कि दोनों देशों ने करीबी द्विपक्षीय संबंधों और हमें प्रभावित करने वाले क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अच्छी चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमारे संबंध प्राचीन, ऐतिहासिक और अटूट हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महासभा के 74वें सत्र के मौके पर रुहानी से मुलाकात की थी।

ट्विटर यूजर्स के डाटा में लगी बड़ी सेंध, एंड्रायड एप में खामी के चलते 1.7 करोड़ फोन नंबर हुए हासिल

द रीव टाइम्स ब्यूरो

माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफार्म ट्विटर की सुरक्षा में सेंध का एक और मामला सामने आया है। एक शोधकर्ता ने ट्विटर के एक एंड्रायड एप में खामी के जरिये उससे करीब 1.7 करोड़ यूजर के फोन नंबर हासिल करने का दावा किया है। जिन लोगों के फोन नंबर हासिल किए गए हैं, उनमें कई दिग्गज राजनेता और अधिकारी बताए गए हैं।

प्रौद्योगिकी वेबसाइट टेकक्रंच के अनुसार, सुरक्षा मामलों के शोधकर्ता इब्राहिम बालिक ने पाया कि ट्विटर के कांटैक्ट अपलोड फीचर के जरिये फोन नंबर की पूरी सूची अपलोड हो सकती है। उन्होंने कहा, अगर आप अपना फोन नंबर अपलोड करते हैं तो बदले में यह यूजर का पूरा डाटा ला देता है।श इस तरीके से प्रभावित होने वालों में ज्यादातर इजरायल, तुर्की, ईरान, ग्रीस, अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी के यूजर बताए गए हैं। बालिक ने बताया कि वह गत दो माह से यूजर्स को सीधे अलर्ट कर रहे थे। लेकिन जब ट्विटर को इसकी जानकारी हुई तो माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफार्म ने उनके इस प्रयास को गत 20 दिसंबर को रोक दिया। बालिक ने यूजर्स को अलर्ट करने के लिए एक वाट्सएप ग्रुप बना रखा था।

ट्विटर ने पिछले हफ्ते यह माना था कि उसके एक एप में बग है, जिससे एंड्रायड यूजर्स के डाटा लीक हो सकते हैं। ट्विटर ने यूजर्स को एप अपडेट करने की सलाह दी थी। गत फरवरी में बड़ी संख्या में ट्विटर के एंड्रायड यूजर्स के निजी ट्वीट सार्वजनिक हो गए थे।

भारत और ईरान रणनीतिक चाबहार परियोजना में तेजी लाने पर सहमत

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारत और ईरान रणनीतिक चाबहार परियोजना को पूरा करने में तेजी लाने पर सहमत हुए और विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अपने ईरानी समकक्ष जवाद जरीफ के साथ पारस्परिक हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक बातचीत की। चाबहार बंदरगाह को भारत, ईरान और अफगानिस्तान संयुक्त रूप से विकसित कर रहे हैं। इस परियोजना को तीन देशों के मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार के सुनहरे अवसरों के लिए प्रवेश द्वार माना जाता है। उन्होंने जरीफ के साथ 19वें संयुक्त आयोग की बैठक की सह-अध्यक्षता की। उनके ईरानी राष्ट्रपति हसन रुहानी से मुलाकात करने की भी उम्मीद है। जयशंकर ने बैठक के बाद ट्वीट किया कि सह-अध्यक्ष विदेश मंत्री जरीफ के साथ भारत-ईरान संयुक्त आयोग की सार्थक बैठक संपन्न हुई। उन्होंने कहा, अपने सहयोग के पूरे आयाम की समीक्षा की। अपनी चाबहार परियोजना की गति तेज करने पर सहमत हुए।

विश्व प्रसिद्ध नॉट्रे ड्रैम चर्च को बचाने की सिर्फ 50 फीसद गुंजाइश

द रीव टाइम्स ब्यूरो

फ्रांस के प्रसिद्ध नॉट्रे ड्रैम कैथेड्रल चर्च की इमारत अब भी इतना कमजोर है कि इसे बचा पाने की गुंजाइश केवल 50 फीसद है। यही नहीं करीब 200 साल में पहली बार इस चर्च में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर प्रार्थना सभा का आयोजन नहीं हुआ। इसकी जानकारी इस ऐतिहासिक चर्च के पादरी ने दी।

बता दें कि 16 अप्रैल को आग लगने से 850 साल पुराना चर्च पूरी तरह तबाह हो गया। मोनसीनेर पैत्रिक शावेत ने कहा कि चर्च के जीर्णोधार का काम 2021 तक शुरू होने की संभावना नहीं है। उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के बाद इस चर्च में क्रिसमस नहीं मनाये जाने पर दुख जताया।

क्रिसमस की पूर्व संध्या उन्होंने कहा कि आज यह इमारत खतरे से बाहर नहीं है।

आज हम कह सकते हैं कि शायद 50 प्रतिशत संभावना है कि इसे बचाया जा सकेगा। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों इसे 2024 तक इसका जीर्णोद्धार करना चाहते हैं। इस दौरान पेरिस में ओलंपिक होगा। हालांकि, इस समय सीमा को लेकर विशेषज्ञों ने आशंका जाहिर की है।

कैथोलिक समुदाय के लोग नोट्रे-डेम के बजाय नजदीक के चर्च सेंट-जर्मेन आई ऑक्सेरोइस में भारी मन से एकत्रित हुए।

कजाकिस्तान में 100 लोगों को ले जा रहा विमान क्रैश

द रीव टाइम्स ब्यूरो

कजाकिस्तान में 98 लोगों को ले जा रहा विमान 26 दिसंबर को क्रैश हो गया है। समाचार एजेंसी रॉयटर के मुताबिक, अलमाटी एयरपोर्ट के पास यह हादसा हुआ है। हादसे के दिन ही 15 लोगों की मौत हो गई। उड़ान भरने के फौरन बाद यह हादसा हुआ। विमान एक इमारत से टकराकर कई हिस्सों में टूट गया। घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान जारी है। अधिकारियों ने बताया कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। विमान में 93 यात्री और पांच क्रू मेंबर सवार थे। फिलहाल, विमान हादसे के कारणों का पता नहीं चल सका है। समाचार एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक, स्थानीय समय के अनुसार 27 दिसंबर सुबह 7.05 बजे अल्माटी एयरपोर्ट से टेक अहफ के कुछ ही मिनट बाद बेक एयर फ्लाइट 2100 का संपर्क टूट गया। अल्माटी हवाई अड्डे के अधिकारियों ने बताया कि सुबह 7 बजकर 22 मिनट पर विमान ने अपना संतुलन खो दिया। विमान उड़ान भरने के तुरंत बाद कंक्रीट के बाड़े और दो मंजिला मकान से टकरा गया। समाचार एजेंसी रॉयटर ने बताया है कि हादसे में गंभीर रूप से घायल 66 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अल्माटी हवाईअड्डे ने अपने फेसबुक पेज पर बताया कि विमान में कोई आग नहीं लगी। हादसे के तुरंत बाद राहत और बचाव कार्य शुरु हो गया। विमान नूर-सुल्तान जा रहा था।

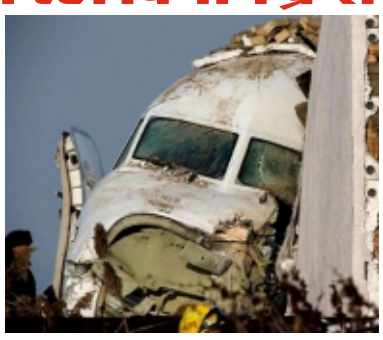

संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद के खिलाफ मोर्चेबंदी में भारत ने मनवाया लोहा, बैकफुट पर रहा पाक

द रीव टाइमस ब्यूरो

भारत ने 10 साल के अथक प्रयासों के बाद 2019 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मुहम्मद सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित कराने में सफलता हासिल की। यह संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद-विरोधी मोर्चे पर भारतीय नेतृत्व की अहमियत को बताता है। भारत ने जलवायु परिवर्तन और टिकाऊ विकास के मुद्दे पर भी आगे बढ़कर पूरी दुनिया का नेतृत्व किया। आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई और आतंकियों को न्याय के कठघरे तक पहुंचाने की इसकी प्रतिबद्धता को वर्ष 2019 के ऐतिहासिक लम्हों के तौर पर याद किया जाएगा। जैश-ए-मुहम्मद द्वारा 14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर हमले ने सभी को आक्रोशित कर दिया और अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने भी इसकी कड़ी निंदा की। पहली बार संयुक्त राष्ट्र की शक्तिशाली सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों ने एक बयान जारी किया। उक्त बयान में पुलवामा में घृणित और कायराना आत्मघाती हमले की सख्त लहजे में निंदा की गई। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे।

फिलीपींस में तबाही का मंजर छोड़ गुजरा तूफान PHANFONE

द रीव टाइमस ब्यूरो

क्रिसमस के मौके पर फिलीपींस में आया तूफान तो शांत हो गया लेकिन तबाही का मंजर अभी शेष है। इस तूफान के कारण मरने वालों की संख्या 28 पहुंच गइ। यह संख्या और भी बढ़ सकती है। तूफान के साथ 200 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवा सूदूर गांवों व लोकप्रिय पर्यटन स्थलों से होकर गुजरी है। अधिकारियों ने मृतकों के संख्या की पुष्टि करते हुए बताया कि आंकड़ा 28 पर पहुंच गया। स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी सूचना के अनुसार, बुरी तरह प्रभावित इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल फोन नेटवर्क काट दिया गया। तूफान के कारण करंट लगने के बाद डूबने से अधिकतर लोगों की मौत हो गई। फिलीपींस कैथलिक बहुल देश है, और इस तूफान ने यहां के सैंकड़ों-हजारों लोगों की क्रिसमस फेस्टिवल के रंग में भंग डाल दिया। इसके कारण दस हजार से अधिक लोग बेघर हो गए। इन्हें राहत शिविरों में ले जाया गया। अपने सफेद सैंड बीच के लिए प्रसिद्ध बोराके आइलैंड भी इस तूफान की चपेट में आने से नहीं बच सका। बता दें कि एक साल में यहां एक मिलियन से अधिक लोग पर्यटन के लिए आते हैं।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

करंट अफेयर्स

- गृह मंत्री अमित शाह ने जिस शहर में भारत वंदना पार्क के शिलान्यास समारोह में हिस्सा लिया – नई दिल्ली
- वह सीबीआई के अधिकारी जिसने नैसकॉम – डीएससीआई का 'इंडिया साइबर कॉप ऑफ द ईयर 2019' पुरस्कार जीता है – बी पी राजू
- प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिखित जिस पुस्तक का हाल ही में ब्रेल संस्करण लॉच किया गया – एग्जाम वॉरियर्स
- एशियाई विकास बैंक ने जिस देश को ऊर्जा दक्षता निवेश में विस्तार के लिए 250 मिलियन डॉलर का ऋण जारी किया है – भारत
- हाल ही में जिस भारतीय स्पिनर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दो बार हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं – कुलदीप यादव
- जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुरक्षित पेय की आपूर्ति के लिए जलसाथी कार्यक्रम शुरू किया – उड़ीसा
- गोवा मुक्ति दिवस जिस दिन मनाया जाता है – 19 दिसंबर
- हाल ही में जिस राज्य में मौजूद 'सबरूम' नामक स्थान पर इस राज्य का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए जाने की घोषणा की गई है – त्रिपुरा
- जिसे हाल ही में अंग्रेजी का साहित्य अकादमी सम्मान – 2019 दिए जाने की घोषणा की गई है – शशि थरूर
- जिसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार – 2019 दिए जाने की घोषणा की गई है – नन्दकिशोर आचार्य
- अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन के अनुसार विश्व में वैज्ञानिक लेख प्रकाशित करने के मामले में भारत विश्व में जिस स्थान पर है – तीसरा स्थान
- कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना तेलंगाना में जिस नदी पर स्थित एक बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजना है – गोदावरी नदी
- हाल ही में बांग्लादेश और जिस देश के बीच होने वाली संयुक्त नदी आयोग की बैठक को बांग्लादेश द्वारा निरस्त कर दिया गया – भारत
- हाल ही में जिस कृषि विश्वविद्यालय ने व्यावसायिक खेती के लिये प्रोसेसिंग – ग्रेड व्हाइट ओनियन किस्म विकसित की है – पंजाब कृषि विश्वविद्यालय
- भारत के जिस पूर्व क्रिकेटर को इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सत्र हेतु किंग्स इलेवन पंजाब का बल्लेबाजी कोच बनाया गया है – वसीम जाफर
- हाल ही में जिस देश ने महात्मा गांधी के आदर्शों को शाश्वत बनाए रखने के लिए गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार आरंभ करने की घोषणा की – पुर्तगाल
- फोर्ब्स इंडिया द्वारा वर्ष 2019 के लिए जारी टॉप – 100 भारतीय सेलेब्रिटीज की सूची में जिसे पहला स्थान मिला है – विराट कोहली
- DRDO द्वारा हाल ही में जिस आर्टिलरी मिसाइल सिस्टम का ओडिशा के चांदीपुर रेंज से सफल परिक्षण किया गया – पिनाका मार्क – 2
- अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस जिस दिन मनाया जाता है – 20 दिसंबर
- भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल द्वारा हाल ही में जिस नाम से बड़े पैमाने पर एंटी – हाईजैकिंग अभ्यास किया गया – अपहरण
- चेन्नई में भारत के खिलाफ पहले वनडे में धीमी गति से ओवर फेंकने को लेकर जिस क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों पर मैच फीस का 80 प्रतिशत जुर्माना लगा है – वेस्टइंडीज
- मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2019 – 20 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान घटाकर जितने प्रतिशत कर दिया है – 4.9 प्रतिशत
- हाल ही में जिसने अंटार्कटिक आइस मैराथन को पूरा करने वाले अब तक के सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं – रॉय जॉर्जन स्वेनिंगसेन
- वह देश जिसके विदेश मंत्री ने 72 साल पुराने त्रिपक्षीय समझौते की समीक्षा की मांग की है – नेपाल
- चीन और जिस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से उत्तर कोरिया पर लगे मुख्य प्रतिबंधों को हटाने की मांग की है – रूस
- हाल ही में जिसने दक्षिण एशियाई साहित्य में डीएससी पुरस्कार 2019 जीता है – अमिताभ बागची
- जिस देश में सेवारत लगभग 850 भारतीय शांति सैनिकों को 'संयुक्त राष्ट्र पदक' से सम्मानित किया गया – दक्षिण सूडान
- अल्पसंख्यक अधिकार दिवस जिस दिन मनाया जाता है – 18 दिसंबर
- डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर से दो जिस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का हाल ही में सफल परीक्षण किया – ब्रह्मोस
- घरौंदा और लावारिस जैसी फिल्मों में नजर आ चुके जिस दिग्गज अभिनेता का 92 साल की उम्र में पुणे (महाराष्ट्र) के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया – श्रीराम लागू
- केंद्र सरकार ने फास्टैग को अनिवार्य रूप से लागू करने की अंतिम तिथि को जब तक के लिए बढ़ा दिया है – 15 जनवरी
- हाल ही में जिस देश की सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वहां प्रत्येक वर्ष हर घर में 260 किलो खाना बर्बाद होता है – सऊदी अरब
- हाल ही में जिस देश के एक विश्वविद्यालय ने 100 भाषाएं बोलने और समझने वाला एक रोबोट तैयार किया है – ईरान
- हाल ही में पहली बार जिस अर्धसैनिक बल ने अपने कर्मियों के लिए मैट्रोमोनियल पोर्टल शुरू किया है – ITBP
- पीटर स्नेल जिस खेल से संबंधित थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है – लंबी दूरी के धावक
- हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का यह स्थान है – 112
- जिसे हाल ही में भारत का अगला थलसेना प्रमुख चुना गया है – मनोज मुकुंद नरवाने
- भारत और जिस देश के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास 'सूर्यकिरण' आयोजित किया गया – नेपाल
- जिसने हाल ही में वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के वरिष्ठ एयर स्टाफ ऑफिसर के रूप में पदभार संभाला है – आर जे डकवर्थ
- सार्वजनिक स्थानों को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाने के लिए आरंभ किये गये जिस अभियान की डेडलाइन को बढ़ाकर मार्च 2020 कर दिया गया है – सुगम्य भारत
- अमेरिकी रेटिंग एजेंसी मूडीज इंवेस्टर्स सर्विस ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान साल 2019 के लिए घटाकर जितने फीसदी कर दिया है – 5.6 फीसदी
- हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने केरल और जिस राज्य के बीच मुल्लापेरियार बांध से संबंधित मुद्दे के समाधान हेतु तीन सदस्यीय पर्यवेक्षी समिति का गठन किया है – तमिलनाडु
- हाल ही में पारित केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय बिल, 2019 द्वारा जितने संस्कृत संस्थानों को केंद्रीय विश्विद्यालय का दर्जा दिया गया है – चार
- मार्च 2020 में 36वें अंतरराष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कॉन्ग्रेस की मेजबानी जो देश करेगा – भारत
- हाल ही में नीदरलैंड के अध्ययनकर्तृताओं द्वारा किये गए एक अध्ययन के अनुसार भारत, चीन और जिस देश से होकर बहने वाली सिंधु तथा उसकी सहायक नदियाँ दुनिया के सबसे कमजोर 'वाटर टावर्स' में से एक हैं – पाकिस्तान
- राष्ट्रीय उर्जा संरक्षण दिवस जिस दिन मनाया जाता है – 14 दिसंबर
- साल 1971 के भारत – पाक युद्ध में भारतीय सेना की जीत के उपलक्ष्य में जिस दिन विजय दिवस मनाया जाता है – 16 दिसंबर
- भारत की सिफारिश पर जिस दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने की घोषणा की गई है – 21 मई
- जिसे हाल ही में मिस वर्ल्ड 2019 चुना गया है – टोनी एन सिंह
- हाल ही में ब्रिटिश आम चुनाव जीतने वाले बोरिस जॉनसन जिस पार्टी से संबंधित हैं – कंजर्वेटिव पार्टी
- राष्ट्रीय किसान दिवस जिस दिन मनाया जाता है – 23 दिसंबर
- 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में जिसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है – अंधाधुन
- पुस्तक 'R N Kao: Gentleman Spymaster' जिसके द्वारा लिखी गई है – नितिन गोखले
- वह टीम जिसने हाल ही में पहली 'बिग बाउट इंडियन बॉक्सिंग लीग' का खिताब जीता है – गुजरात जाइंटस
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में जिस विधानसभा सदस्य की सदस्यता फर्जी दस्तावेज के आधार पर चुनाव लड़ने के कारण रद्द कर दी है – अब्दुल्ला आजम खान
- हाल ही में जिस राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में गैंडों को लाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है – उत्तराखंड
- फुटबॉल की नियामक संस्था – फीफा ने जिस देश को लगातार दूसरी बार वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल टीम के पुरस्कार से सम्मानित किया है – बेल्जियम
- भारतीय मूल के जिस अमेरिकी नागरिक को अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन का निदेशक बनाया गया है – सेतुरमण पंचनाथन
- वह देश जिसके राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनल ने हाल ही में 43 साल बाद देश में प्रधानमंत्री नियुक्त किया है – क्यूबा
- भारत में प्रतिवर्ष जिस दिन 'राष्ट्रीय गणित दिवस' मनाया जाता है – 22 दिसंबर
- भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जिस दिन मनाया जाता है – 24 दिसंबर
- विश्व आर्थिक फोरम की 50वीं वार्षिक बैठक का आयोजन स्विट्जरलैंड के जिस शहर में जनवरी 2020 में किया जायेगा – दावोस
- अपोलो हॉस्पिटल समूह की जिस संयुक्त प्रबंध निदेशक ने देश के प्रमुख उद्योग मंडल फिक्की के अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है – संगीता रेड्डी
- वह देश जिसके पूर्व प्रधानमंत्री चार्ल्स मिशेल ने यूरोपियन काउंसिल तथा यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है – बेल्जियम
- वह राज्य कैबिनेट जिसने हाल ही में वायु प्रदूषण से निपटने हेतु एक बड़ा कदम उठाते हुए इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 को मंजूरी दे दी है – दिल्ली कैबिनेट
- हाल ही में आठ पश्चिमी अफरीकी देशों ने कॉमन करेंसी को यह नाम दिया है – ECO
- वह महिला भारोत्तोलक जिसने कतर इंटरनेशनल कप में कांस्य पदक जीतने के साथ दो नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाए – राखी हलदर
- हाल ही में संपन्न हुए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति चुनावों में जिसे जीत मिली है – अशरफ गनी
- जिस संस्था द्वारा प्रकाशित शोध पत्र में कहा गया है कि प्रत्येक सात में से एक भारतीय मानसिक अस्वस्थता से ग्रसित है – लांसेट पेपर
- जिसे हाल ही में विदेश सचिव नियुक्त किया गया है – हर्षवर्धन श्रृंगला

हिमाचल सामान्य ज्ञान

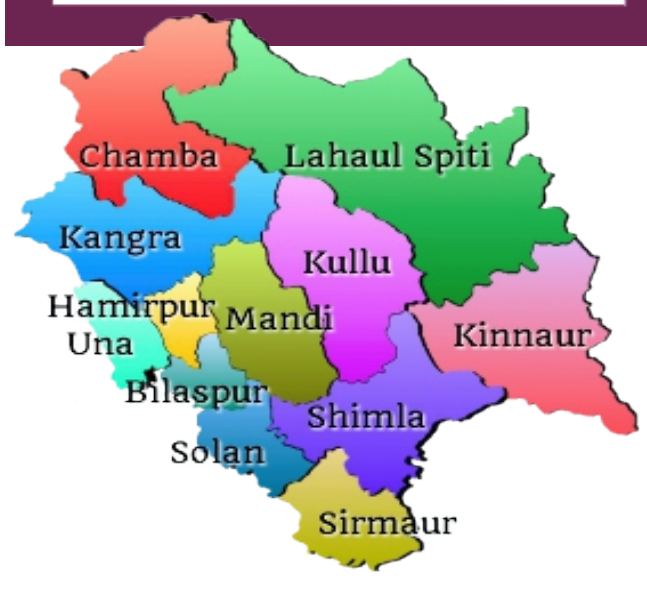

- मनाली में हिडिंबा मंदिर का निर्माण किसने और कब करावाया था – राज बहादुर ने 1553 में
- आदि ब्रह्मा का मंदिर कहां पर है – कुल्लू में
- लाहौल – स्पीति में बना त्रिलोकीनाथ मंदिर किस शैली में बना है – कश्मीर – कनौज
- लाहौल स्पीति के तुपचिंलिंग गांव में बने गुरू घंटाल गोंपा में स्थित अवलोकितेश्वर मूर्ति कौन सी सदी की है – 8वीं सदी की
- गैमूर मोनास्ट्री में कौन सी देवी की मूर्ति है – मरीची वज्रवाही, यह 11–12वीं शताब्दी से संबंधित है और कशमीरी स्टाइल में है
- भरमौर में लक्षणा देवी मंदिर जो अश्टधातु से बना है उसे किस कारीगर ने बनाया था – गुग्गा, यह मंदिर मेरू वर्मन ने बनवाया था
- चंबा के हरीराय मंदिर से मूर्ति कब चोरी हुई थी – 1971 में
- हाटकोटी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था – बीर प्रकाश ने
- मसरूर मंदिर का निर्माण कब किया था – 8वीं शताब्दी में
- मंडी का पराशर मंदिर कब और किसने बनाया था – 1346 में राजा बान सेन ने

आर्थिक सर्वेक्षण

- परिवहन निगम के स्मार्ट कार्ड पर कितनी छूट मिलती है और यह कब से कब तक मान्य है – 10 प्रतिशत छूट के साथ यह कार्ड 31 अक्तूबर से 31 मार्च तक मान्य होता है
- निगम की सामान्य बसों में महिलाओं को कितने प्रतिशत छूट दी जाती है – 25 प्रतिशत
- सम्मान कार्ड का संबंध किससे है और इस पर कितनी छूट है – सम्मान कार्ड वरिष्ठ नागरिकों का बनाया जाता है और इसमें किराए पर 30 फीसदी छूट दी जाती है।
- फेम इंडिया योजना क्या है – इलेक्ट्रिक बस योजना, इसके तहत शिमला को 50 बसें देने का प्रावधान है।
- हिमाचल में कब तक 100 फीसदी इलेक्ट्रिक बसें चलाने का लक्ष्य है – 2030 तक
- हिमाचल प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी – 1972 में
- हिमाचल से प्रकाशित होने वाले हिमप्रस्थ पत्रिका का प्रथम प्रकाशन कब प्रकाशित हुआ – 1955 में
- सोलन फल एवं सब्जीमंडी को ई – नाम योजना के साथ कब जोड़ा गया – 8 मई 2016
- हाल ही में किन दो राज्यों के बीच यमुना नदी के पानी को लेकर समझौता हुआ है – हिमाचल और दिल्ली के बीच
- शिमला के रिज मैदान पर क्राइस्ट चर्च का निर्माण किसने करवाया था – एंग्लीकेन ब्रिटिश कम्युनिटी
- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में हिमाचल को कितने पुरस्कार मिले हैं – तीन पुरस्कार और 65.15 करोड़ की राशि
- हिमाचल के सोलन में मशरूम को लेकर कब कार्य शुरू हुआ था – 1961 में, जबकि 10 सितंबर 1997 को मशरूम सिटी का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान केंद्र 8 जून 1983 को सोलन में स्थापित किया गया।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

मत्स्य पालन

प्रदेश में मत्स्य पालन कार्यक्रम को बढ़ावा देने व मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के साथ–साथ स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने की दृष्टि से प्रदेश सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके साथ ही कुछ योजनाएं केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित हैं। इन योजनाओं के तहत मत्स्य कृषक विकास अभिकरणों की स्थापना की गई है। द रीव टाइम्स के इस अंक में हम केंद्र और राज्य सरकार की ओर से हिमाचल में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दे रहें हैं।

जनजातीय क्षेत्र में मत्स्य विकास योजनाएं

मात्स्यिकी विभाग द्वारा जन जातीय क्षेत्र में एक पक्के ट्राउट युनिट के निर्माण के लिए कुल लागत मुल्य 1 लाख रूपये पर 40 प्रतिशत की दर से अधिकतम 40 हजार रूपये की अनुदान सहायता देने का प्रावधान है। इसके अलावा मछली उत्पादन के पहले वर्ष में मछली बीज एवं खुराक पर कुल लागत 1.50 लाख रूपये तक 40 की दर से अधिकतम 60 हजार रूपये के अनुदान का प्रावधान है।

जानकारी के मुताबिक एक वर्ष में एक युनिट में रेनबो ट्राउट फार्मिंग से 1 टन मछली ली उत्पादन होता है, जिससे मत्स्य पालक को 1.00 लाख रूपये का शुद्ध लाभ मिलता है ।

राज्य सरकार की योजनाएं

दुर्घटना बीमा योजना

प्रदेश के पंजीकृत मत्स्य पालन पालकों के लिए मछुआरों /मत्स्य पालकों की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर और स्थाई रूप से विकलांग होने की स्थिति में 2 लाख रूपये का निशुल्क बीमा कवच प्रदान किया जाता है। वहीं, आंशिक रूप से विकलांग होने की स्थिति में 1 लाख रूपये व चिकित्सा उपचार हेतु 10,000 रूपये का प्रावधान।

मछुआरा जोखिम निधि योजना

जलाशयों में कार्यरत मछुआरों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण मत्स्य उपकरणों को हुए नुकसान की भरपाई हेतु उपकरणों की निर्धारित कीमत की 33 प्रतिशत सहायता।

बंद सीजन राहत भत्ता योजना

जलाशय के मछुआरों को दो माह के वर्जित काल के दौरान 1800 रूपये की सहायता।

- अनुसूचित जनजाति के लिए कबायली क्षेत्र अथवा इससे बाहर के क्षेत्रों में तालाब निर्माण हेतु 5 हजार रूपये तक का अनुदान।

अनुसूचित जाति उप योजना

इस योजना क तहत अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव में 1–0 लाख रूपये की राशि से सामुदायिक तालाब निर्माण का प्रावधान है। सामुदायिक तालाब निर्माण के बाद ग्राम पंचायत के द्वारा गांव के ही किसी अनुसूचित जाति से संबंधित लाभार्थी को मछली पालन हेतु 5 वर्षों के लिए पट्टे पर दिया जाता है।

केंद्र सरकार की योजनाएं

मछली तालाब निर्माण

4 लाख रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से तालाब निर्माण के खर्चे पर सामान्य जाति के लोगों को निर्माण राशि का 20 प्रतिशत अनुदान के रूप में किसानों को दिया जाता है। जिसकी अधिकतम सीमा 80 हजार रूपये प्रति हैक्टेयर है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मत्स्य पालकों के लिए अनुदान की दर 25 प्रतिशत है तथा अनुदान की अधिकतम सीमा एक लाख रूपये प्रति हैक्टेयर है।

पुराने जल क्षेत्रों (तालाबों) की मुरम्मत

सामान्य जाति के लोगों को 15,000 रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से अनुदान सहायता प्रदान की जाती है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के मत्स्य पालकों के लिए यह राशि 18,750 रूपये प्रति हैक्टेयर है।

प्रथम वर्षीय अनुदान

मत्स्य पालन अपनाने पर प्रथम वर्ष मछली बीज, खाद, खुराक आदि पर किए जाने वाले व्यय में सामान्य जाति के लोगों को 20 प्रतिशत या 10 हजार रूपये प्रति हैक्टेयर है, जो कम हो, अनुदान दिया जाता है। अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिए मतस्य पालकों के लिए यह राशि 12 हजार 500 प्रति हैक्टेयर है।

मछली आहार संयत्र

मछली आहार के लिए आहार संयत्र स्थापित करने की अनुमानित निर्माण राशि 7.5 लाख रूपये जो कि भवन, मशीनरी व कलपुर्जों का खर्चा है, जिसमें 20 प्रतिशत की दर से कुल अनुदान 1.5 लाख रूपये दिया जाता है।

कार्प हैचरी निमार्ण

ताजे पानी की मछली बीज उत्पादन के लिए 10 मिलियन फ्राई की क्षमता वाली हैचरी के लिए अनुमानित लागत राशि 16 लाख रूपये की 10 प्रतिशत की दर से 1.60 लाख रूपये अनुदान की सुविधा प्राप्त है।

- सजावटी मछली पालकों के लिए हैचरी सहित समेकित यूनिटों के लिए 1.50 लाख रूपये की अधिकतम सीमा के साथ 10 प्रतिशत की दर से अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।

योजनाओं की जानकारी

मछली पालन से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी जिला स्तर पर तैनात विभागीय अधिकारियों और कार्यालयों में फोन पर अथवा मछली पालन केंद्र की वेबसाइट पर जाकर प्राप्त की जा सकती है।

यहां करें संपर्क

मत्स्य भवन, मात्स्यिकी निदेशालय, हिमाचल प्रदेश, चंगर सैक्टर-बिलासपुर-174001 फोन/फैक्सः 01978–224068 ई मेलः fisheries-hp@nic.in

वैबसाईट : hpfisheries.nic.in

मत्स्य आखेट का केंद्र बनेगा कोल डेम एंगलिंग हट्स भी किए जाएंगे स्थापित

प्रदेश में जल आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार वर्ष-2020 में बिलासपुर स्थित कोल डैम जलाशय में खेल और मत्स्य आखेट गतिविधियां आरंभ करेगी। प्रदेश का मत्स्य विभाग कोल डैम जलाशय में स्पोर्ट्स फिश महाशीर के बीजों का भंडारण और उत्पादन को बढ़ावा देगा। ताकि देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। वर्तमान में मानव निर्मित जलाशयों में कॉर्प, सिल्वर कॉर्प, महाशीर और ग्रास कॉर्प मछलियों की प्रजातियां पाली जा रही हैं।

मत्स्य विभाग ने बिलासपुर, सोलन, मंडी और शिमला जिलों में लगभग 1302 हेक्टेयर जल संग्रह क्षेत्र में स्पोर्ट्स फिशरीज आरंभ करने की योजना बनाई है। कोल डैम जलाशय में एंगलिंग हट्स भी स्थापित की जाएंगी। कोल डैम में वर्ष 2018–19 में 5.595 मीट्रिक टन मछली का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। राज्य सरकार ने कोल डैम के निर्माण के दौरान विस्थापित हुए परिवारों को वाणिज्यिक मत्स्य उत्पादन के माध्यम से जीविकार्जन के अवसर प्रदान किए हैं।

वर्तमान में कोल डैम में 350 मछुआरे मछलियों का उत्पादन कर अपनी जीविका अर्जित कर रहे हैं। सतलुज नदी में साईजोथोरैक्स (गुगली मछली) महाशीर, छोटी कॉर्प, कैट फिश और ऊपरी क्षेत्रों में ट्राउट मछली पाई जाती है। गोबिंद सागर से भी सिल्वर कॉर्प मछली प्रजनन के लिए सतलुज नदी के ऊपरी क्षेत्र की ओर जाती है।

मत्स्य पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि मत्स्य विभाग ने इस जलाशय में कोल बिलासपुर बेरल, सोलन, सुन्नी शिमला में तीन मत्स्य लैंडिंग सेंटर स्थापित किए हैं। इनमें सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। सहकारी सभाओं के सदस्यों की ओर से पकड़ी गई मछलियां ठेकेदारों को दे दी जाती हैं। ताकि उनका इन केंद्रों में विपणन किया जा सके। गोबिंद सागर जलाशय में भी 28 फिश केज स्थापित किए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना (मुफ्त बेबी किट) पूरे प्रदेश में शुरू की गई है। इस योजना का कैसे लाभ मिलेगा, आवेदन फॉर्म 2019 प्रक्रिया, पात्रता आदि सभी विषयों की जानकारी हम आपको द रीव टाइम्स के इस अंक दे रहे हैं। मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना की घोषणा राज्य सरकार द्वारा मार्च 2018 में की गई थी। योजना के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चों को सरकार की ओर से बेबी किट देने का प्रावधान है। इसमें नवजात शिशु की जरुरत का पूरा सामान दिया जाता है। प्रदेश में कई बच्चे ऐसे है जो पोषण के अभाव में जन्म लेते ही मर जाते है, सरकार इस मृत्यु दर को कम करना चाहती है। केंद्र सरकार ने नौकरीपेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश प्रोत्साहन योजना चालू की थी, जिसमें अब कुछ बदलाव के साथ इसे नए तरीके से लागु किया गया है।

योजना नाम	मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना
प्रदेश	हिमाचल प्रदेश
योजना का लाभ	नवजात शिशु को 1500 रू. की बेबी किट
प्रोत्साहन राशि	700 रूपये नवजात की मां को
घोषणा	मार्च 2018
योजना की शुरुवात	दिसम्बर 2018
देखरेख	स्वास्थ्य मंत्रलय

मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना का उद्देश्य

भारत देश में अभी भी बहुत से गाँव है, जहाँ घर पर ही महिला बच्चे को जन्म देती है, इससे बच्चे और माँ दोनों को खतरा होता है। सरकार अस्पताल में डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए यह योजना लेकर आई है, ताकि अधिक से अधिक लोग बच्चे का जन्म अस्पताल में करवाएं। इसके साथ ही गरीबी के चलते वे बच्चे को सही पोषण और उनकी जरुरत का समान मुहैया नहीं करा पाते है। सरकार ऐसे गरीब परिवार की इस योजना के द्वारा मदद करेगी।

फ्री बेबी किट-नवजात शिशुओं के लिए मुफ्त में किट दी जाती है। इसमे कुल 15 आइटम होती है जो कि नवजात की उचित देख रेख के लिये उपयोग में लाई जाती है। इसमें बेबी सूट, बनियान, वेलवेट के कपड़े, ग्लव्स (हाथ पोश), मोजे, मसाज करने के लिए तेल, 6 नैपी, मच्छरदानी, कम्बल, खिलौना षामिल है। इसके अलावा नवजात की माँ के लिए टूथपेस्ट, टूथब्रश, नहाने का साबुन, वैसलीन और सैनिटरी नैपकिन।

बेबी केयर किट का समान कुल 1500 रूपए का होता है। सरकार ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना के तहत टारगेट रखा है कि हर साल लगभग 1 लाख नवजात बच्चा और उसकी माँ को इस योजना का लाभ पहुँचाया जायेगा।

मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना पात्रता

हिमाचल राज्य के निवासी-मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना का लाभ सिर्फ उन्ही महिला को मिलेगा, जो हिमाचल प्रदेश के ही रहने वाले है। हिमाचल का मूल निवासी पत्र होना अनिवार्य है, तभी वह महिला इस योजना का लाभ उठा सकती है।

सरकारी अस्पताल में जन्मे – योजना का लाभ उन्हीं बच्चों को मिलेगा, जो सरकारी अस्पताल में जन्म लेते है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जन्मे या घर में जन्मे बच्चे और उनकी माँ को 700 रूपए की सहायता

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के दायरे में कौन सी खेती आती है?

PMFBY योजना वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी बीमा सुरक्षा प्रदान करती है

हर साल प्राकृतिक आपदा के चलते भारत में किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। बाढ़, आंधी, ओले और तेज बारिश से उनकी फसल खराब हो जाती है। उन्हें ऐसे संकट से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) शुरू की है। इसे 13 जनवरी 2016 को शुरू किया गया था।

इसके तहत किसानों को खरीफ की फसल के लिये 2 फीसदी प्रीमियम और रबी की फसल के लिये 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है।

PMFBY में प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम को बहुत कम रखा गया है। इससे PMFBY तक हर किसान की पहुंच बनाने में मदद मिली है।

PMFBY योजना वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें हालांकि किसानों को 5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है।

भारतीय कृषि बीमा कंपनी (एआईसी या AIC) इस योजना को चलाती है।

योजना के उद्देश्य

प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को बीमा कवर और वित्तीय सहायता देना। किसानों की खेती में रुचि बनाये रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना। किसानों को कृषि में इन्नोवेशन एवं आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। कृषि क्षेत्र में ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

कहां से लें PMFBY का फॉर्म?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के लिए ऑफलाइन (बैंक जाकर) और दूसरा ऑनलाइन, दोनों तरीके से फॉर्म लिए जा सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए आप इस लिंक पर जा सकते हैं- http://pmfby-gov-in/

अगर आप फॉर्म ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना (PMFBY) का फॉर्म भर सकते हैं।

PMFBY के लिए किन दस्तावेजों की है जरुरत?

- किसान की एक फोटो
- किसान का आईडी कार्ड (पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड)
- किसान का एड्रेस प्रूफ (ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड)

अगर खेत आपका अपना है तो इसका खसरा नंबर, खाता नंबर का पेपर साथ में रखें।

खेत में फसल की बुवाई हुई है, इसका सबूत पेश करना होगा।

इसके सबूत के तौर पर किसान पटवारी, सरपंच, प्रधान जैसे लोगों से एक पत्र लिखवा ले सकते हैं।

- अगर खेत बटाई या किराए पर लेकर फसल की बुवाई की गयी है, तो खेत के मालिक के साथ करार की कॉपी की फोटोकॉपी जरूर ले जायें।
- इसमें खेत का खाता, खसरा नंबर साफ तौर पर लिखा होना चाहिए।
- फसल को नुकसान होने की स्थिति में पैसा सीधे आपके बैंक खाते में पाने के लिए एक रद्द चेक लगाना जरूरी है।

PMFBY के लिए ध्यान रखने वाली कुछ अन्य बातें

- फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर आपको **PMFBY** का फॉर्म भरना जरूरी है।
- फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो।
- दावा भुगतान में होने वाली देरी को कम करने के लिए फसल काटने के आंकड़े जुटाने एवं उसे साईट पर अपलोड करने के लिए स्मार्ट फोन, रिमोट सेंसिंग ड्रोन और जीपीएस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है।
- कपास की फसल के बीमा का प्रीमियम पिछले साल प्रति एकड़ 62 रुपये था, जबकि धान की फसल के लिए 505.86 रुपये, बाजरा के लिए 222.58 रुपये और मक्का के लिए यह 202.34 रुपये प्रति एकड़ था।

विशेष वेब पोर्टल और मोबाइल एप

भारत सरकार ने हाल ही में बेहतर प्रशासन, विभिन्न एजेंसियों के बीच सही तालमेल, इस बारे में जानकारी के प्रचार-प्रसार और प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए एक बीमा पोर्टल शुरू किया है।

एंडॉयड आधारित फसल बीमा एप भी शुरू किया गया है, जो फसल बीमा, कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग (डीएसी एवं परिवार कल्याण) की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

क्र.सं.	फसल	किसान द्वारा देय अधिकतम बीमा प्रभार (बीमित राशि का प्रतिशत)
1	खरीफ	2.0%
2	रबी	1.5%
3	वार्षिक वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलें	5%

प्रधानमंत्री धन लक्ष्मी योजना ऑनलाइन आवेदन, एप्लीकेशन फॉर्म 2019, मिलेंगे 5 लाख

द रीव टाइम्स के इस अंक मे इस बर केंद्र सरकार की योजना,"प्रधानमंत्री धन लक्ष्मी योजना" जो लॉन्च हुई है उसकी बात करेंगे इसमें सरकार आपको सीधे ₹5 लाख का लाभ देगी और यह महिलाओं के लिए विशेष तौर पर है। कैसे आपको फॉर्म भरना है और इसके लिए आवेदन कैसे करेंगे।

प्रधानमंत्री धन लक्ष्मी योजना

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, प्रधानमंत्री धन लक्ष्मी योजना में महिलाओं को विशेष लाभ देने की घोषणा की गई है।

प्रधानमंत्री धन लक्ष्मी योजना जिसमें आपको 5 लाख भुगतान करने की बात कही गई है।यह योजना पूरे भारत में लागू हुई है। विशेष तौर पर गरीब और मध्यम वर्ग की महिलाओं को निर्भर बनाना इस योजना का लक्ष्य है। यह योजना केंद्र सरकार की ओर से लांच की गई है इसमें महिलाओं के खाते में सीधे ₹5 लाख ट्रांसफर किए जाएंगे। अपना नया स्वरोजगार शुरू करने के लिए नगद राशि देने का भुगतान किया जाने का प्रावधान है।

इस योजना के तहत कुछ महिलाओं को इसका लाभ भी मिल चुका है और कुछ अभी बाकी है। उत्तर भारत में इस योजना को पूरा करने के लिए तीन चरण है और दक्षिण भारत में साल के अंत तक पूरी की जानी है। केंद्र सरकार ने इस योजना का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति यानी की अंतिम पायदान पर बैठी महिलाओं को भी लाभ देने की घोषणा की है।

प्रधानमंत्री धन लक्ष्मी लोन योजना 2019 , 5 लाख का लोन 0 प्रतिशत ब्याज

धन लक्ष्मी योजना के लिए जो आवश्यक कागजात

महिलाओं का स्वयं का खाता होना चाहिए यानी कि जो महिला इस योजना का लाभ लेना चाहती है उसका स्वयं का खाता होना चाहिए।

Note : महिला का खाता किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय कृत बैंक में ही होना चाहिए ना कि किसी भी प्राइवेट बैंक।

- आपका आधार कार्ड होना जरूरी है आजकल आधार कार्ड तो 99 वर्ष लोगों के पास है जिनके पास भी नहीं है वह अपना आधार कार्ड बनवा लें तभी इस योजना का लाभ ले पाएंगे : आपका आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है और वह भी मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए तो आप भी योजना का लाभ मैं अपना मोबाइल नंबर जो है आधार कार्ड से लिंक जरूर करवा लें तभी आप इसका लाभ ले पाएंगे
- आपके पास पैन कार्ड हो या फिर वोटर कार्ड न दोनों में से एक होना आवश्यक है।

धनलक्ष्मी योजना के पोर्टल पर आप का पंजीयन होना जरूरी है।

अन्य शर्त

- आयु 18 से 55 होनी चाहिए
- यदि महिला के नाम पर कोई भी प्रॉपर्टी है तो आप इस योजना का धन लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे
- प्रधानमंत्री धन लक्ष्मी योजना, ऑनलाइन आवेदन (पंजीयन) एप्लीकेशन फॉर्म

धन लक्ष्मी योजना के अंतर्गत आवेदकों को क्या लाभ मिलेगा?

दोस्तों जैसे कि आपको पहले बताया इसी योजना का उद्देश्य देश की सभी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना हैं। सरकार चाहती है कि महिलाएं आगे बढ़ कर अपना बिजनेस शुरू करेंद्य इसके लिए सरकार इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए ₹500000 तक का लोन देगी। इस राशि में 0 : ब्याज दर रहेगी और चुकाने की समय सीमा 30 साल होगी।

यानी सरकार द्वारा लिए गए ₹500000 के ऋण को आप अगले 30 साल में चुका सकते हैं वह भी बिना एक पैसा भी फालतू देकर। इस योजना में आवेदन जिला स्तरीय समुदायिक केंद्र में जाकर आप कर सकते हैं।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

111 साल पहले धरती पर हुआ था महाविस्फोट

द रीव टाइम्स ब्यूरो

ये वाकया 111 साल पुराना है। रूस के साइबेरिया इलाके में एक बहुत ही भयानक विस्फोट हुआ था। ये धमाका पोडकामेन्नया तुंगुस्का नदी के पास हुआ था। इस धमाके से आग का जो गोला उठा उसके बारे में कहा जाता है कि ये 50 से 100 मीटर चौड़ा था। इसने इलाके के टैगा जंगलों के करीब दो हजार वर्ग मीटर इलाके को पल भर में राख कर दिया था। धमाके की वजह से आठ करोड़ पेड़ जल गए थे। साइबेरिया में 111 साल पहले हुए इस धमाके में इतनी ताकत थी कि धरती कांप उठी थी। जहां धमाका हुआ वहां से करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित कस्बे के घरों की खिड़कियां टूट गई थीं। वहां के लोगों तक को इस धमाके से निकली गर्मी महसूस हुई थी। कुछ लोग तो उछलकर दूर जा गिरे थे।

किस्मत से जिस इलाके में ये भयंकर धमाका हुआ, वहां पर आबादी बेहद कम या न के बराबर थी। आधिकारिक रूप से इस धमाके में सिर्फ एक गड़ेरिए के मारे जाने की तस्दीक की गई थी। वो धमाके की वजह से एक पेड़ से जा टकराया था और उसी में फंसकर रह गया था। इस धमाके की वजह से सैकड़ों रेंडियर कंकाल में तब्दील हो गए थे। उस धमाके के गवाह रहे एक शख्स ने बताया था कि जंगल के ऊपर का आसमान मानो दो हिस्सों में बंट गया था। ऐसा लग रहा था कि आकाश में आग लग गई है। ऐसा लगा कि जमीन से कोई चीज टकराई है। इसके बाद पत्थरों की बारिश और गोलियां चलने की आवाजें आई थीं।

दुनिया इसे तुंगुस्का विस्फोट के नाम से जानती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस धमाके से इतनी ऊर्जा पैदा हुई थी कि ये हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 185 गुना ज्यादा थी। कई वैज्ञानिक तो ये मानते हैं कि धमाका इससे भी ज्यादा ताकतवर था। इस धमाके से जमीन के अंदर जो हलचल मची थी, उसे हजारों किलोमीटर दूर ब्रिटेन तक में दर्ज किया गया था। ज 111 साल बाद भी इस धमाके के राज से पूरी तरह से पर्दा नहीं हट सका है। आज भी वैज्ञानिक अपने-अपने हिसाब से इस धमाके की वजह पर अटकलें ही लगा रहे हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि उस दिन तुंगुस्का में कोई उल्कापिंड या धूमकेतु धरती से टकराया था। ये धमाका उसी का नतीजा था।

दुनिया की सबसे गर्म जगह, जहां छिपे हैं कई गहरे राज

द रीव टाइम्स ब्यूरो

दुनिया की सबसे गर्म जगह का नाम है, डानाकिल डिप्रेशन। ये जगह उत्तरी अफ्रीकी देश इथियोपिया में है। इसका एक हिस्सा पड़ोसी देश इरीट्रिया से भी मिलता है। डानाकिल डिप्रेशन दुनिया की सबसे गर्म, सबसे सूखी, और धरती पर सबसे नीची जगह है। ये इथियोपिया के अफार इलाके में पड़ती है। यहां का मौसम बेहद जालिम है। फिर भी आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बेहद खराब माहौल होने के बावजूद यहां बहुत से लोग रहते हैं।

इथियोपिया के अफार समुदाय के लोग बेरहम मौसम वाले ठिकाने को अपना घर मानते हैं। डानाकिल डिप्रेशन को दुनिया की सबसे गर्म जगह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां साल भर औसत तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। धरती पर जो और गर्म जगहें हैं, वहां औसतन इतना तापमान नहीं रहता। कभी-कभी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। मगर डानाकिल डिप्रेशन में औसत तापमान ही 35 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रहता है। इसके सिवा यहां बारिश भी बेहद कम होती है। साल भर में केवल 100 से 200 मिलीमीटर बारिश यहां होती है। इसके अलावा एक खास बात और भी है कि डानाकिल डिप्रेशन समुद्र तल से करीब सवा सौ मीटर नीचे है।

यहां के ये हालात इसे रहने के लिए धरती पर सबसे बदतर ठिकाना बना देते हैं।डानाकिल डिप्रेशन में सिर्फ धरती के ऊपर का माहौल नहीं खराब है। यहां धरती के अंदर भी हलचल मची हुई है। ये वो जगह है जहां पर तीन टेक्टॉनिक प्लेट्स मिलती हैं। ये वो प्लेट हैं, जिन पर हमारे महाद्वीप और महासागर हैं।

डानाकिल डिप्रेशन में जो तीन टेक्टॉनिक प्लेटें हैं वो सालाना एक से दो सेंटीमीटर की दर से एक दूसरे से दूर हो रही हैं। धरती के भीतर मची-इस उथल-पुथल का नतीजा ये कि धरती के भीतर की आग अक्सर यहां बाहर निकल आती है। पिघलता लावा यहां बड़े इलाके में फैला हुआ है। पूरे इलाके में कई ज्वालामुखी हैं जो आग और राख उगलते रहते हैं।

मंगल ग्रह पर आज तक क्यों नहीं पहुंच पाया कोई इंसान? क्या है इसके पीछे का रहस्य

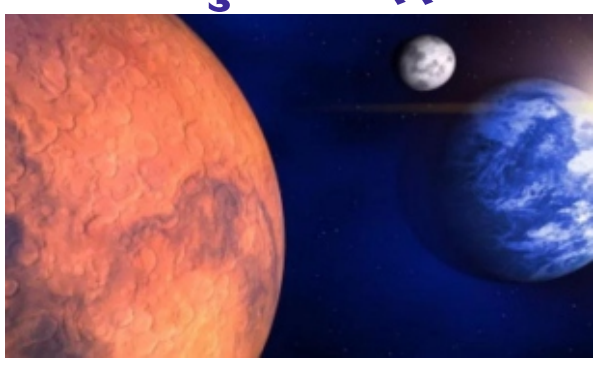

द रीव टाइम्स ब्यूरो

यूं तो विज्ञान के क्षेत्र में हमने काफी तरक्की कर ली है, लेकिन आज भी कई ऐसी चीजें हैं जो इंसानों के लिए हमेशा से एक चुनौती बनी हुई हैं। ऐसी ही एक चुनौती है मंगल ग्रह पर इंसानों का आज तक न पहुंच पाना। इसके पीछे कई वजहें हैं, जिनके बारे में अंतरिक्ष एजेंसी नासा भी जिक्र कर चुकी है। नासा ने पिछले साल मंगल ग्रह पर इंसान के पहुंचने के रास्ते में आने वाली मुश्किलों की एक सूची बनाई थी। नासा के मुताबिक ये मुश्किलें हैं- मंगल ग्रह पर विकिरण, अलगाव, धरती से मंगल ग्रह की अधिक दूरी, गुरुत्वाकर्षण और वहां का बंद वातावरण। मंगल पर जाने की सबसे पहली चुनौती विकिरण को लेकर है, जिसे इंसानी आंखों से देखा नहीं जा सकता। चूंकि मंगल का अपना कोई चुम्बकीय क्षेत्र नहीं है, ऐसे में वहां का खतरनाक ब्रह्मांडीय विकिरण (रेडिएशन) इंसानों की आंखों में मोतियाबिंद और यहां तक कि कैंसर का कारण भी बन सकता है। धरती से मंगल ग्रह की दूरी करीब 14 करोड़ मील है। चांद तक पहुंचने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को मुश्किल से तीन दिन की यात्रा करनी पड़ी थी, लेकिन मंगल तक पहुंचने के लिए इंसान को कई महीनों तक सफर करना होगा। यह अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। धरती से मंगल ग्रह की दूरी करीब 14 करोड़ मील है। चांद तक पहुंचने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को मुश्किल से तीन दिन की यात्रा करनी पड़ी थी, लेकिन मंगल तक पहुंचने के लिए इंसान को कई महीनों तक सफर करना होगा। मंगल ग्रह पर इंसानों को अलग तरह के गुरुत्वाकर्षण का भी सामना करना पड़ेगा। धरती पर जिस इंसान का वजन 100 पाउंड यानी 45.3 किलो होगा, मंगल ग्रह पर उसी का वजन 38 पाउंड यानी 17.2 किलो हो जाएगा। मंगल का तापमान और दबाव भी इंसानों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। पृथ्वी के मुकाबले ठंड, धूल भरी आंधी और बवंडर, मंगल ग्रह पर कहीं ज्यादा हैं। गर्मियों में मंगल ग्रह का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन सर्दियों में यही तापमान - 140 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। चूंकि इंसानों के जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी है ऑक्सीजन, लेकिन मंगल ग्रह पर इसकी भारी कमी है। मंगल के वातारण में 96 फीसदी कार्बन डाई अहक्साइड है, 1.93 फीसदी आर्गन, 0.14 फीसदी ऑक्सीजन और 2 फीसदी नाइट्रोजन है। साथ ही यहां के वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड के निशान भी पाए गए हैं। ऐसे में वहां पर कोई भी इंसान महज कुछ घंटों तक ही जिंदा रह पाएगा।

जर्मनी का वो वीरान गांव, जहां बनी थी दुनिया की पहली मिसाइल फैक्ट्री

द रीव टाइम्स ब्यूरो

आज दुनिया मिसाइलों और रॉकेटों के जरिए जंग लड़ती है। हर देश तरह-तरह की मिसाइलें अपने हथियारों के जखीरे में रखता है ताकि दुश्मन को दूर से ही नेस्तनाबूद किया जा सके। भारत के पास भी, पास और दूर तक मार करने वाली कई तरह की मिसाइलें हैं। जर्मनी वो पहला देश था जिसने युद्ध में मिसाइलों का इस्तेमाल करने की सोची थी। ये बात और है कि आज रूस और अमेरिका इस रेस में बहुत आगे निकल गए हैं। मगर मिसाइलों की इस होड़ की शुरुआत जर्मनी ने ही की थी। बाद में वहीं के वैज्ञानिकों ने रूस और अमेरिका में मिसाइलों के निर्माण में अहम रोल निभाया। ये बात और है कि जर्मनी खुद कभी मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं कर सका। ये बात दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की है। जर्मनी का एक गांव मिसाइल फैक्ट्री के तौर पर विकसित किया गया था। इस गांव का नाम है, पेनमुंडे। ये गांव जर्मनी के यूसडम द्वीप में पेन नदी के मुहाने पर स्थित है। पेन नदी, यहां पर आकर बाल्टिक सागर में गिरती है। 1936 से 1945 के बीच इस द्वीप के पेनमुंडे गांव को नाजी सरकार ने अपने बेहद खुफिया मिशन का अड्डा बनाया था। 1935 में जर्मन इंजीनियर वर्नहर वॉन ब्रॉन ने पेनमुंडे गांव को अपने मिसाइल के कारखाने के लिए चुना था। इसके आसपास का चार सौ किलोमीटर का इलाका सुनसान था। ब्रॉन ने सोचा कि ये जगह उनके रॉकेट के परीक्षण के लिए बिल्कुल सही रहेगी। सरकार से इजाजत मिलने के बाद यहां मिसाइल का कारखाना और टेस्टिंग रेंज स्थापित करने का काम बड़ी तेजी से हुआ। करीब 12 हजार लोगों ने यहां दिन-रात काम करके दुनिया की पहली क्रूज मिसाइल बनाने की फैक्ट्री और टेस्टिंग रेंज को तैयार किया। इस गांव में रहने वाले ज्यादातर लोग किसान या चरवाहे हैं। ये अपने जानवरों को इन्हीं पहाड़ों पर चरने के लिए छोड़ देते हैं। जहां-जहां खुद वो जाते हैं, वहां-वहां अपने साथ अपने जानवर भी ले जाते हैं। ये लोग इन पहाड़ों में जड़ी-बूटियां भी जमा करते हैं। इनका दावा है कि इन जड़ी बूटियों का सेवन करने से इनकी सेहत ठीक रहती है। इन्हें लंबी जिंदगी मिलती है। हालांकि आज लोग इन गुफाओं में बसने से कतराते हैं। गुफाओं में रहने के बजाए वो आस-पास के शहरों में बसने चले जाते हैं।

इतिहास का सबसे अमीर आदमी, जिसे भूल गई दुनिया, विश्व के चार बड़े रईसों से भी ज्यादा थी संपत्ति

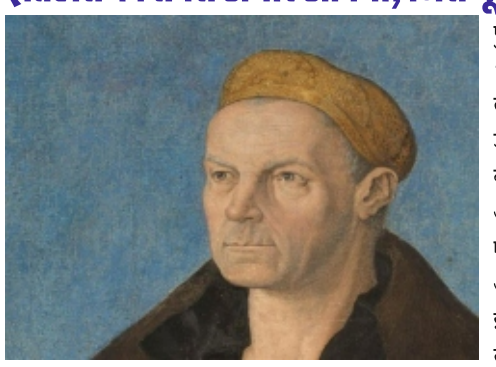

द रीव टाइम्स ब्यूरो

जैकब फग्गर अगर आज जिंदा होते, तब भी बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, वैरन बफेट और कारलोस स्लिम यानी दुनिया के चार बड़े रईसों से ज्यादा दौलतमंद होते। जैकब के जीवनीकार और वॉल स्ट्रीट जनरल के पूर्व संपादक ग्रेग स्टाइनमेट्ज के मुताबिक, इस जर्मन बैंकर और व्यापारी को द रिच वन पुकारा जाता था। ये दौर था साल 1459 से 1525 का। जैकब ने उस दौर में आज के 400 बिलियन यूएस डॉलर यानी करीब 25 खरब रुपये कमाए। ग्रेग ने 2015 में जैकब को अपनी किताब द रिचेस्ट मैन हू एवर लिव्ड में इतिहास का सबसे अमीर आदमी बताया। जैकब को इतिहास के सबसे अमीर आदमी बताने के ग्रेग के दावे पर सवाल किए जा सकते हैं। बीबीसी वर्ल्ड से बात करते हुए ग्रेग ने कहा, जैकब निसंदेह दुनिया में अब तक के सबसे ताकतवर बैंकर थे।

वह पुर्नजागरण काल में रह रहे थे। तब दुनिया को दो ताकतें रोमन साम्राज्य और पोप चलाते थे। फग्गर इन दोनों को पैसा मुहैया कराते थे। इतिहास में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ, जिसके पास इतनी राजनीतिक ताकतें हों। फग्गर ने ये तय किया कि स्पेन के राजा चार्ल्स - 1 को रोम का राजा होना चाहिए और चार्ल्स - 5 के रूप में उन्हें सफलता भी मिली।

चार्ल्स - 5 ने नई दुनिया को उपनेविश बनाया। अगर वो सत्ता में न आए होते तो दुनिया वैसी न होती, जैसी आज है। उस दौर के रईसों मेडिकी, सीजर और लुसरेजिया बोर्गिया बंधु के बारे में काफी लोग जानते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि फग्गर के बारे में कम लोग क्यों जानते हैं। ग्रेग इसकी वजह बताते हैं, ऐसा इसलिए था क्योंकि फग्गर जर्मन थे और वो अंग्रेजी बोलने वाली दुनिया के बीच पहचाने नहीं गए। मैं बर्लिन में वॉल स्ट्रीट जनरल का ब्यूरो प्रमुख था। मैंने कई बार फग्गर का नाम सुना था, लेकिन मुझे अंग्रेजी में उनके बारे में कुछ पढ़ने को नहीं मिला।

द रीव टाइम्स
आपकी आवाज़ ही है हमारी आवाज़

द रीव टाइम्स

संस्थापक: डॉ एल.सी. शर्मा
प्रकाशक: आईआईआरडी काम्पलेक्स, बाईपास रोड शनान, सन्जौली शिमला-6 हि.प्र.
द रीव टाइम्स के लिए मुद्रक प्रदीप कुमार जरेट द्वारा एसोसिएट प्रैस, सायबू निवास समीप सेक्टर-2, बस स्टैंड, मिडल मार्केट न्यू शिमला-9, हि.प्र. से प्रकाशित एवं मुद्रित
संपादक: हेम राज चौहान

फोन न. : 0177 2640761
आर.एन.आई. रिफ्रेंस नं. 1328500
टाइटल कोड : HPBIL00313
पोस्टल रजिस्ट्रेशन नं. HP/129/SML/2019-2021

E-mail : hem.raj@iirdshimla.org
Website : www.therievtimes.com

आवश्यक सूचना

हिमाचल का सबसे तेज़ गति से उभरता पाक्षिक समाचार पत्र द रीव टाइम्स में मार्केटिंग हेतु युवाओं (लड़के / लड़कियों) की आवश्यकता है। एक स्थाई रोजगार एवं बेहतर वेतनमान के साथ आकर्षक कमीशन का प्रावधान रहेगा। इच्छुक शीघ्र ही संपर्क करें।

दूरभाष : 9418404334
Chauhan.hemraj09@gmail.com, hem.raj@iirdshimla.org

द रीव टाइम्स आपकी आवाज़ ही है हमारी आवाज़

राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, जिलों, गांव, स्वास्थ्य, कानून, समसामयिक विषयों पर संपादकीय एवं अभिव्यक्ति, सामान्य ज्ञान, प्रतियोगी परीक्षाओं का ज्ञान दर्पण, सरकारी जनपयोगी योजनाओं का संपूर्ण दस्तावेज़..... द रीव टाइम्स उत्कृष्ठ गुणवत्ता, संपूर्ण रंगीन पृष्ठ, शानदार विषयवस्तु के साथ प्रदेश का पाक्षिक समाचार पत्र द रीव टाइम्स अब आपको मिलेगा घर – द्वार पर ही। समाचार पत्र को लगाने के लिए आप हमारी वेबसाइट ीजजचरुध्ध्नइण्उपेपवदतपमअण्पद पर लॉगइन कर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा मिशन रीव के कार्यकर्ता / अधिकारी से संपर्क कर भी आप कैशलैस भुगतान कर इसके वार्षिक सदस्य बन सकते हैं। अब आपके लिए आकर्षक ऑफर.....

अब वार्षिक सदस्य बनें केवल 500 रूपये, छः माह के लिए 250 रूपये में और घर बैठे पांऐ द रीव टाइम्स..... क्योंकि आपकी आवाज़ ही है हमारी आवाज़

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र